चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 10 मई-16 मई 2010

दो डीजीपी की ज़ंग में शहीद हो रहे जवान

पेज 3

बांग्लादेशी दुल्हनों का बड़ा बाज़ार

पेज 4

साइबर अपराध और क़ानून

पेज 7

भक्ति की शक्ति

पेज 12

राजनीति की काली दुनिया

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

मामला महंगाई की मार झेल रही जनता की समस्याओं से शुरू हुआ. विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया. लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया गया. जनता को लगा कि विपक्ष उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है, लेकिन राजनीति के घिनौने खेल ने जनता का मज़ाक उड़ाकर रख दिया. कटौती प्रस्ताव के इर्द-गिर्द राजनीति का जो घिनौना खेल खेला गया, उससे लोकसभा ने जनता को यही संदेश दिया कि महंगाई पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतें जायज़ हैं और जो भी समस्याएं हैं, उससे जनता को ख़ुद निपटना होगा. इससे महत्वपूर्ण संदेश राजनीतिक दलों ने दिया कि वे सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं. अभी तो विदेश मंत्रालय की अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़ी गई है. देश चलाने वालों का यही हाल रहा तो हर गली-मुहल्ले में देशद्रोही नज़र आएंगे. लेकिन, अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को इस ख़तरे का आभास तक नहीं है.

नेताओं की ग़लतफहमियों ने देश के राजनीतिक पतन का एक नया अध्याय लिख दिया. भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा घिनौना खेल खेला, जिससे जनता का सिर शर्म से झुक गया. राजनीति का यह शर्मनाक खेल किसी ग़लती की वजह से नहीं, बल्कि नेताओं की ग़लतफहमी की वजह से खेला गया. नेताओं को यह भ्रम हो गया है कि देश की जनता मूर्ख है. वे कोई भी घिनौना दांव खेलकर, जनता को झांसा देकर निकल जाएंगे. सबसे घिनौना खेल झारखंड में खेला गया. भारतीय जनता पार्टी ने यह फिर से साबित कर दिया कि वह कितनी खोखली है. महंगाई के मुद्दे पर शिबू सोरेन ने जब कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला और भाजपा ने समर्थन वापसी की घोषणा की तो लोगों ने इस फ़ैसले को काफी सराहा. उन्हें लगा कि कम से कम देश में एक तो पार्टी ऐसी है, जो जनता के सवालों पर सत्ता को ठोकर मारने की ताक़त रखती है. लेकिन अचानक भाजपा ने यू टर्न ले लिया. शिबू को सबक सिखाने की बजाय वह ख़ुद सरकार बनाने मैदान में कूद गई. भाजपा के इस यू टर्न के बाद तो यही कहा जा सकता है कि महंगाई के सवाल पर कटौती प्रस्ताव और भारत बंद जनता के साथ किया गया एक और मज़ाक बनकर रह गया.

लोकसभा में देश की जनता ने राजनीति का घिनौना खेल देखा. लोगों ने नेताओं की मूर्खता देखी, षड्यंत्र देखा, बिकने वाले नकली चेहरे देखे और सीबीआई का डंडा दिखाकर नेताओं का समर्थन लेने वाली सरकार को भी देखा. महंगाई और जनता से जुड़े सवालों को ढाल बनाकर हमारे नेता किस तरह षड्यंत्र रचते हैं और किस तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, यह बात सबके सामने आ गई. जिस पार्टी के समर्थन से आप राज्य के मुखिया बने हैं, उसी पार्टी के ख़िलाफ़ लोकसभा में आप वोट डाल दें! राजनीति का यह पाठ शिबू सोरेन जैसे नेता ही पढ़ा सकते हैं. यह घटना भारतीय राजनीति में कई सालों तक याद की जाएगी. पकड़े जाने पर शिबू सोरेन को जब मीडिया ने घेरा तो उन्होंने मूर्खतापूर्ण जवाब दिया. उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि ग़लती से ग़लत बटन दब गया. वह तो लोकसभा की वोटिंग मशीन ख़राब हो गई, वरना आज तक शिबू यही बात कहते रहते कि ग़लती हो गई. मशीन ख़राब होने के बाद काग़ज़ के पुर्जे पर वोटिंग हुई थी, वहां भी शिबू सोरेन ने सरकार का साथ दिया था. वैसे भी लोकसभा में वोटिंग के दौरान चमत्कार करना शिबू सोरेन की पुरानी आदत है. इस बार अंतर यह है कि ग़लती का बहाना बनाकर शिबू के बेटे हेमंत सोरेन ने भाजपा से माफी मांगी और राजनीति का काला अध्याय लिखा. महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर सत्ता पाने और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लालच में भाजपा भी अच्छे-बुरे का अंतर भूल गई. जिसके विश्वासघात से नाराज़ होकर उसने समर्थन वापसी की घोषणा की थी, अगले ही दिन वह उसके साथ खड़ी हो गई. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया.

27 अप्रैल को महंगाई के ख़िलाफ़ कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे. देशव्यापी बंद सफल रहा. सुबह से ही जनता टीवी चैनलों पर देश भर में व्यापक बंद का नज़ारा देख रही थी. तस्वीरें हर शहर से आ रही थीं. कार्यकर्ता गिरफ़्तार हो रहे थे. विपक्षी पार्टियां पहली बार इस तरह महंगाई के ख़िलाफ़ लामबंद नज़र आईं. देश की जनता ने इसे काफी सराहा. संसद में जब हंगामा शुरू हुआ तो किसी को यह गुमान तक नहीं था कि उनके बीच भी जयचंद मौजूद हैं. वैसे केंद्र की सरकार से जनता को ज़्यादा उम्मीद नहीं है. फिर भी शाम ढलते ही राजनीति का काला साया ऐसा उमड़ा कि सरकार को चलाने वाले कर्ताधर्ताओं का असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो गया. संसद में भाजपा अकेली नज़र आई. टीवी पर संसद में बैठे दासगुप्ता जी उदास और हताश दिखे.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने काफी दिनों से गांधी परिवार को निशाने पर ले रखा था. वह कभी राहुल तो कभी सोनिया गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान समस्या खड़ी करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी थीं. मायावती ने कट मोशन आने पर ऐसा संदेश दिया कि वह कांग्रेस के ख़िलाफ़ संसद में आवाज़ उठाएंगी. महिला आरक्षण बिल पर कड़े तेवर दिखाने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कट मोशन से पहले ऐसे बयान दे रहे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

रोचक तथ्य यह है कि यूपीए के पिछले कार्यकाल में जब सिब्बल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे तो दीक्षित उनके निजी सचिव हुआ करते थे और सिब्बल के हृदय परिवर्तन का संभवत: यही राज है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कपिल सिब्बल का बदला मिजाज

ऐसा लगता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों को नियुक्त न करने के अपने पुराने फैसले को तिलांजलि दे दी है. पिछले साल तक सिब्बल का स्पष्ट रवैया था कि वह शिक्षा विभाग में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों की अपेक्षा शिक्षाविदों की नियुक्ति के पक्ष में हैं, लेकिन अब वह अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं. 1986 बैच के डिफेंस एकाउंट्स सर्विस के अधिकारी अविनाश दीक्षित को केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की उनकी अनुशंसा से तो यही लगता है.

सूत्र बताते हैं कि दीक्षित के नाम की अनुशंसा मंत्रालय की चयन समिति ने की थी, जिसका गठन सिब्बल ने किया था. रोचक तथ्य यह है कि यूपीए के पिछले कार्यकाल में जब सिब्बल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे तो दीक्षित उनके निजी सचिव हुआ करते थे और सिब्बल के हृदय परिवर्तन का संभवत: यही राज है. सिब्बल के इस कदम के खिलाफ विरोध के स्वर अब तक सुनाई नहीं पड़े हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों की नियुक्ति के खिलाफ शिक्षाविद पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं. अब आगे क्या होता है, इसके लिए प्रतीक्षा करें.

नौकरशाहों पर नज़र

चंडीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों के बीच अक्सर विवाद का कारण बनती रही है. अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है. चंडीगढ़ प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर पंजाब ने विरोध की आवाज बुलंद की है. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, चंडीगढ़ का प्रशासन दोनों राज्य मिलकर चलाते हैं, जिसमें साठ प्रतिशत अधिकारियों को पंजाब सरकार नियुक्त करती है, बाकी चालीस प्रतिशत अधिकारियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा होती है. लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का दावा है कि यह आंकड़ा अभी हरियाणा के पक्ष में है. बादल के मुताबिक, वर्तमान में चंडीगढ़ में कुल 13 प्रशासनिक पदों में से केवल तीन पदों पर ही पंजाब कैडर के अधिकारी काबिज हैं.

एक ओर बादल चंडीगढ़ में पंजाब कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चिंतित हैं तो दूसरी ओर नौकरशाह खुद ऐसा नहीं चाहते. इस केंद्र शासित प्रदेश में घोटालों-घपलों की बढ़ती संख्या के चलते आईएएस अधिकारी इससे बचने की कोशिश में रहते हैं. और तो और, वर्तमान में चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले अधिकारी भी अपने मूल कैडर में वापस लौटने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं.

एन संतोष हेगड़े

विवाद थम नहीं रहा

कर्नाटक में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ छापों की कार्रवाई को हरी झंडी देने के एक साल बाद लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े मुश्किल में हैं. राज्य में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड के लिए काम कर चुके आईपीएस अधिकारी एच निंबालकर ने बंगलुरू की एक अदालत में हेगड़े के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया है. निंबालकर का आरोप है कि लोकायुक्त ने उनकी पत्नी की संपत्ति को बेनामी संपत्ति मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी. इसकी एवज में उन्होंने एक रुपये के हर्जाने का दावा किया है.

सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, निंबालकर के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर हेगड़े पूरी तरह आश्वस्त हैं और अदालत में दर्ज अपील से बेफिक्र हैं. इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति से पहले अपनी सारी संपत्ति की जानकारी लोकायुक्त कार्यालय एवं राज्य सरकार को देनी चाहिए. इसके पीछे उनकी स्पष्ट सोच है कि सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम है और इसके लिए ऐसे कदम उठाने ही होंगे. लेकिन हेगड़े की इस सलाह पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है.

dilipcherian@chauthiduniya.com

राजनीति की काली दुनिया

पृष्ठ 1 का शेष

थे, जिन्हें सुनकर तो यही लगा कि ये दोनों सरकार के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन शाम होते-होते उनके रंग बदल गए. उन्होंने कांग्रेस की ज़बरदस्त मदद की और साथ ही लोकसभा से वाकआउट करके अपने चेहरे बचाने की कोशिश भी. अब सवाल यह है कि इन तीनों नेताओं ने ऐसा क्यों किया? टीवी चैनलों पर ख़बर यह आई कि मायावती के साथ कांग्रेस की डील कुछ दिनों पहले ही हो गई थी. इस डील के तहत तय हुआ कि मायावती कट मोशन में कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगी और बदले में कांग्रेस ने यह भरोसा दिया कि उन पर चल रहे आय से ज़्यादा आमदनी के मामले में सीबीआई रियायत बरतेगी. ताज कॉरिडोर वग़ैरह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और राहुल गांधी दलितों को कांग्रेस में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई रैली या प्रयत्न नहीं करेंगे. जनता में यही संदेश गया है कि सीबीआई की वजह से मायावती कांग्रेस के समर्थन में आ खड़ी हुईं. मुलायम सिंह और लालू के बारे में भी जनता में अच्छा संदेश नहीं गया. बेटे अखिलेश को लखनऊ में पुलिस गिरफ़्तार कर रही थी, लेकिन पिता मुलायम सरकार को बचाने के लिए राजनीति के दांव-पेंच में उलझे थे. शाम तक वह भी बेनकाब हो गए. अब जनता कह रही है कि सीबीआई के डंडे से कांग्रेस ने मुलायम सिंह को भी डरा दिया. लालू प्रसाद यादव के बारे में तो देश की जनता को समझ में ही नहीं आया कि कल तक कांग्रेस को कोसने वाले लालू अचानक सोनिया गांधी का गुणगान क्यों करने लग गए. क्या वह चारा घोटाला और इससे जुड़े कई अन्य मामलों में सीबीआई की लटकी तलवार से डर गए. लालू प्रसाद ने सांप्रदायिकता की दुहाई देकर लोकसभा में यह बयान दिया कि वह भाजपा के साथ वोट नहीं कर सकते. यह दलील तो सही है, लेकिन यह सिर्फ़ दलील है. अगर बिहार में 15 साल के अपने शासनकाल में लालू यादव ने मुसलमानों के विकास के लिए एक भी क्रांतिकारी कदम उठाया होता तो शायद कल महंगाई के ख़िलाफ़ अगर भाजपा के साथ भी उन्हें वोट करना पड़ता तो देश के मुसलमान उन्हें माफ कर देते. महंगाई की मार ऐसी होती है, जिसका कोई धर्म नहीं होता, हिंदू हो या मुसलमान, यह दोनों पर बराबर पड़ती है.

आईपीएल घोटाले पर मचे बवाल के बाद अब भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब देश की जनता ढूंढ रही है. करोड़ों रुपये के आईपीएल घोटाले का क्या हुआ. इतना हंगामा होने के बावजूद अचानक सब शांत क्यों हो गया. आईपीएल घोटाले में मंत्रियों के नाम सामने आए, अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ा, मुनाफा कमाने के लिए हवाला से भी ख़तरनाक तरीक़ों का पर्दाफाश हुआ, सट्टेबाज़ी की सच्चाई का पता चला, नेताओं, खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं फ़िल्मी हस्तियों पर आरोप लगे. आईपीएल घोटाले में जो कुछ हुआ, वह काफी ख़तरनाक है और चिंताजनक भी. फिर भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. क्या सरकार और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच कोई डील हो गई है कि अब इस मामले को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, नहीं तो सब लोगों की पोल खुल जाएगी. अगर ऐसा नहीं है तो आईपीएल के मुद्दे पर आडवाणी ने यह क्यों कहा कि बस अब बहुत ज़्यादा आईपीएल हो गया. बीसीसीआई के अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन मंत्रियों और नेताओं को क्यों छोड़ दिया गया, जिनके नाम इस घोटाले में शामिल हैं. शशि थरूर और ललित मोदी के बाद किसी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई. आईपीएल का अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ क्या रिश्ता है. शाहरुख़ की टीम में किसने कितने पैसे लगाए. जिन लोगों ने गांधी परिवार से निकट संबंधों का फ़ायदा उठाकर क्रिकेट को बदनाम करने का काम किया, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया. देश की जनता ऐसे कई सवालों के जवाब जानना चाहती है. अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो जनता यही समझेगी कि आईपीएल पर लगे आरोप सही थे और देश के दिग्गजों ने मिल-जुलकर लूटा और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अगर इस मसले पर जवाब न मिले और विपक्ष बिक जाए या फिर बेवकूफी में चुप बैठ जाए तो देश की जनता के पास इन सवालों के जवाब जानने के लिए कौन सा रास्ता बचेगा.

27 अप्रैल, 2010 का दिन इतिहास बन चुका है. यह दिन कई बातों के लिए याद किया जाएगा. नेता किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं. देश की जनता ने राजनीति का एक नया पाठ सीखा कि जनता और सांसदों के विश्वास के बग़ैर सीबीआई के सहारे कैसे सरकार चलाई जा सकती है. कैसे एक परमाणु शक्ति से लैस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकसभा में वोटिंग मशीन तक ठीक नहीं है. साथ ही यह साफ हो गया कि लोहिया, जयप्रकाश और अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव एवं मायावती महंगाई के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं. यह दिन इतिहास में इसलिए भी याद किया जाएगा कि आज़ाद भारत में पहली बार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली विदेश मंत्रालय की अधिकारी को गिरफ़्तार किया जाता है और लोकसभा में इसकी चर्चा तक नहीं होती. राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि जिस तरह देश में सरकारी तंत्र चल रहा है, जिस तरह आदर्श और मर्यादाओं को ताख पर रख दिया गया है, उसी का यह नतीजा है कि जिन पर देश की ज़िम्मेदारी है, वही दुश्मनों के लिए जासूसी कर रहे हैं. अभी एक अधिकारी का मामला सामने आया है, कल अगर देश की आम जनता देश की दुश्मन बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा.

manish@chauthiduniya.com

संसद में सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते नेता.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 9
दिल्ली, 10 मई-16 मई 2010
संपादक
संतोष भारतीय
मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित
संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301
फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120-4783950
पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

66 हज़ार किलोमीटर लंबी नहर का नेटवर्क खड़ा करने वाली यह योजना पूरी होने से 18 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो सकती है, जिससे लगभग तीन हज़ार पांच सौ गांवों को फ़ायदा पहुंच सकता है.

दो डीजीपी की जंग में शहीद हो रहे जवान

रूबी अरुण

नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की ख़ातिर छत्तीसगढ़ में तैनात किए गए दो पुलिस महानिदेशक नक्सलियों को मटियामेट करने के बजाय आपस में ही धींगामुश्ती कर रहे हैं. नक्सलियों का सफाया करने की जगह उनमें इस बात की होड़ मची है कि नक्सलियों के ख़िलाफ़ चल रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट की डोर किसके हाथ रहे और इसका सेहरा किसके सिर बंधे. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन को यह कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके महकमे में कोई और भी दख़ल दे. उनका महकमा बस उनके इशारों पर नाचे. वहीं नक्सलियों के वजूद को ख़त्म करने की ख़ातिर तैनात किए गए सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक विजय रमण चाहते हैं कि जब कभी सीआरपीएफ का विशेष अभियान हो, तब वहां के पुलिस अधिकारी उनके निर्देशों का पालन करें. इन दोनों के बीच चल रही अधिकारों की इस जंग का सीधा फ़ायदा नक्सली उठा रहे हैं. यहां वर्दी ही वर्दी की मुख़ालफ़त कर रही है. ज़ाहिर तौर पर भले ही सरकार इस बात की मुनादी करे कि वह इस समस्या से पार पाने के लिए पूरी तरह चौकस और चुस्त है. संसद में गृहमंत्री पी चिदंबरम भाव भरे शब्दों में दिलासा और सफाई दे दें. जवानों पर रणनीतिक चूक करने का इल्ज़ाम मढ़ दें, पर सच तो यही है कि इन दोनों अधिकारियों में चल रही नूरा–कुश्ती का ही खामियाज़ा 76 जवानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. सुबह पांच बजे से चिंतलनार के जंगल में जवान नक्सलियों से जंग लड़ रहे थे और बार–बार यह सूचना पुलिस मुख्यालय में भिजवा रहे थे कि अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जाए, लेकिन पुलिस बल दोपहर के बारह बजे पहुंचा. इतना ही नहीं, चिंतलनार पुलिस चेकपोस्ट पर नियम के मुताबिक़ पुलिस के 20 जवानों की ड्यूटी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां महज़ 3 पुलिस वाले ही मौजूद थे. हैरानी तो इस बात की भी है कि जब इस बाबत विश्वरंजन से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता ज़ाहिर की. उधर, सीआरपीएफ के विशेष निदेशक विजय रमण इस सिलसिले में कुछ कहना ही नहीं चाहते. पर गृहमंत्री पी चिदंबरम से मिलकर उन्होंने अपनी शिक़ायत दर्ज़ ज़रूर कराई है. विजय रमण ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी की मनमानी के कारण सीआरपीएफ वहां काम नहीं कर पा रही है. एक और हैरान कर देने वाला सच यह भी है कि सीआरपीएफ के पास अपना कोई इंटेलिजेंस सेल है ही नहीं. इतनी बड़ी लड़ाई वह राज्य पुलिस की मुखबिरी की बदौलत लड़ रही है, जिसका उसे अमूमन भारी नुक़सान उठाना पड़ता है. छह अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसकी भनक राज्य पुलिस को पहले से ही थी. विश्वरंजन इस बात को स्वीकारते भी हैं कि राज्य पुलिस के एसबीआई को इस बात की पूरी ख़बर थी कि नक्सली चिंतलनार के जंगल में कुछ उपद्रव करने वाले हैं. इस संबंध में

एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी तैयार की गई थी. फिर भी इतनी बड़ी वारदात हो गई तो ज़ाहिर है कि राज्य पुलिस का सहयोग सीआरपीएफ को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा.

राज्य पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन तो 6 अप्रैल को नक्सलियों द्वारा की गई दिल दहला देने वाली वारदात से ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. वह साफ़ तौर पर कहते हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, वह सीआरपीएफ की ज़िम्मेदारी है, न कि राज्य पुलिस की. विश्वरंजन फ़रमाते हैं कि सीआरपीएफ जिस ऑपरेशन को अंजाम देने निकली थी, दरअसल उसकी योजना छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले ही बना रखी थी. अब सीआरपीएफ ने अचानक अपनी योजना पर अमल कर लिया तो भला वह क्या कर सकते हैं?

यानी कि अगर विश्वरंजन के बयान के मुतल्लिक देखा जाए तो गृहमंत्री पी चिदंबरम भी झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही बयान दिया है कि 6 अप्रैल को सीआरपीएफ ने जो ऑपरेशन किया, उसकी पूरी जानकारी और ज़िम्मेदारी आईजी बस्तर लौंग कुमार, डीआईजी दंतेवाड़ा नलिन प्रभात एवं एसपी दंतेवाड़ा अमरेश मिश्रा की थी. बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन का ऐसा कहना क्या दर्शाता है, यह आप ही तय करें.

उनका तो यह आलम है कि वह नक्सलियों के ख़िलाफ़ चल रहे इस पूरे अभियान का नेता ख़ुद को साबित करने की जुगत में हर जोड़–तोड़ में लगे रहते हैं. लिहाज़ा इस बाबत कुछ भी बयान देने से वह बाज नहीं आते. चौथी दुनिया से हुई बातचीत में वह साफ़ कहते हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट राज्य पुलिस की रणनीति है और इसे जारी रखने के लिए राज्य पुलिस पूरी गंभीरता के साथ लगी है. पर यह कैसी गंभीरता है कि वारदात के चौथे दिन ही रायपुर में राग–रागिनी की महफ़िल सजाई गई, जश्न मनाया गया और इस जलसे में मौज़ूद रहे राज्य पुलिस एवं प्रशासन के कई आला अधिकारी. कल्पवृक्ष रिसोर्ट नामक एक व्यवसायिक संस्था ने 10 अप्रैल को ग़ज़ल गायक जगजीत सिंह का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें न सिर्फ़ समूचा पुलिस महकमा निमंत्रित था, बल्कि मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भी. 76 जवानों की लाशों से पटी रायपुर की ज़मीन पर एक तरफ़ तो पुलिसवाले राज्य की महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी के साथ झूम–झूमकर ग़ज़ल का लुत्फ़ उठाते रहे और दूसरी तरफ़ सीआरपीएफ के जवान नम आंखों और भरे मन के साथ अपने शहीद साथियों की लाशें उनके परिजनों तक पहुंचाने की जद्दोजहद करते रहे. सीआरपीएफ के विशेष निदेशक विजय रमण इस बात से बेहद आहत हैं और इस बात का भी ज़िक्र उन्होंने गृहमंत्री से किया है.

ज़ाहिर है कि दोनों पुलिस महानिदेशकों के बीच जारी इस रस्साकशी के दरम्यान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी इस बात का पूरा इल्म है, पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है. मंशा क्या है, यह तो रमन सिंह ही बता सकते हैं. पर इतना तय है कि दोनों पुलिस महानिदेशकों के बीच की इस खींचतान से कई और हादसे जन्म लेंगे.

ruby@chauthiduniya.com

सरदार सरोवर परियोजना

फिर भी प्यासे हैं खेत और किसान...

शशि शेखर

योजनाओं का सच क्या होता है, इसे समझने के लिए एक घटना का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है. नेहरू जी ने विनोबा भावे को पंचवर्षीय योजना के बारे में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया था. विनोबा जी ने पूछा कि इस योजना से ग़रीबों को रोटी कितने दिनों के अंदर मिलने लगेगी? नेहरू जी ने कहा, बीस साल. तब विनोबा जी ने कहा कि क्या ग़रीब रोटी के लिए 20 साल इंतज़ार करेगा? ज़ाहिर है, ग़रीबों का वह इंतज़ार आज भी ख़त्म नहीं हुआ है. और, हो भी कैसे? इसका एक उदाहरण है सरदार सरोवर परियोजना. इसके बारे में यह प्रचारित किया जाता रहा है कि इस योजना से करोड़ों लोगों को पीने एवं खेतों की सिंचाई के लिए पानी और हज़ारों मेगावाट बिजली मिलेगी. कहा गया कि इस परियोजना के तहत नहरों का एक लंबा–चौड़ा जाल बिछा दिया जाएगा. 66 हज़ार किलोमीटर लंबी नहर का नेटवर्क खड़ा करने वाली यह योजना पूरी होने से 18 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो सकती है, जिससे लगभग तीन हज़ार पांच सौ गांवों को फ़ायदा पहुंच सकता है.

लेकिन, हाल में एक जांच रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है. गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डी जी कजारिया की अध्यक्षता में गठित पीपुल्स इंक्वायरी कमेटी ने आठ महीनों तक जगह–जगह घूमकर, लोगों से बात कर और आंकड़े एकत्र करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके निष्कर्ष वास्तव में इस परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करते हैं. 49 साल और 29 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च करने के बाद भी सरदार सरोवर परियोजना के तहत नहर बनाने की योजना महज़ 29 फ़ीसदी ही पूरी हो पाई है. 2001 से 2010 के बीच नहर बनाने का काम महज़ तीन फ़ीसदी सालाना की दर से ही हो पाया है. दूसरी ओर नहर बनाने की इस योजना को पूरा करने के लिए अभी भी दस हज़ार करोड़ रुपये की और ज़रूरत है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों को इन नहरों से पीने का पानी अब तक नहीं मिल सका है. दरअसल इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए अब तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी है. इस क्षेत्र के लोग अब ख़ुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. और इतना ही नहीं, सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों पर पानी की तथाकथित चोरी का आरोप लगाकर सरकार क़ानूनी कार्रवाई भी कर रही है. पीपुल्स इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जांच के दौरान यह भी पाया कि गुजरात सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला पैसा भी नर्मदा पाइप लाइन योजना में लगा दिया. कमेटी ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया है. कमेटी ने भरूच, जामनगर, राजकोट, पाटन और हलवाड जैसी जगहों पर जब जनसुनवाई आयोजित की तो उसमें हज़ारों किसानों ने भागीदारी की. किसान इस बात से नाराज़ थे कि सरकार ने पानी देने का जो वायदा उनसे किया था, वह अब तक पूरा नहीं हो सका है. ग़ौरतलब है कि पिछले साल गुजरात सरकार ने बिना किसी बहस और विमर्श के उद्योगों को नर्मदा का पांच गुना ज़्यादा पानी आवंटित कर दिया था. कैग ने इस पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार के इस फ़ैसले से गांवों में सूखे की समस्या और बढ़ेगी. कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक़, सरकार के इस क़दम से पानी की औद्योगिक खपत अधिक होगी और घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी की उपलब्धता कम होगी, जिसकी वजह से सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल में भारी कमी हो जाएगी. इस परियोजना के तहत गुजरात के 16 ज़िलों के 8215 गांवों में रहने वाले दो करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है. साथ ही यह योजना थी कि मार्च 2009 तक गुजरात की लगभग साढ़े छह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाना था. लेकिन जनवरी 2010 तक भी यह योजना काग़ज़ से निकल कर खेतों तक नहीं पहुंच सकी है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ कुछ अनुशंसाएं भी राज्य सरकार को भेजी हैं. मुख्य अनुशंसाओं के मुताबिक़, नहर योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अंतिम समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए. साथ ही एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें आम लोगों की भागीदारी हो. कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल को भी सौंपी है. अब देखना यह है कि राज्य एवं केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को कितनी अहमियत देती है और इसकी अनुशंसाओं पर कितना अमल कर पाती है, ताकि किसानों एवं खेतों की प्यास बुझ सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

- 49 साल में 29 हज़ार करोड़ रुपये खर्च, लेकिन नहर निर्माण महज़ 29 फ़ीसदी.
- पिछले दस वर्षों में तीन फ़ीसदी सालाना दर से ही हुआ नहर निर्माण.
- गुजरात के 8215 गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है.
- मार्च 2009 तक साढ़े छह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक पहुंचना था पानी.
- जनवरी 2010 तक पानी खेतों और घरों तक नहीं पहुंच सका.

लड़कियों की तस्करी का सिलसिला 1970 के दशक से शुरू हुआ. 60 के दशक में हिंदी पट्टी खासकर उत्तर प्रदेश के दूल्हे दलालों के ज़रिए ही यहां आते थे, लेकिन 1990 के बाद कुछ दूल्हे सीधे बांग्लादेश तक जाने लगे.

उत्तर भारत
बांग्लादेशी दुल्हनों का बड़ा बाज़ार

बिमल राय

मां तुम मुझे अब कभी नहीं देख सकोगी. मुझे भूल जाओ. सोच लो कि तुम्हारी बेटी नज़मा अब मर गई. मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती और वे यहां आ नहीं सकते. वे तुम्हें कभी नानी नहीं कह पाएंगे. मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, उक्त उद्गार हैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में ब्याही तहमीना नामक दुल्हन के, जो सात साल पहले अपनी मां से मिलने बांग्लादेश लौटी थी. 11 साल बाद उसे यह मौक़ा नसीब हुआ था और अब उसकी मां को अपनी बेटी का कोई सुराग़ नहीं मिल रहा है. यह दुल्हन लौटने के लिए मजबूर रहे, इसलिए उसके चार बच्चों को पति ने अपने पास ही रख लिया था.

बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी का सिलसिला 1970 के दशक से शुरू हुआ. 60 के दशक में हिंदी पट्टी ख़ासकर उत्तर प्रदेश के दूल्हे दलालों के ज़रिए ही यहां आते थे, पर 1990 के बाद कुछ दूल्हे सीधे बांग्लादेश तक जाने लगे. स्थानीय स्तर पर सम्मान बना रहे, इसके लिए राजी हुए अभिभावक दूल्हों की पहचान छुपा कर घर में ही छोटे स्तर पर शादी रचा देते थे और बाद में सीमा पार कराने वाले दलालों के ज़रिए वे भारत लौटते थे. जो लड़कियां अपने मां-बाप को देखने वापस बांग्लादेश जाना चाहती हैं, उन्हें बच्चों को घर पर छोड़कर जाना पड़ता है. ढाका के दृष्टि रिसर्च सेंटर की ओर से कराए गए एक शोधपत्र में दुल्हनों की इस ख़रीद-बिक्री पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है. शोधपत्र अक्टूबर 2003 में एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट (एईडी) को सौंपा गया. अध्ययन में कुल 112 बांग्लादेशी लड़कियों के साक्षात्कार शामिल हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश एवं अन्य उत्तरी राज्यों में बेचा गया. टीम ने उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोंडा और सिद्धार्थनगर आदि ज़िलों का दौरा किया, जहां इस तरह की लड़कियां थीं. टीम ने पाया कि बंगाली लड़की का मतलब ही हुआ ख़रीदी गई औरत. और वे बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगहों से आई हुई होती हैं. अध्ययन में सतखीरा (बांग्लादेश) निवासी तहमीना की रामकहानी विस्तार से लिखी गई है. कैसे 1984 में 14 साल की उम्र में उसकी शादी बरेली के एक अधेड़

104 मामलों का सैंपल सर्वे

एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट (एईडी) ढाका, बांग्लादेश द्धारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77 (बस्ती-41, गोंडा-12, बरेली-09, बदायूं-06, आगरा-04, फर्रुखाबाद-03, कानपुर एवं लखनऊ में एक-एक), राजस्थान में नौ, कश्मीर में चार, पंजाब में तीन, उत्तराखंड में दो (हरिद्धार एवं नैनीताल एक-एक), दिल्ली में एक यानी कुल 96 बांग्लादेशी लड़कियां बेची-ब्याही गईं. यही नहीं, पाकिस्तान के कराची में पांच, रहीमगंज में एक और नेपाल के जंगीपार में 2 लड़कियां बेची-ब्याही गईं.

उम्र के हिंदू से हुई थी, फिर वह कितनी बार बेची गई और कैसे वापस सतखीरा लौटने में कामयाब हुई. 1995 में बांग्लादेश के एक स्वयंसेवी संगठन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट (एसीडी) ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि भारत में ब्याही जाने वाली ज़्यादातर बांग्लादेशी लड़कियां कभी वापस मां-बाप से मिलने नहीं आ पातीं. उसी साल संगठन ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा किया कि नवाबगंज ज़िले के साहिबगंज थाना अंतर्गत विनोदपुर और मनकोशा इलाक़े के 180 परिवारों की लड़कियां शादी के मक़सद से भारत आईं और उनमें से 84 प्रतिशत फिर कभी नहीं लौटीं. जो 16 प्रतिशत लड़कियां लौटने में कामयाब हुईं, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उन्हें पत्नी बनाने के बाद कोठे पर बेच दिया गया. कइयों को आधा दर्जन बार बेचा गया. एसीडी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के दूल्हों की ख़ासियत बताई गई है कि वे कभी तलाक नहीं देते और न बहुविवाह करते हैं. बांग्लादेश के राजशाही निवासिनी एक 60 वर्षीय पूर्व महिला दलाल के मुताबिक़, मुर्शिदाबाद ज़िले के जियागंज, लालगोला एवं भोगवांगुला में बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के शादी करने के लिए आते हैं. वर्ष 1977-78 में कुछ लड़के बांग्लादेश भी पहुंचे. उस समय वहां बहुत ग़रीबी थी, विधवा एवं ग़रीब घरों की औरतें ऐसे दूल्हों से शादी करती थीं. दोनों अध्ययनों से साफ़ था कि ग़रीबी के कारण ही मां-बाप को यह क़दम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है.

भारत में ब्याही जाने वाली औरतों में सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों (97-86.6 प्रतिशत) की थी. इनमें से 15 औरतें (13.4 प्रतिशत) हिंदू थीं. अध्ययन के मुताबिक़, 31.2 प्रतिशत लड़कियां इसलिए भारत में ब्याही गईं, क्योंकि उनके मां-बाप दहेज देने के क़ाबिल नहीं थे, जबकि 23 प्रतिशत लड़कियां दलालों की धोखाधड़ी का शिकार हुईं. केवल 10.7 प्रतिशत अभिभावकों ने पैसे के लिए अपनी बेटियों को ब्याहा. इसके अलावा अन्य कई कारण भी रहे. एडीसी के अध्ययन में पता चला कि 70 प्रतिशत लड़कियां उत्तर प्रदेश में लाई गईं. भारत में इन औरतों को कठिन हालात में काम करना पड़ता है. इनके लिए सबसे पीड़ादायक होता है सांस्कृतिक बदलाव. मछली-भात की जगह दाल-रोटी ले लेती है और अपने पर्व-त्योहार और भाषा छोड़कर शौहर की संस्कृति में पूरी तरह घुलना-मिलना इनकी मजबूरी बन जाती है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड की ओर से कराए गए एक अध्ययन से भी पता चला है कि पश्चिम बंगाल एवं असम से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए लड़कियों की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट में एक ख़ास बात यह दर्ज़ है कि इन्हें संतान (लड़का) पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में कराए गए इस सर्वे के मुताबिक़, पुत्र जनने के बाद इन औरतों को छोड़ दिया जाता है या किसी दूसरे को सौंप दिया जाता है.

बताने की ज़रूरत नहीं कि बांग्लादेशी लड़कियों का भारत में एक बहुत बड़ा बाज़ार है. घुसपैठियों का परिवार जैसे ही भारत में प्रवेश करता है, उसे सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण की तलाश होती है. राजनीतिक संरक्षण की प्रक्रिया सामाजिक स्वीकृति मिलने या समायोजन के बाद होती है. कई मामलों में देखा जाता है कि दलाल शादी के बहाने लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं. बांग्लादेशी लड़कियों की शादी बहुत कठिन होती है, क्योंकि मूल बंगाली परिवार के ज़्यादातर वर घुसपैठिया बहू स्वीकार नहीं करते. इसी सामाजिक अलगाव का फ़ायदा दलाल उठाते हैं और उनसे ख़ुद शादी करके या किसी दूसरे से कराकर उन्हें देश के विभिन्न नगरों के कोठों पर बेच दिया जाता है. लड़कियों की तस्करी की इस समस्या के निदान के लिए सरकारी और ग़ैर सरकारी स्तर पर काफी कोशिशें की जाती हैं, पर मर्ज़ बढ़ता ही जाता है. 2008 के सितंबर महीने के पहले सप्ताह में अदालत ने भी इस नासूर को लेकर चिंता जताई थी. गांवों में तेज़ी से न्याय दिलाने के लिए बने मोबाइल कोर्ट कार्यक्रम के तहत कोलकाता हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर और सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश वाई के संभरवाल ने राज्य के बहरमपुर ज़िले का दौरा किया. न्यायमूर्तिद्वय की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लड़कियों की तस्करी की दर इस ख़तरनाक स्तर पर कैसे पहुंच गई है और पुलिस की भूमिका इतनी लचर क्यों है. उन्होंने इलाक़े की उन 20 लड़कियों से बातचीत की, जिन्हें उनके घरवालों ने ही दलालों को बेच दिया था. बहरमपुर के बैरक स्क्वायर में इन लड़कियों ने बताया कि उनका सौदा कैसे होता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे नरक से भी बदतर हो जाती है. यहीं पर

एक पीड़ित परिवार ने अपनी जो रामकहानी बताई, उससे पुलिस की संवेदनहीनता की एक झलक देखी जा सकती है.

मदपुर की फिरदौसा बीबी ने बताया कि पिछले साल जुलाई में खैरुल बशीर शेख ने मेरी बेटी अरोबा से शादी की और पांच दिन बाद मुंबई चला गया. दो माह पहले वह मुंबई से आया और उसने बताया कि मेरी बेटी वहां दूसरे के साथ भाग गई है. मुझे इस कहानी पर यक़ीन नहीं हुआ और मैं शिक़ायत लेकर बहरमपुर थाने गई. वहां पुलिस ने शिक़ायत दर्ज़ करने से इंकार कर दिया और कारण बताया कि घटना मुंबई में हुई है. कई बार पुलिस विभाग की संवेदनहीनता क्षुब्ध कर देने वाली होती है. थाने का रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए ज़्यादातर मामले दर्ज़ ही नहीं होते. हर परिवार उच्चाधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाता. कुछ थक-हारकर तो कुछ दलालों एवं उनके गुंडों की धमकी से डरकर अपनी बहू-बेटियों की खोजबीन का काम छोड़ देते हैं. चौथी दुनिया ने जब देगंगा थाने के ओसी से पिछले एक साल में इलाक़े से लापता या तस्करी का शिकार हुईं लड़कियों के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्होंने साफ़ कहा कि ऐसा एक भी मामला दर्ज़ नहीं हुआ. इलाक़े के लोगों का आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज़ न कर कुछ ले-देकर मामले सुलटाने की फिराक़ में रहती है. यह एक बड़ी बाधा है. सीमावर्ती ज़िलों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्रोत तस्करी से होने वाली कमाई है. इसमें गांवों की पंचायतों के भ्रष्ट प्रधान भी शामिल हैं और पुलिस भी. घुसपैठियों को भारत में स्थापित करने के लिए उनका आर्थिक शोषण होता है. घुसपैठिए गांवों में सस्ते मज़दूरों की कमी पूरी करते हैं और एक अच्छा-ख़ासा वोटबैंक भी बन जाते हैं. मूल बंगालियों को इनकी दुरावस्था से सहानुभूति नाममात्र की होती है. इन्हीं सब कारणों से यह समस्या कैंसर बनती जा रही है. आरोप है कि उत्तर 24 परगना के बाछारपाड़ा की तपती मंडल और मुकेश (देखें पिछला अंक) के मामले में पुलिस 25 हज़ार रुपये लेकर मामले को सुलटाने में लगी है. बाछारपाड़ा के अब्दुल गनी मंडल ने बताया कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है. हरियाणा के दूल्हे को रोककर अदालत में मुक़दमा लड़ने में न उसकी रुचि है और न घुसपैठिया दुल्हन को हिरासत में रखकर. यही वजह है कि रिपोर्ट लिखे जाने तक कथित अभियुक्त पुलिस हिरासत में था. उन्होंने बताया कि पुलिस को जैसे ही पैसा मिलेगा, सबूतों के अभाव में दूल्हा बरी हो जाएगा और दुल्हन घुसपैठियों से भरी भारतीय जेल में ठूंस दी जाएगी.

इस समस्या पर वर्षों से काम कर रही संस्था सीसीडी के प्रमुख स्वप्न मुखर्जी ने चौथी दुनिया को बताया कि हम हर मामले की रिपोर्ट दर्ज़ कराते हैं, पर प्रशासन से हमें सिर्फ़ आश्वासन मिलता है. तस्करी बदस्तूर जारी रहती है. जो मामले अदालत में जाते हैं, उनके सालों तक चलते रहने की गारंटी हो जाती है. दो दिन बाद दलाल जमानत पा जाते हैं और वे फिर दूसरे इलाक़े में जाकर सक्रिय हो जाते हैं. स्वप्न ने बताया कि कई मामलों में हमारी पहल ने लड़कियों की पीड़ा और बढ़ा दी, जिसे एक तरह से रक्षा में हत्या कहेंगे. उनका मानना है कि समस्या पर काबू पाने के लिए सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार एक बेहतर उपाय हो सकता है. लेकिन बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में, जहां मूल निवासियों से ज़्यादा संख्या घुसपैठिया परिवारों की है, यह उपाय कितना कारगर होगा, समझा जा सकता है. महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के इस माहौल में उनकी तस्करी का यह घिनौना कारोबार सिर्फ़ लफ्फाज़ी या काग़ज़ी कार्यवाही से दूर होने वाला नहीं है.

यौन बस्तियों में खपत

लड़कियों की खपत का एक बड़ा क्षेत्र यौन बस्तियां भी हैं. उन्हें वेश्यालयों में बेचने का काम अक्सर परिचित और रिश्तेदार ही करते हैं. एक अनुमान के मुताबिक़, सीमा पार से आने वाली 60 फ़ीसदी लड़कियां देह व्यापार का पेशा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं. चौथी दुनिया ने कोलकाता की एक बदनाम बस्ती की कुछ ऐसी ही लड़कियों से बातचीत की, जो बांग्लादेश से आई हैं. रेवा मित्र एवं बेबी चौधरी को बांग्लादेश के मागुरहाट से दलाल उनकी उम्र 8-9 साल होते ही ले उड़े. सुनील राय नामक एक भारतीय दलाल ने इन्हें मात्र 5-5 सौ रुपये में ख़रीदा. इन्हें देह बाज़ार के लिए तैयार करने में सालों देर थी, इसलिए इतने कम पैसों में अभिभावकों ने इन्हें बेच दिया. आज इनकी उम्र 40 के आसपास है. इसी तरह रंजिता को बांग्लादेश के जैसोर ज़िले के दवईन गांव से लाया गया. कुछ साल पहले नदिया ज़िले में एक मामला सामने आया था. राणाघाट के राशिद शेख की 19 वर्षीय बेटी सलमा (बदला हुआ नाम) ने अपने पिता से कान की बालियां ख़रीदने के लिए कुछ रुपये मांगे, पर पिता ने देने से इंकार कर दिया. इससे नाराज़ होकर सलमा घर से भागकर 18 किलोमीटर दूर गंगापुर में अपनी चाची अकीला के घर जा पहुंची. अकीला के पति जैनाल शेख एवं बहन अनवरा ख़ातून ने सलमा को कोलकाता के वेश्यालय में बेच दिया. 14 माह तक वह वेश्यालय मालिक के क़ब्ज़े में रही, मगर एक दिन वह अपने एक ग्राहक की मदद से उस नरक से निकल भागी. जब वह घर पहुंची तो पिता राशिद शेख ने अपनी दो बिनब्याही बेटियों की शादी पर संकट की बात कहकर उसे अपने पास रखने से इंकार कर दिया.

सलमा के बयान पर पुलिस ने अकीला, उसके पति जैनाल एवं बहन अनवरा को गिरफ़्तार कर लिया. सलमा अब अपनी बड़ी बहन के घर में शरणार्थी की ज़िंदगी गुज़ार रही है. उत्तर 24 परगना ज़िले के वशीरहाट में एक जीजा ने नाबालिग साली को ही कोठे पर बेच दिया. सिर से मां-बाप का साया उठने के बाद वह 13 वर्षीय किशोरी अपने जीजा के पास रहती थी. जीजा रियाजुल उसे लेकर मुंबई चला गया और वहां उसने उस किशोरी से एक साल तक देह व्यापार कराया. फिर वशीरहाट लौटने के बाद उसे कोलकाता के बदनाम मकान करनानी मेंशन की सावित्री चक्रवर्ती नामक एक महिला को 20 हज़ार रुपये में बेच दिया. सावित्री मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करती थी. क़िस्मत की करवट का नतीजा है कि वह किशोरी अब हावड़ा के लिलुया के महिला सुधारगृह में अपना जीवन व्यतीत कर रही है. किशोरी से पूछताछ के बाद रियाजुल और उसके साथियों गौतम हलदर और अंगूरा बीबी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया गया है. पुलिस ने पांच सितंबर 2009 को तारातला इलाक़े से पुणे ले जाकर बेची गई एक युवती को छुड़ाया. इसी साल फरवरी में जयनगर निवासी मोहम्मद रफीक उर्फ राजा ने 16 वर्षीय मोइतान ख़ातून को नौकरी दिलवाने के बहाने पुणे ले जाकर एक कोठे पर बेच दिया.

चार जुलाई को कोलकाता के बाघाजतिन इलाक़े के पाटुली घोषपाड़ा निवासी अनामिका हलदर ने यादवपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज़ कराई कि उसकी बहन अनुराधा एवं पड़ोसी कल्पना को नौकरी का लालच देकर पुणे में बेच दिया गया. नौ अगस्त को यादवपुर पुलिस ने ही कल्पना सहित नौ युवतियों को गिरफ़्तार किया. नेपाल और बांग्लादेश दोनों से सटा होने के कारण उत्तर बंगाल भी लड़कियों की तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन गया है. पिछले साल अप्रैल महीने में क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा सेल ने दार्जिलिंग की एक लड़की को पुणे के एक वेश्यालय से छुड़ाया. राज्य पुलिस के सूत्रों के मुताबिक़, पिछले साल जनवरी से अप्रैल तक कुल 16 लड़कियों को वेश्यालयों से मुक्त कराया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें क़रीब दो लाख वर्ग किलोमीटर का इलाक़ा रेत के क़ब्ज़े में है.

राजस्थान के रास्ते

महाविनाश की दस्तक

राकेश योगी

ठीक जैसा बोओगे, वैसा काटोगे वाली कहावत जैसे हालात हैं. प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ और मनमानी का ही नतीजा है कि महाविनाश हमारी ड्योढ़ी पर दस्तक देने को आतुर है. आने वाली कई पीढ़ियों को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है. बावजूद इसके न जनता चेत रही है और न ही सरकार.

यह पंचांग बांचने वाले किसी पंडित की भविष्यवाणी नहीं है. यह सरहद पार के किसी दुश्मन की साजिश भी नहीं है. यह हमारी अपनी करनी है, जिसका फल हमें भुगतना पड़ेगा. जी हां, राजस्थान के रास्ते महाविनाश देश में दस्तक दे रहा है. थार मरुस्थल के लिए पहचाना जाने वाला राजस्थान हमें अपने मतलबपरस्त और अदूरदर्शी कामों के लिए सजा देने का ज़रिया बनेगा. जब यह महाविनाश आएगा तो किसी की तिजोरी में जमा धन काम नहीं आएगा. कोई चाहे कितना अमीर या पावरफुल हो, सब इसकी जद में होंगे. और, यह भयानक नज़ारा अब हमसे दूर नहीं है. हमारी अपनी ही बनाई गई व्यवस्था में वह एक-एक क़दम आगे बढ़ाता जा रहा है. मौजूदा पीढ़ी शायद इसकी आहट ही महसूस कर रही हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हमारे कर्मों का फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा. इस महाविनाश में थार का मरुस्थल महज़ राजस्थान की दुखती रग नहीं रहेगा, बल्कि यह आधे भारत की तकदीर बन जाएगा. बस मुश्किल से एक सदी का सफर बाक़ी बचा है इस आफत के आने में. आप फ़िलहाल सिर्फ़ कल्पना कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कितनी भयानक विरासत छोड़कर जा रहे हैं.

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें क़रीब दो लाख वर्ग किलोमीटर का इलाक़ा रेत के क़ब्ज़े में है. उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ों के बीच 692 किलोमीटर की अरावली पर्वत श्रृंखला इस रेगिस्तान पर लगाम लगाने का काम करती रही है, लेकिन अब इन पहाड़ियों की ताक़त ख़त्म हो रही है. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और तटीय मरुस्थल पर पशुओं एवं इंसानों की बढ़ती आबादी ने इस क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है. रेगिस्तान के सामने दीवार बनकर खड़ी अरावली की पहाड़ियां अब नंगी हो गई हैं और मरुस्थल की ताक़त के समक्ष दम तोड़ने लगी हैं. उपग्रह से लिए गए चित्र बताते हैं कि किस तरह रेगिस्तान इस अरावली की कमज़ोर हो चुकी दीवार में सेंध लगाकर अपना आकार बढ़ाने पर आमादा है. इन चित्रों में साफ नज़र आता है कि रेगिस्तान की रुकावट बनी अरावली की पहाड़ियों में नौ दर्रे बन गए हैं, जहां से रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है. इन दर्रों के ज़रिए रेत लगातार दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ रही है. दक्षिणी राजस्थान प्रदेश का वह इलाक़ा है, जो हरा-भरा, झील, नदियों और प्राकृतिक संपदा से भरपूर हुआ करता था. पिछले कई सालों से यहां भी बारिश का औसत बेहद कम हो गया है. नदी-नाले और झीलें सूख गई हैं. झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर की झीलें अब सूखे मैदानों में तब्दील होती जा रही हैं. राज्य के इस भाग में कभी बारिश की कमी के कारण गंभीर अकाल की स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन पिछले एक दशक से यह क्षेत्र भी अकाल और सूखे की चपेट में है. किसी वक़्त यहां छोटी-बड़ी क़रीब एक दर्ज़न नदियां वर्ष भर बहती थीं, लेकिन अब ऐसी कोई नदी नहीं बची. बारिश के दौरान जिन नदियों और झीलों में थोड़ा-बहुत पानी आ भी जाता है, वह भी कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता है.

दरअसल अरावली के इस क्षेत्र को सरकारी शह पर कुछ इस तरह लूटा जा रहा है, जैसे किसी डूबने वाले जहाज में सवार लोग उसकी क़ीमती चीज़ें तोड़कर अपनी जेबों में भर रहे हों और यह भूल गए हों कि जिस दिन जहाज डूबेगा, उस दिन जेबों में भरा क़ीमती सामान उनके किसी काम नहीं आएगा. यहां मिलने वाला क़ीमती मार्बल ही इस क्षेत्र में आई समृद्धि का कारण रहा और अब वही यहां की बर्बादी की वजह भी बन रहा है. मार्बल के लालच में अरावली में भारी पैमाने पर वैध और अवैध खनन हो रहा है. इस वजह से जंगल ख़त्म हो रहे हैं और पहाड़ भी. इस खनन का सीधा असर पहाड़ों और जंगलों पर पड़ता है, लेकिन व्यापक स्तर पर देखा जाए तो यह तमाम पारिस्थितिकी तंत्र को मटियामेट कर रहा है. पहाड़ों और जंगलों के ख़त्म होने के कारण क्षेत्र में बारिश का औसत तेज़ी से कम हुआ है. साथ ही अरब सागर से आने वाले मानसून का राजस्थान पर मेहरबान होना भी दुश्वार हो गया है. इसके अलावा मार्बल खनन और उसकी प्रोसेसिंग यूनिटों से भारी मात्रा में सफेद पाउडर निकलता है, जो इंसानों के फेफड़ों में जमकर सांसें रोक देता है और ज़मीन पर फैलने के बाद उसकी पानी सोखने जैसी सामान्य प्रक्रियाओं को रोक देता है. यही वजह है कि बारिश होने के बावजूद पानी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है. अलग-अलग हिस्सों में फैला पानी ज़मीन के नीचे चलने वाली अंतर्धाराओं के माध्यम से संरक्षित रहता है और नदियों या झीलों को वर्षपर्यंत भरा रखने में मदद करता है. यही अंतर्धाराएं भूमिगत जलस्तर का पैमाना होती हैं और कुएं आदि से सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था का आधार भी. दक्षिणी राजस्थान की धरती पर यहां-वहां जमा हो रहा मार्बल पाउडर इस प्राकृतिक जल तंत्र को नष्ट कर रहा है और इसके प्रभाव भी साफ नज़र आने लगे हैं, लेकिन इंसान का लालच है कि बर्बादी की कगार पर आकर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. इस लालच को सरकारी शह भी मिली हुई है, क्योंकि उसके बिना संरक्षित अरावली क्षेत्र को इस तरह लूटना संभव नहीं होता. अरावली की पहाड़ियां देश के दो प्रमुख जल निकास प्रबंधों को अलग करती हैं. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ़ पानी ले जाने वाली नदियों के बीच अरावली दीवार की तरह खड़ी है. इसके पूर्व की तरफ़ का पानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम का पानी अरब सागर में जाता है. इसी वजह से इसे ग्रेट इंडिया डिवाइडर कहा जाता है. इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो सिर्फ़ राजस्थान नहीं, बल्कि समूचे उत्तर भारत में पर्यावरण की ख़तरनाक समस्याएं पैदा होती हैं. इस संतुलन के बिगड़ने से ही वर्षा का औसत घट रहा है और भूमिगत जलस्तर भी. अरावली के साथ हो रहे विनाशकारी दोहन के कारण राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पर सीधा असर पड़ने के हालात बन रहे हैं. इन राज्यों की तरफ़ भी रेगिस्तान का फैलाव शुरू हो सकता है. इसकी शुरुआत धूल भरी आंधियों, भीषण गर्मी और बारिश की कमी जैसे संकेतों के रूप में हो चुकी है. दरअसल अरावली की पहाड़ियां ही गंगा के मैदान में धूल भरी आंधियों और रेत के फैलाव को रोकती हैं. अरावली के कमज़ोर होने पर रेगिस्तान की इस विभीषिका को रोकना मुश्किल होगा. अरावली में पैदा हुए दर्रों के रास्ते से जो रेत उड़कर राजस्थान के पूर्वी भागों से होते हुए आगरा तक पहुंच रही है, वह आने वाले भयावह कल का इशारा कर रही है. वनों की कमी, भूमि कटाव और अंधाधुंध खनन के कारण अरावली अब मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध के रूप में समर्थ नहीं रही. यहां पहाड़ों को काटकर उन्हें चट्टानी रेगिस्तान में तब्दील किया जा रहा है. रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सबसे पहली एवं सबसे मोटी दीवार को जिस बेरहमी और वीभत्स तरीक़े से मिटाया जा रहा है, वह अपनी मां को नोच-नोचकर खा जाने से भी गंभीर अपराध है.

देश और प्रदेश की सरकार अकाल, सूखे, भूमिगत जलस्तर में कमी और नदियों-झीलों के सूखने की समस्याओं के लिए हज़ारों करोड़ की योजनाएं बनाती हैं. हो सकता है, इस राशि का कुछ प्रतिशत ख़र्च भी होता हो, लेकिन समस्या के मूल कारणों की तरफ़ ध्यान देने की किसी को शायद फ़ुर्सत नहीं है या फिर खनन माफ़ियाओं के कुचक्र और लालच में फंसा शासन-प्रशासन जानबूझ कर इस ओर से आंखें मूंदे बैठा है. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें विनाश के भागीदार बने सभी लोग इसके प्रभावों से भी अछूते नहीं रहेंगे, फिर भी तात्कालिक लालच उन्हें अकर्मण्य बना रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

स्कूलों में दुर्व्यवहार के दंश से पीड़ित बच्चों की कोई उम्र विशेष नहीं होती. यह किसी भी उम्र के बच्चे के साथ घटित हो सकता है, जिसके कारण उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ती है.

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का सवाल

उमाशंकर मिश्र

हाल में उड़ीसा विधानसभा में एक ऐसे मुद्दे को लेकर गहमागहमी बढ़ गई, जिसका सीधा संबंध ग़रीब आदिवासियों की बेबसी और लाचारी की आड़ में उनके शोषण से जुड़ा था. राज्य सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विद्यालय, जो ग़रीब एवं पिछड़े आदिवासी छात्रों को शिक्षा का उजाला दिखाने के लिए खोले गए थे, उनके उत्पीड़न का केंद्र बन गए. नवरंगपुर ज़िले के सेवाश्रम आवासीय स्कूल की एक अध्यापिका ने जब स्कूल के पुरुष अध्यापकों द्वारा लड़कियों के साथ बलात्कार एवं उत्पीड़न की सूचना पुलिस को दी तो मामला प्रकाश में आया. इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ए के साहू और एक अन्य अध्यापक ईश्वर को लड़कियों के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. बलात्कार पीड़ित दो लड़कियां गर्भवती हैं. बाद में तीन अन्य अध्यापकों को भी हिरासत में ले लिया गया. अपनी परंपराओं से बंधा जनजातीय समाज अब शायद ही इन लड़कियों को स्वीकार करेगा. यदि ऐसा हुआ तो पीड़ित लड़कियों को बहिष्कृत जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इस आशंका के मद्देनजर उड़ीसा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इन लड़कियों के लिए शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था करने की मांग की है. लड़कियों के प्रत्येक छात्रावास में महिला वार्डन रखने की मांग भी की गई. राज्य का हर राजनीतिक दल तमाम मतभेदों के बावज़ूद आज इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा नज़र आता है. इसी तरह एक मामला केरल के मल्लापुरम ज़िले का है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा संचालित हॉस्टल के पादरी को एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मार्च के पहले सप्ताह में फादर के जी जोसेफ उर्फ फादर हबीब जोसेफ को केरल की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जमानत मिल गई. पादरी पर आईपीसी की धारा 354 के तहत किसी महिला के शीलहरण के प्रयास के आरोप लगाए गए थे. पीड़ित लड़की चर्च द्वारा चलाए जा रहे कैथोलिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है. इस मामले को ध्यान में रखकर अब पुलिस गत वर्ष अक्टूबर में लड़की की बड़ी बहन की कथित तौर पर खाद्य संक्रमण से हॉस्टल में हुई मौत की जांच में जुट गई है, जिसके कुछ दिनों बाद ही नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने पादरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

स्कूलों में बच्चों के उत्पीड़न की घटनाएं प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं. यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी स्वीकार की है. पिछले साल नेशनल चाइल्ड राइट्स पैनल को स्कूलों में बच्चों के उत्पीड़न की 95 शिकायतें मिली थीं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक़, स्कूलों में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के दर्ज़ मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है. इनमें यौन शोषण, उत्पीड़न, अपमान, हत्या एवं शारीरिक दंड जैसे मामलों में गत तीन वर्षों में तीन गुना तक वृद्धि हुई है. 2007–08 में 34, 2008–09 में 68 और वर्ष 2009–10 में 21 राज्यों से इस तरह के 95 मामले सामने आए हैं. गत वर्ष पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था, जहां ऐसे 27 मामले सामने आए, जिनमें से 20 शारीरिक उत्पीड़न एवं एक मामला हत्या से जुड़ा था. वहीं तमिलनाडु में 12 और दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में बच्चों से दुर्व्यवहार के 9–9 मामले सामने आए. राजस्थान, हरियाणा, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में इस तरह के 4–4 मामले दर्ज़ किए गए थे. जानकारों की मानें तो ज़्यादातर डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों, न्यायाधीशों एवं पुलिस अधिकारियों को यही नहीं पता होता कि इन मामलों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आमतौर पर यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता. बच्चों के साथ स्कूलों में कई तरह के दुर्व्यवहार होते रहते हैं, जिससे उनमें शर्म या डर की भावना बैठ जाती है. शरीर के साथ हानिकारक या आक्रामक संसर्ग और ऐसी कोई बात या फिर व्यवहार, जो बच्चे को शारीरिक अथवा मानसिक आघात पहुंचाता हो, आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है. पूरी दुनिया में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं. पहले तो उक्त मामले घर की चाहरदीवारी में अभिभावकों तक ही सीमित रहा करते थे, लेकिन अब शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय भी बच्चों के लिए भयावह साबित हो रहे हैं. इस संक्रमण ने गुरु–शिष्य परंपरा का देश कहे जाने वाले भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी है.

गत वर्ष जब नेशनल चाइल्ड राइट्स पैनल ने स्कूलों में बच्चों के उत्पीड़न से जुड़ी क़रीब 95 शिक़ायतें मिलने का ख़ुलासा किया तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी इस बात पर सहमति जताई. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक़, पिछले तीन वर्षों में स्कूली बच्चों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों में तीन गुना तक वृद्धि हुई है. आख़िर वजह क्या है और सरकार इस संदर्भ में ख़ामोश क्यों है?

स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामले उड़ीसा जैसे दूरदराज के जनजातीय इलाक़े तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अनेक गांवों, कस्बों एवं शहरों के स्कूलों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को कभी अध्यापकों, कर्मचारियों या फिर उम्र में बड़े अन्य छात्रों के शोषण का शिकार बनना पड़ता है. स्कूलों में बच्चों के शोषण का यह सिलसिला राजधानी दिल्ली में भी अपने पैर जमा चुका है. हाल में दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में पांचवी कक्षा के बच्चे के साथ कुकृत्य की बात सामने आई है. गत वर्ष दिल्ली के मालवीय नगर इलाक़े में 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकृत्य का मामला हो या फिर बात उत्तर– पश्चिमी दिल्ली में 10 वर्षीय बच्चे के साथ स्कूल के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की हो, हर जगह मासूम बच्चों को बेखौफ शिकार बनाया जा रहा है. जुलाई 2008 में एमसीडी के ही एक स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल परिसर में बलात्कार की बात सामने आई थी. तब एमसीडी ने स्कूल परिसरों में सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन हालिया घटनाएं स्कूलों, विशेषकर सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं. इससे पहले वर्ष 2007 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के उत्पीड़न को लेकर देश भर में एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे. इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 13 राज्यों में 5 से 12 साल तक की उम्र के 12,247 और 12 वर्ष से अधिक उम्र के 2,324 बच्चों से बातचीत की गई थी. सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इस तरह के मामले न रुकने से वास्तविकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अध्ययन के मुताबिक़, प्रत्येक दो बच्चों में से एक को स्कूल में यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है. चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या अधिक रहती है, जिसमें छेड़छाड़ से लेकर पोर्नोग्राफी के माध्यम से उकसाने और सेक्सुअल दुराचरण के मामले शामिल रहते हैं.

कुछ समय पूर्व दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आमोद कंठ ने एक ऐसी रणनीति एवं संरचना ईज़ाद करने की जरूरत पर ज़ोर दिया था, जहां बच्चे हिंसामुक्त एवं भयमुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकें. ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष रामपाल बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं. दिल्ली स्थित संस्था प्लान इंडिया ने भी इस मुद्दे पर स्कूल प्राधिकारियों, सरकारी निकायों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श का आयोजन किया और सुरक्षित स्कूल परिसर से जुड़ी गाइड लाइंस के क्रियान्वयन की मांग सरकार से की थी. सबसे ज़्यादा ठेस अभिभावकों के उस भरोसे को पहुंचती है, जिसके चलते वे अध्यापकों एवं शैक्षिक संस्थानों पर विश्वास करके अपने बच्चों को वहां शिक्षा के लिए भेजते हैं.

भारत में बच्चों के साथ होने वाले दुराचार की बात को आमतौर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता. शायद तभी पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा था कि बच्चों पर होने वाले अत्याचारों पर चुप रहकर हम इसे बढ़ावा देते हैं. लेकिन जो भी हो, यह एक कड़वी सच्चाई है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर अध्यापकों द्वारा कई बार तो ऐसे कृत्य किए जाते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ बच्चों के मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनमें हीन भावना घर कर जाती है. ताजा घटना मध्य प्रदेश के जनजातीय ज़िले बड़वानी की है, जहां एक क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को उत्पीड़ित करने की एक अनूठी घटना सामने आई है. इसमें कथित तौर पर बच्चों को चप्पलों की माला पहनाए जाने की बात कही जा रही है. भारत में चप्पलों की माला पहना कर सज़ा ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, जिसने सामाजिक एवं नैतिक नियमों का उल्लंघन किया हो. लेकिन, मासूम बच्चों के मामले में क्या ऐसा सोचा जा सकता है? सेंट ऑगस्टाइन स्कूल से संबद्ध सिस्टर मेरी जॉन के मुताबिक़, अभिभावकों ने इस बारे में पुलिस में शिक़ायत दर्ज़ नहीं कराई. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जब तक अभिभावक कोई शिकायत दर्ज़ नहीं कराते, हम कुछ नहीं कर सकते.

स्कूलों में दुर्व्यवहार के दंश से पीड़ित बच्चों की कोई उम्र विशेष नहीं होती. यह किसी भी उम्र के बच्चे के साथ घटित हो सकता है, जिसके कारण उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ती है. कई बार तो नौबत बच्चे की मृत्यु तक पहुंच जाती है. हरियाणा में रुचिका गिरहोत्रा की मौत को बानगी के तौर पर देखा जा सकता है. डर और सामाजिक दबाव के कारण स्कूलों से विशेषकर लड़कियों की ड्रॉप आउट दर अधिक देखने को मिलती है. ग्रामीण स्कूलों में तो शौचालय की सुविधा तक नहीं होती, जिसके चलते छात्राओं को विशेष तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वर्ष 2007 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण स्कूलों में आवश्यक जन सुविधाओं की बेहतरी की सिफरिश की गई थी, जिससे स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति एवं नामांकन को बढ़ाया जा सके. गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में स्कूलों की स्थापना के अलावा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ज़रूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

भारत में ऐसा कोई क़ानून नहीं है, जो हर दृष्टिकोण से बाल उत्पीड़न को रोकने में कारगर हो. हालांकि कुछ जानकार समस्या की जड़ क़ानूनों की अपेक्षा उन्हें क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के ढुलमुल रवैये को मानते हैं. बच्चों के यौन उत्पीड़न को ठीक से परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है. किसी बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के मामले में क़ानून की स्थिति और भी अस्पष्ट हो जाती है. ऐसे मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भूमिका शुरू हो जाती है, जिसमें कई खामियां हैं.

दूसरी ओर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो में बच्चों के उत्पीड़न से जुड़े सिर्फ़ ऐसे मामले शामिल रहते हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज़ कराई जाती है. लेकिन ऐसे मामलों की भरमार है, जो किसी कारणवश प्रकाश में नहीं आ पाते. पिछली सरकार ने बाल अपराध निरोधक बिल संसद में लाने की बात की थी. बच्चों की सुरक्षा पर बजट राशि 0.03 प्रतिशत में बढ़ोत्तरी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी. इस तरह नीतियां बनाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें अमलीजामा पहनाए जाने से पहले ही सारा उत्साह ठंडा हो जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बनाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को ऐसा करने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है.

साइबर अपराध और क़ानून

जस्टिस राजेश टंडन

सूचना तकनीक क़ानून के अंतर्गत मामलों के निष्पादन के लिए इसमें धारा 46 का प्रावधान किया गया है. मामलों के निष्पादन का अधिकार सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी को दिया गया है, जो इस क़ानून की धारा 46 और 47 के अंतर्गत मुआवज़े या क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करेगा.

धारा 46-निष्पादन का अधिकार

1. किसी व्यक्ति द्वारा सूचना तकनीक क़ानून के किसी भी प्रावधान या इससे संबंधित केंद्र सरकार के किसी भी नियम, दिशानिर्देश या आदेश की अवहेलना की हालत में उपखंड (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को जांच अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार हासिल है. यह जांच अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर या राज्य सरकार में इसी स्तर का अधिकारी हो सकता है और वह सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में संबद्ध प्रावधानों के तहत मामले की जांच-पड़ताल करेगा.

2. उपखंड (1) के अंतर्गत जांच अधिकारी आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के पर्याप्त मौक़े देगा और जांच के बाद यदि उसे लगता है कि क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो वह जुर्माना या भरपाई का आदेश दे सकता है.

3. किसी ऐसे ही अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और उसके क़ानूनी पक्षों का विस्तृत अनुभव हो.

4. यदि एक से ज़्यादा जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार एक आदेश द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करेगी.

5. जांच अधिकारी की शक्तियां सिविल कोर्ट के अधिकारों के समतुल्य होंगी, जो धारा 58 के उपखंड (2) के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को हासिल हैं और-

ए. इसकी सारी कार्रवाई को इंडियन पेनल कोड की धाराओं 193 और 228 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा. (1860 का 45)

बी. आपराधिक क़ानून संहिता, 1973 की धाराओं 345 और 346 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया को सिविल कोर्ट की क़ानूनी प्रक्रिया के समतुल्य माना जाएगा. (1974 का 2)

धारा 47-जांच अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य

उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने की राशि का निर्धारण करते समय जांच अधिकारी निम्न तथ्यों को ध्यान में रखेगा-

ए. आपराधिक कृत्य से होने वाला आर्थिक मुनाफा, यदि उसकी गणना संभव हो.

बी. अपराध से पीड़ित पक्ष को होने वाली आर्थिक हानि.

सी. अपराध का दोहराव

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 की धाराओं 43 एवं 44 में जुर्माने और क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं.

धारा 43-जुर्माना और क्षेत्राधिकार

कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क आदि को नुक़सान पहुंचाने का दंड यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के मालिक या इसके लिए अधिकृत अधिकारी के आदेश के बिना-

ए. कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना लेता है.

बी. इस पहुंच के आधार पर वह कंप्यूटर में संग्रहित डाटा या जानकारियां हासिल कर लेता है.

सी. कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस जैसी कोई चीज़ डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है.

डी. कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करने या उसमें संग्रहित आंकड़ों या कार्यक्रमों को बाधित करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है.

इ. किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की कार्यप्रणाली को बाधित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है.

एफ. किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बनाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को ऐसा करने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है.

जी. उक्त क़ानून के प्रावधानों के ख़िलाफ़ किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बनाने का मौक़ा देता है या ऐसा करने में उसकी मदद करता है.

एच. कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में संग्रहित जानकारियों के साथ छेड़छाड़ कर इसे दूसरे के सिर मढ़ने की कोशिश करता है तो-

उसे पीड़ित पक्ष को हर्जाना देना पड़ सकता है. हर्जाने की यह राशि अधिकतम एक करोड़ रुपये हो सकती है.

66-ए. कोई व्यक्ति कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी भेजता है जो-

ए. दुर्भावना से प्रेरित हो या ख़तरनाक हो.

बी. ग़लत है, लेकिन किसी को परेशान करने, ख़तरे में डालने, चोट पहुंचाने, धमकी देने, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने, दुश्मनी की भावना या घृणा फैलाने के इरादे से जानबूझ कर बार-बार भेजता है.

सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से कोई ईमेल या ऐसा संदेश भेजता है, जिसमें भेजने वाले का नाम स्पष्ट न हो और जिसका उद्देश्य संबद्ध व्यक्ति को परेशान करना या धोखा देना हो, तो उस पर तीन साल के कारावास के साथ-साथ जुर्माने का दंड आरोपित किया जा सकता है.

66-बी. यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से चुराई गई या ग़लत तरीक़े से हासिल की गई सूचनाएं प्राप्त करता है या अपने पास रख लेता है तो उसे अधिकतम तीन साल का कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है.

66-सी. यदि कोई धोखेबाज़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या निजी पहचान से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हासिल कर उसका ग़लत इस्तेमाल करता है, तो उसे तीन साल तक के अधिकतम कारावास एवं/अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी होना पड़ सकता है.

66-डी. यदि कोई सूचना तकनीक के किसी भी माध्यम की मदद से अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे इंसान की पहचान का इस्तेमाल करता है, तो उसे अधिकतम तीन साल तक के कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है.

66-इ. यदि कोई किसी की निजी ज़िंदगी में दख़ल देते हुए उससे पूछकर या बिना पूछे उसके निजी पलों को कैमरे में कैद कर उसे सार्वजनिक करता है और उसकी निजता को भंग करने की कोशिश करता है, तो उसे अधिकतम तीन साल का कारावास एवं/अथवा दो लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी होना पड़ सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अश्लील जानकारियों के प्रकाशन एवं प्रसारण से संबंधित प्रावधान इस क़ानून की धारा 67 में उल्लिखित हैं.

धारा 67-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन

यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है, जो अश्लील हो या जिससे कामुकता झलकती हो और जिससे इसे देखने, पढ़ने या सुनने वालों के ऊपर ग़लत असर पड़ने की आशंका हो, तो पहली बार किए गए ऐसे अपराध की हालत में उसे अधिकतम पांच साल तक के कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. यदि यह अपराध दोबारा प्रमाणित हो जाए तो आरोपी को अधिकतम दस साल तक का कारावास एवं दो लाख रुपये तक का आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है. इस क़ानून में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा 67-ए और 67-बी धाराओं को जोड़ा गया है.

67-ए. यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से किसी ऐसी सामग्री के प्रकाशन या उसे प्रचारित करने का दोषी पाया जाता है, जो अश्लील हो तो पहली बार किए गए ऐसे अपराध की हालत में उसे अधिकतम पांच साल के कारावास एवं दस लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. अपराध के दोबारा किए जाने की हालत में यह दंड अधिकतम सात साल के कारावास एवं दस लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है. इन सभी अपराधों की सुनवाई और दंड निर्धारित करने का अधिकार जांच अधिकारी के हाथों में निहित है.

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 की धारा 43 एवं 44 में दंड और क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों की व्याख्या की गई है. इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी के फ़ैसले के बाद धारा 48 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील की जा सकती है.

धारा 48-साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन

1. केंद्र सरकार घोषणा द्वारा एक या ज़्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनलों का गठन कर सकती है, जिसे साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है.

2. उपखंड (1) के अंतर्गत उक्त घोषणा में सरकार अपीलेट ट्रिब्यूनल के कार्यों एवं उसके क्षेत्राधिकार की भी व्याख्या करेगी. अपीलेट ट्रिब्यूनल की शक्तियां सूचना तकनीक क़ानून की धारा 58 में उल्लिखित हैं.

धारा 58-साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियां

साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करना है. इसके अलावा सूचना तकनीक क़ानून के अन्य प्रावधानों के मद्देनज़र ट्रिब्यूनल अपनी प्रक्रिया को नियमित करने के लिए स्वतंत्र है. यह ख़ुद ही इस बात का फ़ैसला करेगा कि इसकी बैठकें कहां और कैसे आयोजित होंगी.

2. अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए ट्रिब्यूनल की शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल कोर्ट के समतुल्य होंगी. इसे उक्त अधिकार निम्न मामलों से संबंधित अपीलों की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में हासिल होंगे-

ए. किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने और उसे अपना पक्ष रखने में.

बी. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ की खोज और उसे पेश करने में.

सी. हलफनामे के रूप में सबूत हासिल करना.

डी. साक्ष्यों और सबूतों की सत्यता की जांच.

इ. अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना.

एफ. अपीलों को ख़ारिज करना.

जी. कोई भी अन्य मुद्दा, जो इसके सामने पेश किया जाए.

3. धारा 193 और 228 के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की हर प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा, जबकि धारा 195 और आपराधिक आचार संहिता के XXVI के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समतुल्य माना जाएगा. सूचना तकनीक क़ानून की प्रस्तावना के मुताबिक़, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को क़ानूनी मान्यता देना है. क़ानून की धारा 1(2) के मुताबिक़, क़ानून में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर यह भारत के पूरे भूभाग में प्रभावी है. इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा देश से बाहर भी इसके प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में यह प्रभावी होगा.

मूल क़ानून की धारा 70 में निम्न उपखंडों में बदलाव किए गए हैं-

1. राजकीय गजट में घोषणा द्वारा सरकार सूचना की संवेदनशीलता के मद्देनज़र किसी भी कंप्यूटर संसाधन को सुरक्षित घोषित कर सकती है.

उपखंड (3) के बाद एक और उपखंड जोड़ा गया है-

(2) केंद्र सरकार उक्त सुरक्षित संसाधन के लिए सूचनाओं की सुरक्षा के तरीक़े और इसकी प्रक्रिया के बारे में दिशानिर्देश जारी करेगी.

इसी तरह धारा 70 के बाद निम्न उपखंडों को जोड़ा गया है-

70 (1) केंद्र सरकार गजट में अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए शीर्ष निकाय घोषित कर सकती है.

(2) उपखंड 1 के अंतर्गत शीर्ष निकाय घोषित की गई संस्था संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण से संबंधित सभी ज़रूरी कार्यों, जैसे शोध एवं विकास के लिए ज़िम्मेदार होगी.

(3) उपखंड (1) में उल्लिखित एजेंसी के कर्तव्यों और प्रक्रियाओं को गजट में ही स्पष्ट कर दिया जाएगा.

70-बी. (1) केंद्र सरकार गजट में अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संगठन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के रूप में घोषित कर सकती है.

(2) केंद्र सरकार उपखंड (1) में उल्लिखित उक्त संस्था को महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगी.

(3) महानिदेशक एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों की स्पष्ट व्याख्या अधिघोषणा में की जाएगी.

48. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

(1) साइबर घटनाओं से संबंधित सूचनाओं और आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और उसे प्रचारित-प्रसारित करना.

(2) साइबर घटनाओं से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करना.

(3) साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपातकालीन घटनाओं से निबटने के लिए ज़रूरी क़दम उठाना.

(4) साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बीच सामंजस्य क़ायम करना.

(5) साइबर सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश, सलाहें, प्रक्रियाओं की जानकारी आदि जारी करना.

(6) साइबर सुरक्षा से संबंधित अन्य ज़रूरी कार्यों को अंजाम देना.

मूल क़ानून की धारा 77 की जगह निम्न धाराओं को इसमें जगह दी गई है-

77. इस क़ानून के अंतर्गत आरोपित किए गए हर्जाने, जुर्माने या संपत्ति ज़ब्त करने के फैसले पर किसी अन्य क़ानून के अंतर्गत दिए गए फ़ैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा.

77-ए. मामले पर फ़ैसला लेने के लिए अधिकृत न्यायालय किसी अन्य आरोप के सिलसिले में आरोपी के दंड को बढ़ा सकता है या उसके स्वरूप में बदलाव कर सकता है.

(2) इस क़ानून के अंतर्गत आरोप झेल रहा शख़्स अदालत में अपने मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दाख़िल कर सकता है और ऐसे मामलों में अपराध आचार संहिता, 1973 की धाराएं 265-बी और 265-सी प्रभावी होंगी.

77-बी. कोई भी ऐसा अपराध, जिसके लिए तीन साल या उससे ज़्यादा के कारावास की सजा हो सकती हो तो उसका संज्ञान लिया जा सकता है और कोई ऐसा अपराध, जिसके लिए तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती हो तो उसमें जमानत हो सकती है. ऐसे मामलों में अपराध आचार संहिता, 1973 के प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं होगा.

हालांकि, मेरा मानना है कि साइबर अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क़ानून बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे क़ानून में देश के बाहर किए गए अपराधों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.

(लेखक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं)

feedback@chauthiduniya.com

ग़रीबी से पीड़ित जो मियो किसान बनिया-साहूकारों से क़र्ज़ लेते थे, उनसे हर महीने 5 फ़ीसदी यानी हर साल 60 फ़ीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता था.

आतंकी इस्लाम के आ... सही नहीं ठहरा सकते. ... मुख्य आधार ही ख़त्म ...

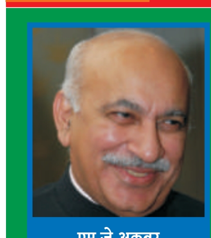

एम जे अकबर

थरूर का इस्तीफ़ा कहानी का अंत नहीं है

भारतीय मीडिया में अब तक के सबसे अनोखे सोप ओपेरा एवं सनसनीखेज क्राइम थ्रिलर से अचंभित और रोमांचित हो रहे लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने शायद अगाथा क्रिस्टी की लिखी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस नहीं पढ़ी. उन्होंने इसके फ़िल्मी रूपांतरण में अल्बर्ट फिनी और पीटर उस्तीनोव को हरक्यूल पॉयरट के किरदार में भी नहीं देखा है. कातिल की तलाश में लगे पॉयरट के अधपके बालों का रंग और भी सफेद हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कातिल उन्हीं बारह लोगों में से एक है, जो ट्रेन में सवार थे. लेकिन उन अधपके बालों ने कोई ग़लती नहीं की, उसने सनसनीखेज सत्य को सबके सामने ला खड़ा किया, उनमें से हरेक दोषी था.

आईपीएल के मौजूदा तमाशे में भी कुछ यही हाल है. आईपीएल के अंदर क्या चल रहा था, यह सबको पता था. मॉरीशस से आ रहे बेनामी पैसे से लेकर सट्टेबाज़ी और रंग-रंगीली पार्टियां तक किसी से छुपी नहीं थीं. ख़ामोशी ख़रीदने के लिए इन्हीं चीज़ों का बख़ूबी इस्तेमाल भी किया गया, धंधा बढ़ता गया और इसके साथ ख़ामोशी भी बढ़ती गई. ख़ामोशी ख़रीदने के लिए किसी तानाशाह की ज़रूरत नहीं होती. इसके लिए मार्क्सवाद की एक प्रचलित अवधारणा के आधुनिक रूपांतरण की मदद ली गई. सबसे उनकी योग्यता के हिसाब से, सबको उनके लालच के हिसाब से. किंवदंती का हिस्सा बन चुके पॉयरट को तथ्यों की तलाश थी, लेकिन दिल्ली को केवल बलि के बकरों की तलाश है. दोनों में से कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता ज़्यादा मुश्किल है. बलि के बकरे की एक ख़ासियत होती है, बलि से ठीक पहले वह अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ जाता है. आपने अभी-अभी एक को देखा है और अब एक और की तलाश है. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो हलाल होने जाते समय ख़ूब शोरशराबा करते हैं. यदि उनकी ज़ुबान बंद कर दी गई हो तो गोपनीय तरीक़े से भेजे गए किसी ई-मेल की मदद ले सकते हैं. हर चीज़ की जानकारी रखने वाला ललित मोदी जैसा इंसान आसानी से गुमनामी के अंधेरे में जाने को तैयार नहीं होगा, बल्कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश ज़रूर करेगा. वह अकेला नहीं डूबेगा. यदि वह अपने साथ किसी कैबिनेट मंत्री को भी इस्तीफ़ा देने को मजबूर करता है तो इससे केंद्र सरकार की स्थिरता को ख़तरा पैदा होता है. हालांकि इससे सरकार के अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता.

सरकारें जानबूझ कर आत्महत्या नहीं करतीं, लेकिन कई बार ग़लती से ऐसा कर बैठती हैं. यदि आप चोट के चलते एक पैर से लंगड़ा रहे हों तो प्रतिशोध में दूसरा पैर भी तोड़ नहीं लेते. यही वजह है कि राजनीतिज्ञ जांच का रुख़ मोड़ने के लिए हर पैंतरे अपनाएंगे. वे आधे-अधूरे सत्य, बेदम तर्कों और कई बार सफेद झूठ तक का सहारा ले सकते हैं. सत्तारूढ़ गठबंधन में मची हलचल शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं है. टीमों के मालिकों में कई दक्षिण भारतीय हैं और उनकी शक्तियों को कम करके आंकना ग़लती हो सकती है. फिर यह भी याद रखना होगा कि द्रमुक को पटाना सबसे आसान है. राजनीतिज्ञों के हाथों का

सबसे बड़ा हथियार है आम जनता की भूलने की आदत. आरोप-प्रत्यारोप, रिपोर्ट और भविष्यवाणियों से निकलती हर नई ख़बर के बाद लोग अक्सर पुरानी बातों को भूल जाते हैं. पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक़, एक केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि टीम की फ्रेंचाइजी को बुलाकर उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था, जिसमें कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था. प्रस्ताव था, हमारी बात मान लो या फिर...लेकिन रिपोर्ट में उस मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया गया था. इतनी बड़ी ख़बर आज कहां ग़ायब है. यह सवाल मत पूछो, वरना...

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा अपने अधिकारियों को जांच कार्य में लगाने का असली मतलब उनके अगले क़दम से स्पष्ट होगा. मौजूदा विवाद से निबटने में उन्होंने बड़ी परिपक्वता से क़दम उठाए हैं, लेकिन फाइलों में बंद जानकारियों के दम पर वह कितना कर सकते हैं. काले धन को सफेद बनाने के कई रास्ते हैं और इसके लिए एकाउंटेंट की कलम को बस थोड़ा ही मोड़ना पड़ता है. मुखर्जी के पास आज मौक़ा है कि वह आईपीएल के साथ कई और क्षेत्रों की गंदगी को साफ कर सकते हैं. वह चाहें तो निजी क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को भी चुनौती दे सकते हैं. लेकिन यह फ़ैसला वह अकेले नहीं ले सकते. आईपीएल के शीर्ष पर बैठा राजनीतिज्ञों-खेल प्रशासकों का गठजोड़ बेताबी से उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है, जब लोग इस ख़बर से थक जाएं और तब यह ख़बर टीवी चैनलों, अख़बारों और यहां तक कि आम लोगों के जेहन तक से निकल जाएगी. लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पिछले छह दशकों में इतनी बड़ी ख़बर नहीं आई, जिसमें सेक्स, झूठ और सुपरस्टारों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ हो. इसमें पैसा है, भाई-भतीजावाद है, मॉडल्स हैं, शराब-शबाब है और पार्टियां हैं, जिसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी रात के अंधेरे में खेलते हैं. इससे गुजरे जमाने में पाकिस्तानी क्रिकेट के हीरो रहे इमरान ख़ान की एक पुरानी टी-शर्ट याद आ जाती है. इसमें अंदरखाने रहकर काम करने वाले लोग हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, जुआरियों की जमात है तो सट्टेबाज़ी का पूरा तंत्र भी शामिल है. कैमरे के सामने सेलिब्रिटी एक-दूसरे के पीछे भागते हैं, कटाक्ष करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे गोपनीय तरीक़ों से पैसों का लेन-देन होता है और अफवाहों पर भरोसा करें तो यह पैसा क्रिकेट के खेल से जुड़े ऐसे लोगों तक पहुंचता है, जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते. कोई संदेह नहीं कि इन सबके बीच नए ढंग का क्रिकेट भी देखने को मिलता है. जब इतना मसाला मौजूद हो तो मीडिया इस पर हाय-तौबा मचाने के लोभ से कैसे बच सकता है. आईपीएल के पहले सेमी फाइनल से ठीक पहले लोगों की नज़रें मैच से ज़्यादा लगातार आ रही ख़बरों पर ही लगी थीं. संभव है कि जल्द ही इस पर मसालेदार फ़िल्मों का निर्माण शुरू हो जाए. आप डिज़ाइनर कपड़ों में शोले या लगान के नए अवतार की संभावना से इंकार नहीं कर सकते. कितने पैसे थे कालिया?

आलोचकों ने आईपीएल को सर्कस का नाम दिया है. जब आप टिकट ख़रीद कर सर्कस देखने जाते हैं तो आपको जोकर के साथ ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो शेरों को अपने इशारे पर नचाते हैं. लेकिन जब इनके बीच का फ़र्क़ मालूम करना नामुमकिन हो जाए तो मुश्किल हो सकती है.

इतना तो सत्य है कि शशि थरूर का इस्तीफ़ा इस कहानी का अंत नहीं है. यह तो धारावाहिक की शुरुआत भर है.

feedback@chauthiduniya.com

मेवात का सामाजिक-आर्थिक परिवेश और तबलीगी जमात

योगी सिकंद

मेवात इलाक़े में अधिकतर ज़मीनों पर खेती मियो किसान ही करते थे, लेकिन कुछ चौधरियों (स्थानीय समुदायों के नेताओं) को छोड़कर बड़े जमींदारों में उनकी गिनती नहीं थी. अधिकांश मियो छोटे किसान ही थे और ग़रीबी की हालत में जीते थे. (गिब्सन 1909:13) ज़मीन की उत्पादकता कम थी, वहीं आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का भी नितांत अभाव था. परिणामस्वरूप, मेवात में अक्सर अकाल जैसी हालत पैदा हो जाती थी और मियो किसान जैन एवं हिंदू बनिया साहूकारों के क़र्ज़ में डूबने को मजबूर थे. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उनकी ख़राब आर्थिक स्थिति दिनोंदिन और बिगड़ती चली गई. पंजाब सरकार की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1916 के मुताबिक़, मियो किसानों की स्थिति तेज़ी से बिगड़ती जा रही है. वे दाने-दाने को मोहताज हैं. शादी में ख़र्च के लिए, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि के लिए या छोटी-मोटी सुख-सुविधाओं के लिए भी उन्हें साहूकारों की शरण में जाना पड़ता है. नतीजा यह होता है कि जब सूखा या अकाल पड़ता है तो उन्हें साहूकारों की मनमानी शर्तों पर उधार के लिए मजबूर होना पड़ता है. (राठी 1971 ए:43)

एक सूत्र के अनुसार, ग़रीबी से पीड़ित जो मियो किसान बनिया- साहूकारों से क़र्ज़ लेते थे, उनसे हर महीने 5 फ़ीसदी यानी हर साल 60 फ़ीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता था. (डब्ल्यू.ख़ान 1988:34) ज़्यादातर मियो किसान क़र्ज़ चुकाने में असमर्थ होते गए, नतीजा उनकी गिरवी रखी ज़मीन पर बनिया-साहूकारों ने अपना क़ब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया. 1910 के आते-आते मियो किसानों की क़रीब 40 फ़ीसदी ज़मीन बनिया-साहूकारों के पास गिरवी हो चुकी थी. (राठी:43) ज़मीन पर साहूकारों द्वारा क़ब्ज़ा जमाने की यह प्रथा अंग्रेजों द्वारा ज़मीन पर मालिकाना हक़ को लेकर शुरू की गई नई सोच का नतीजा था, जिसमें ज़मीन को ऐसी चीज़ और निजी संपत्ति के रूप में देखा जाता था, जिसे ख़रीदा, बेचा और गिरवी रखा जा सकता था. पहले जहां मियो किसान खेतों में लगी फ़सल को गिरवी रखकर उधार लेते थे, अब ज़मीन को ही गिरवी रखने लगे. यह मियो किसानों की बढ़ती ग़रीबी और दरिद्रता का नतीजा था.

यह ग़रीबी लगातार बढ़ती गई तो मियो किसानों को यह अनुभव होने लगा कि साहूकार उनकी मजबूरियों का केवल फ़ायदा ही नहीं उठा रहे, बल्कि इसके कारण भी वही हैं. साहूकारों को आमतौर पर उच्चवर्गीय हिंदू समुदाय का प्रतिनिधि माना जाता था. जैसे-जैसे मियो किसानों में उनके ख़िलाफ़ असंतोष बढ़ता गया, वे हिंदूवादी परंपराओं से भी दूर होने लगे और इस्लाम के प्रति उनके आकर्षण में लगातार वृद्धि होती गई. इसकी एक वजह और थी. मियो राजपूत समुदाय से संबंधित होने के कितने भी दावे क्यों न करें, साहूकार उनके इस दावे को नहीं मानते थे. और तो और, वे उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे और उन्हें नीची निगाहों से देखते थे. बदली हुई परिस्थितियों में मियो मुगल या अन्य मुस्लिम शासकों की बजाय उच्चवर्गीय हिंदुओं को अपने दुश्मन के रूप में देखने लगे. तबलीगी जमात में मियो समुदाय का प्रवेश इसी का एक नतीजा था. दरअसल अपनी सामुदायिक पहचान को मुस्लिमों के साथ जोड़ने के लिए यह उनकी एक सोची-समझी रणनीति थी.

सामाजिक विस्थापन ख़ुद किसी आंदोलन को जन्म नहीं देता. समुदाय से बाहर का कोई करिश्माई नेता भी आम लोगों को तब तक लामबंद नहीं कर सकता, जब तक कि समुदाय के अंदर के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी बातों को पसंद न करें और फिर उन्हें स्थानीय लोगों की भाषा में उन तक न पहुंचाएं. मेवात में तबलीगी जमात के नज़रिए से देखें तो यह काम इस्लामी मदरसों एवं प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ती संख्या ने किया. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से ही अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र वाले मेवाती इलाक़ों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे थे. इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम उर्दू था, क्योंकि इस भाषा में पाठ्य सामग्री बहुतायत में उपलब्ध थी. इसका परिणाम मियो समुदाय के बीच युवाओं के एक नए वर्ग के उदय के रूप में सामने आया, जो इस्लामिक साहित्य से भलीभांति परिचित था. 1910 के आते-आते प्राथमिक शिक्षा प्राप्त मियो युवाओं की संख्या इतनी हो चुकी थी कि इस इलाक़े में एक हाईस्कूल की मांग जोर पकड़ने लगी.

मेवात में पहले माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 1923 में गुड़गांव के नूह में हुई और इसका नामकरण इसके संस्थापक फ्रैंक ल्यूगार्ड ब्रायन के नाम पर ही किया गया था. ब्रायन गुड़गांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे. यहां से शिक्षा प्राप्त कई मियो युवा बाद के सालों में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के जामिया मिलिया एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी पहुंचे. मेवात में तबलीगी जमात की शुरुआत से पहले मुस्लिमों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका था, जो मुस्लिम भाईचारे और एकता की भावनाओं से वाक़िफ़ था. इसी वर्ग ने तबलीगी जमात के संदेश को आम मियो जनता के बीच फैलाने में अहम भूमिका निभाई. ख़ुद इलियास भी थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त इस समुदाय और ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में नंबरदार, जेलदार, मुंशी एवं चौधरी जैसे पदों पर कार्य कर रहे लोगों पर भरोसा करने लगे. इसके अलावा मदरसों में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी मेवात इलाक़े में तबलीगी जमात के संदेश को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इनके पास उच्चस्तरीय धर्म निरपेक्ष शिक्षा का नितांत अभाव था, ये तो इलाक़े में चल रहे इस्लामिक विद्यालयों से बाहर निकले थे. गौरतलब है कि इस समय तक मेवात इलाक़े में ऐसे शिक्षण संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही थी.

शिक्षा के प्रसार ने मियो समुदाय को एक नई पहचान देने का कार्य किया, सामाजिक स्तर पर उनकी कमज़ोर स्थिति से उन्हें रूबरू कराया एवं इस्लाम धर्म के साथ उनके रिश्ते को और मज़बूत बनाने में महती भूमिका निभाई. कलीमा के प्रति मियो लोगों की अनभिज्ञता की चर्चा करते हुए एक ब्रिटिश प्रशासक ने लिखा है, यह केवल अलवर और उसके आसपास के इलाक़ों के लिए ही सच है. ब्रिटिश प्रभाव वाले इलाक़ों में इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य मियो लोगों को इस्लामिक धार्मिक परंपराओं के ज़्यादा नज़दीक लाना है. (एसए हक 1972:105) अलवर के हिंदू राजा ने अपने इलाक़े के स्कूलों में उर्दू की बजाय हिंदी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया था. उस समय हिंदी भाषा में इस्लामिक साहित्य का नितांत अभाव था. इसकी वजह यह थी कि हिंदी को हिंदुओं की भाषा के रूप में देखा जाता था. इस तरह ब्रिटिश प्रभाव वाले इलाक़ों में रहने वाले मियो लोग हिंदू शासित अलवर और भरतपुर क्षेत्र के निवासी स्वजातीय लोगों के मुक़ाबले इस्लामिक विचारधारा से ज़्यादा परिचित हो चुके थे. बाद के सालों में गुड़गांव क्षेत्र में रहने वाले इन्हीं लोगों ने पूरे मेवात इलाक़े में तबलीगी जमात के संदेश के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाई.

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस के तीन चेहरे

26 अप्रैल-02 मई के अंक में प्रकाशित आवरण कथा-प्रियंका गांधी, कांग्रेस की आंधी पढ़ी. कांग्रेस के लिए तीन चेहरे वैसे भी महत्वपूर्ण हैं-सोनिया, राहुल एवं प्रियंका. इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता दलों से कहीं ज़्यादा उनके नेताओं को तवज्जो देती रही है. यह बात अलग है कि अक्सर वह इसी मोड़ पर धोखा भी खाती रही है. आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डालकर आलेख को रोचक बना दिया.

-रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

दुल्हनों का बाज़ार

बिमल राय का आलेख-पश्चिम बंगाल बना दुल्हनों का बाज़ार दिल को हिला देने वाला है. कितनी अजीब बात है कि एक ओर देश में महिला सशक्तिकरण का शोर है और वहीं दूसरी तरफ़ लड़कियां बेची-ख़रीदी जा रही हैं. सबसे ज़्यादा दु:खद यह कि शासन-प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी उदासीन है.

-मजहर अब्बास, *पीरागढ़ी, नई दिल्ली.*

ज्ञानवर्द्धक जानकारी

साइबर अपराध और साइबर कानून विषयक आलेख (26 अप्रैल-02 मई) काफी ज्ञानवर्द्धक है. लेखक ने विषय के हर बिंदु पर बख़ूबी प्रकाश डाला है. ऐसे आलेख पाठकों की जानकारियां बढ़ाते हैं. साइबर अपराध के मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं. ऐसे में इस तरह के आलेख हमारे लिए खासे मददगार साबित हो सकते हैं.

-संजीव निगम, *पन्ना, मध्य प्रदेश.*

गिरगिट

रंग पे रंग बदल जा गिरगिट,
मौक़ा देख फिसल जा गिरगिट.
जोड़-तोड़ से कुर्सी पाकर,
जिसको चाहे छल जा गिरगिट.
चाहे जैसी जांच चले फिर,
बच के राह निकल जा गिरगिट.
कुत्ता-बिल्ली भेष बनाकर,
संसद में तू चल जा गिरगिट.
जब पैसा ज़्यादा हो जाए,
सीटीलैंड से चल जा गिरगिट.
कांग्रेस अगर सीट न दे तो,
बीजेपी से दल जा गिरगिट.
बीजेपी अगर टिकट न दे तो,
और दलों संग पल जा गिरगिट.
भिखमंगों सा वोट मांगकर,
वादों से तू टल जा गिरगिट.
कुर्सी दो दिन की मेहमां है,
फिर हाथों को मल जा गिरगिट.
आख़िर कब तक दाल गलेगी,
खाया-पिया उगल जा गिरगिट.
बात कहे इक कवि आईना,
दीन-धरम में ढल जा गिरगिट.

-हलीम आईना, कोटा, राजस्थान.

बदहाल बुनकर

बनारसी साड़ी उद्योग से संबद्ध बुनकरों की हालत पढ़कर काफी दु:ख हुआ. मेहनतकश बुनकर दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पा रहे हैं, यह तो सरकार और समाज के लिए डूब मरने वाली बात है. मशीनों ने सदियों पुरानी हस्तकला के अस्तित्व पर ग्रहण सा लगा दिया है. वहीं बड़े व्यापारियों की मुनाफाखोरी ने इस आग में घी डालने का काम किया है. जरूरत इस बात की है कि बुनकरों की हालत पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए.

-एल के मीणा, *अजमेर, राजस्थान.*

ठगी का महामुकाबला

26 अप्रैल-02 मई के अंक में प्रकाशित छपा लेख-जनता को ठगने का महामुकाबला पढ़कर पता चला कि टीवी चैनलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दर्शकों यानी जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है. जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने और उसे आर्थिक हानि पहुंचाने वाले ऐसे चैनलों-कार्यक्रमों पर अविलंब प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

-सुष्मिता सिंह, *ई-मेल से.*

नक्सल समस्या और भारत

सौमित्र मोहन का आलेख-नक्सल समस्या: राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की जरूरत तथ्य एवं विचारपरक है. लेखक ने समस्या के स्थायी समाधान के ठोस उपाय सुझाए हैं. वास्तव में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास की जरूरत है. गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है. जब तक भरपेट भोजन, जरूरत भर कपड़ा और सिर छुपाने के लिए छत जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के प्रयास नहीं होंगे, अलगाववाद और बगावत को रोका नहीं जा सकेगा.

-लोकेंद्र कुमार, *रायपुर, छत्तीसगढ़.*

अख़बार नहीं मिलता

मैं चौथी दुनिया अखबार तबसे पढ़ता रहा हूं, जब यह बीस रुपये में मिला करता था. लेकिन, अब जबकि यह पांच रुपये में आ रहा है तो मुजफ्फपुर में सहज उपलब्ध नहीं है. इस ओर जरूर ध्यान दीजिए और स्थानीय खबरों के बारे में भी.

-गौरी शंकर (रुपौली), *रेवा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

प्रधानमंत्री जी, देश की ओर ईमानदारी से देखिए

लोकसभा और राज्यसभा में एक दिन का शोरशराबा और बात ख़त्म. केवल रस्म अदायगी हुई. एक पत्रिका ने छापा कि भारत सरकार की एक एजेंसी फोन टेप कर रही है. नाम आए, नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह के. पर यह सतही सच्चाई है. यह हमारा ध्यान बंटाने की सफल कोशिश हुई है. साजिश बहुत गहरी है, जिसके सिरे न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों तक पहुंचते हैं. हमने जनवरी में लिखा था कि पैंतीस लोग विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसी के निशाने पर हैं. इनमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के नेताओं के साथ कुछ जुझारू पत्रकारों के भी नाम हैं. इनकी साख ख़त्म करने की पूरी योजना बनाई जा चुकी है. अब इनसे जुड़ी झूठी कहानियों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे सामने एक नए खुलासे के रूप में पेश की जाएंगी. यह झूठ सच के नाम पर इस तरह से पेश होने वाला है कि लोगों के मन में संदेह पैदा कर दे.

इस सारी योजना का दु:खद पहलू यह है कि दो बड़ी विदेशी एजेंसियों की मदद हमारे देश के ही कुछ लोग कर रहे हैं, जिन्हें इसके बदले बड़ी रकम मिलती है. ये दो विदेशी एजेंसियां हैं सीआईए और मोसाद. दोनों ही भारत को पूरी तरह पश्चिमी देशों की पुलिस चौकी में तब्दील कर देना चाहती हैं. ये दोनों एजेंसियां भारतीय एजेंसियों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं और उन्हें समय-समय पर ख़ुफ़िया सूचनाएं भी उपलब्ध करा रही हैं. दोनों ने अपना कार्यक्षेत्र बांट रखा है. सीआईए चीन को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाती है, जबकि मोसाद पाकिस्तान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को ध्यान में रखकर. देश में होने वाले कई बम विस्फोट आतंकवादी करते हैं, लेकिन कई विस्फोट ये एजेंसियां भी कराती हैं.

एक प्रमुख ख़ुफ़िया अधिकारी ने बताया है कि मालेगांव विस्फोट सीआईए और मोसाद द्वारा प्रायोजित था. 12 अप्रैल 2008 को सीआईए और मोसाद ने भोपाल के श्रीराम मंदिर में एक मीटिंग भी की थी, जिसमें रॉ और आईबी के कई पूर्व और वर्तमान अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था. इसकी जानकारी उच्च ख़ुफ़िया अधिकारियों को है, लेकिन कितनी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी है, कहा नहीं जा सकता. कुछ पत्रकारों पर शक़ है कि वे सीआईए और मोसाद के लिए सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं. पत्रकार अगर अपने पेशे से गद्दारी करे तो अच्छा इन्फॉरमर बन जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच आसानी से सूचना और निर्णय करने वाले केंद्रों तक होती है. साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक के दरवाजे आसानी से पत्रकारों के लिए खुल जाते हैं.

उदाहरण भी है. सीआईए के लिए मुखबिरी करने वाले एक पत्रकार मैथ्यू रोज़ेनबर्ग, पाकिस्तान के संघ शासित स्वायत्त कबाइली क्षेत्र फाटा और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत एन डब्ल्यू एफपी के अधिकारियों कैप्टन हयात ख़ान एवं हबीब ख़ान के साथ सघन यात्रा पर गए थे. दरअसल मैथ्यू रोज़ेनबर्ग सीआईए के साथ मोसाद के भी एजेंट हैं. मैथ्यू ने सीआईए के लिए तालिबान आतंकवादियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान की भी मुखबिरी की थी. पाकिस्तान ने उन्हें चेतावनी भी दी थी, पर भारत में मैथ्यू के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां कई बड़े अधिकारी मैथ्यू की तरह ही एजेंट हैं. विदेशी अख़बारों में रिपोर्ट करने के नाम पर शातिर जासूसों का दल दिल्ली से अपनी गतिविधियां चला रहा है.

मोसाद का मानना है कि भारत में, ख़ासकर दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाक़ों की जमकर जासूसी होनी चाहिए. करोड़ों की मशीनें मंगाई गई हैं. ये मशीनें महंगी गाड़ियों में लगाई गई हैं तथा उन्हें जामिया, ओखला, पुरानी दिल्ली जैसे इलाक़ों में लगाया गया है. बहाना है कि आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ने का जाल बिछाया जा रहा है, पर इनका असल इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं की जासूसी में हो रहा है. मुस्लिम राजनीति करने वाले नेता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले ग़ैर मुस्लिम राजनीतिक नेता इस श्रेणी में आते हैं. नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह पर भी इसीलिए नज़र रखी गई. ख़ुफ़िया सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी भी नज़र के दायरे में हैं, क्योंकि ये विदेशी एजेंसियां चाहती हैं कि वे राहुल गांधी की कमज़ोरियां पकड़ें. इनका मानना है कि रात आठ बजे के बाद यदि राहुल गांधी की बातचीत या वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो राहुल गांधी की राजनीति भी इनके क़ब्ज़े में आ जाएगी.

लोकसभा में जब सरकार कहती है कि उसने टेलीफोन टेप करने का आदेश नहीं दिया तो वह सही कहती है. यह काम तो उसकी जानकारी के बिना विदेशी एजेंसियां कर रही हैं और समय-समय पर, ज़रूरत पड़ने पर भारतीय एजेंसियों को इन्हें मुहैया कराती रहती हैं. इन एजेंसियों के निशाने पर कोई भी राजनेता या पत्रकार हो, ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता, पर यहीं राहुल गांधी के कंप्यूटर का डाटा, उनके ईमेल, उनकी बातचीत कहीं और रिकॉर्ड हो रही हो तो?

लोकसभा में जब सरकार कहती है कि उसने टेलीफोन टेप करने का आदेश नहीं दिया तो वह सही कहती है. यह काम तो उसकी जानकारी के बिना विदेशी एजेंसियां कर रही हैं और समय-समय पर, ज़रूरत पड़ने पर भारतीय एजेंसियों को इन्हें मुहैया कराती रहती हैं. इन एजेंसियों के निशाने पर कोई भी राजनेता या पत्रकार हो, ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता, पर यहीं राहुल गांधी के कंप्यूटर का डाटा, उनके ईमेल, उनकी बातचीत कहीं और रिकॉर्ड हो रही हो तो? भारत सरकार को चाहिए कि वह राहुल गांधी को इस जासूसी से बचाए. इन एजेंसियों का मानना है कि भारत के होने वाले प्रधानमंत्री को अभी से अपने क़ब्ज़े में लेना चाहिए. आपके पास हाईटेक लैपटॉप हो, आपको पता न चले और आपकी तस्वीर रिकॉर्ड हो रही हो तो क्या करेंगे. भारत के अंदर ऐसे यंत्र, जिनसे तीन किलोमीटर के भीतर मोबाइल और लैंडलाइन की बात रिकॉर्ड हो जाए, लैपटॉप से वीडियो बन जाए, कार के अंदर बटन बराबर चिप लगाकर आपकी गतिविधियां रिकॉर्ड कर ली जाएं, मोसाद द्वारा ले आए गए हैं. ये सब इज़रायल के बने हैं. पाकिस्तान की सीमा पर लगा उपग्रह इज़रायली है, जो दावा तो करता है कि वह बकरी की गतिविधि भी पकड़ सकता है, पर घुसपैठिए हैं कि आए जा रहे हैं. दंतेवाड़ा में एक हज़ार से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और जवानों को मार देते हैं और ये उपग्रह कोई जानकारी नहीं देते.

इतना ही नहीं, हमारी रॉ का अफसर अमेरिका के लिए सालों जासूसी करता है और फिर वहीं भागकर बस जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते. माधुरी को पकड़ने में तीन साल लग जाते हैं. कुछ अफसरों का कहना है कि माधुरी को हमारी जांच एजेंसियों ने डबल एजेंट बनाया. उसने जो सूचनाएं दीं, हमने उनका फायदा नहीं उठाया, जबकि आईएसआई ने उन सूचनाओं पर अमल किया. हमारी एजेंसी समझ नहीं पाई कि कब माधुरी पूरी की पूरी आईएसआई की होकर रह गई. शर्म की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सीआरपीएफ के कैंपों पर छापा डाल रही है. उसे सूचना मिली है कि माओवादियों को हथियार और गोलियां इन कैंपों से ही जा रही हैं. जिस देश की पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और सेना से हथियार उनके दुश्मनों के पास जा रहे हों, और राजनीति करने वाले नेताओं और प्रशासन चलाने वाले नौकरशाहों को लज्जा न आए तो क्या कहें. सचमुच सिस्टम फेल हो रहा है.

ये कुछ घटनाएं हैं, जो हमें चेतावनी देती हैं. हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक कीजिए. घुन लग चुका है. कुछ तो देश के बारे में सोचिए, अन्यथा देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को सफलता मिल जाएगी. आख़िर अमल तो सरकार को ही करना है. देश की ओर ईमानदारी से देखिए प्रधानमंत्री जी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

जिहाद से इत्तिहाद तक

असगर अली इंजीनियर

जिहाद, एक ऐसा शब्द, जिसे हर अर्थ में ग़लत ही माना जाता है. और, यह 9/11 के हमले के बाद पश्चिमी देशों के लिए एक ख़ौफ़नाक शब्द बनकर रह गया है. पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान एवं इराक जैसे मुस्लिम देश आज हर पल आतंक के साये में जी रहे हैं. आलम यह है कि इन देशों में अक्सर हिंसा बेकाबू हो जाती है और ख़ुद मुस्लिम ही आतंकियों के निशाने पर हैं.

उलेमाओं ने आत्मघाती विस्फोट और आतंकवाद को इस्लाम के ख़िलाफ़ घोषित कर इसकी बार-बार कड़ी निंदा की है. विभिन्न इस्लामिक देशों के उलेमाओं ने कई बार सभाएं आयोजित करके यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. पिछले महीने सेनेगल से लेकर इंडोनेशिया तक के प्रमुख उलेमा तुर्की के मर्दीन में एकत्र हुए और उन्होंने मध्यकाल में इब्न तैमैया द्वारा जारी किए गए मर्दीन के फतवे को ख़ारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि नागरिक अधिकारों की अवधारणा पर आधारित वैश्वीकरण के इस युग में ऐसे फतवों का कोई औचित्य नहीं है.

ओसामा बिन लादेन ने आतंकी हमलों को तार्किक ठहराने के लिए मर्दीन के फतवे का सहारा लिया था. इसके ठीक बाद 12 अप्रैल को सउदी अरब के शीर्ष धार्मिक निकाय ने आतंकवाद की आलोचना की. इस निकाय ने हर तरह के आतंक के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया. यहां तक कि इसे आर्थिक मदद पहुंचाने वाले हर काम और इंसान को वीभत्स अपराध घोषित कर दिया. अब आतंकी इस्लाम के आधार पर अपनी कार्रवाइयों को सही नहीं ठहरा सकते. इसने आतंकियों के तर्क का मुख्य आधार ही ख़त्म कर दिया. हालांकि ऐसे फतवों का कितना असर होता है, यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. फिर भी, यह ऐसे मुसलमानों को आतंकियों के फंदे से वापस लौटाने में कारगर हो सकता है, जो धर्म के आधार पर आतंकियों की कार्रवाइयों को सही मानकर उनके चंगुल में फंस गए हैं. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.

अब हमें अपना ध्यान जिहाद से इत्तिहाद की ओर करना होगा. इत्तिहाद का मतलब है इस्लामिक देशों की समस्याओं को विचारशीलता के साथ समझना और फिर कुरान के सिद्धांतों के अनुरूप उनका समाधान तलाश करना. अल्लामा इक़बाल सहित कई इस्लामिक विद्वानों ने इत्तिहाद को इस्लाम एवं इस्लामिक क़ानून का सबसे प्रगतिशील पहलू माना है.

अब हमें अपना ध्यान जिहाद से इत्तिहाद की ओर करना होगा. इत्तिहाद का मतलब है इस्लामिक देशों की समस्याओं को विचारशीलता के साथ समझना और फिर कुरान के सिद्धांतों के अनुरूप उनका समाधान तलाश करना. अल्लामा इक़बाल सहित कई इस्लामिक विद्वानों ने इत्तिहाद को इस्लाम एवं इस्लामिक क़ानून का सबसे प्रगतिशील पहलू माना है. इस्लाम के शुरुआती दिनों से ही इत्तिहाद एक जीवनशैली के रूप में मौजूद रहा है. विद्वानों का मानना है कि 1258 में मुगलों द्वारा बगदाद को सत्ता से हटाए जाने के दौरान इसके दरवाज़े दुनिया के लिए बंद थे. हैरत की बात है कि इसके क़रीब पचास साल बाद इब्न तैमैया ने हनबली विचारधारा को परिभाषित करते हुए जिहाद के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया था. इस तरह इत्तिहाद के दरवाजे बंद थे तो उग्र जिहादी विचारधारा को पनपने का मौक़ा मिला.

अब जबकि आतंकवाद के नए अवतार के रूप में जिहाद की इस्लामिक देशों के सभी प्रमुख उलेमाओं द्वारा आलोचना की जा रही है, यही समय है कि इत्तिहाद को फिर से व्यवहार में लाया जाए और मुस्लिम समुदाय के सामने मौजूद तमाम क़ानूनी एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया जाए. खुला अंधानुकरण और निष्क्रियता इस्मालिक क़ानून के लिए अभिशाप बन चुके हैं. एक ओर जहां हमारे चारों ओर की दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हम अपने धार्मिक-क़ानूनी मामलों में अभी भी 1258 के पहले के न्यायविदों की ही नकल किए जा रहे हैं. हम नए नज़रिए से सोचने में अक्षम हो चुके हैं और न ही कुरान से प्रेरित होते हैं. हम केवल कुछ गिने-चुने इमामों एवं मध्यकालीन विद्वानों का ही उदाहरण पेश करते हैं, जो हमारे लिए पवित्र कुरान से भी ज़्यादा माननीय बन चुके हैं. एक नई विचारधारा को विकसित करने और इत्तिहाद के दरवाजे खोलने के लिए मैं कुछ आधारभूत बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं.

सबसे पहले, कुछ उलेमाओं एवं मुस्लिम बुद्धिजीवियों (ऐसे बहुत हैं, जो पारंपरिक इस्लामिक साहित्य के तफसीर, हदीथ व न्यायशास्त्र में प्रशिक्षित हैं और जो परिवर्तन चाहते हैं) को साहस दिखाना होगा और नए नज़रिए के विकास के लिए आगे आना होगा. उन शक्तिशाली निजी स्वार्थों को चुनौती देनी होगी, जो मौजूदा धार्मिक व्यवस्था पर क़ाबिज़ हैं और उसमें किसी भी बदलाव के ख़िलाफ़ हैं. दूसरी बात, हमें इस्लामिक क़ानून की सभी मौजूदा विचारधाराओं को तिलांजलि देते हुए एक नई एकीकृत विचारधारा का विकास करना होगा, जो सभी मुसलमानों के लिए एक समान रूप से लागू हो. इससे इस्लामी एकता के अब तक के खोखले नारे को भी मज़बूती मिलेगी. इसका मतलब यह नहीं है कि हम न्यायशास्त्र से संबंधित सभी मौजूदा विचारधाराओं को ख़ारिज कर दें, बल्कि कुरान की विचारधारा के अनुरूप इनमें से केवल उन्हीं बातों का चुनाव करें, जो श्रेष्ठ हैं. तीसरी बात यह कि हमें उन मुद्दों पर सर्वसम्मति (इज्मा) बनानी होगी, जो मौजूदा समय के लिहाज़ से मौजूं हैं. यदि इस्लाम की पहली तीन सदियों में उलेमा ऐसा कर सकते हैं, तो आज हम क्यों नहीं? पूर्व में उलेमाओं की इज्मा उनकी अपनी विचारधारा तक ही सीमित थी, लेकिन आज की वैश्वीकृत दुनिया में सभी विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए विस्तृत पैमाने पर सर्वसम्मति का विकास करना होगा. सूचना और दूरसंचार की आधुनिकतम तकनीकों ने इस काम को पहले ही आसान बना दिया है.

मध्ययुगीन इस्लामिक न्यायशास्त्र में उन्होंने तार्किक समानताओं और इज्मा का प्रयोग किया था. ज़ाहिर है, क़ानूनी समस्याओं के निदान के लिहाज़ से उक्त दोनों शब्द बौद्धिक आधार प्रदान करते रहे हैं. हम आज वैश्विक स्तर पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? शरिया क़ानून में जिसे आज नैसर्गिक माना जाता है, वह और कुछ नहीं, बल्कि कुछ स्थानीय परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. मुख्य रूप से अरब एवं पारसी संस्कृति से जुड़ी उक्त परंपराएं सदियों से मौजूद रही हैं. हमें इन सारे तत्वों से आगे जाकर सोचना होगा और कुरान की ही तर्ज़ पर शरिया क़ानून को मौजूदा समय के मुताबिक़ ढालते हुए एक व्यापक विचारधारा का विकास करना होगा. शरिया के स्रोतों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन शरिया क़ानून को बदलना ही होगा. इत्तिहाद और इज्मा के सिद्धांतों पर आधारित उक्त बदलाव ऐसे हों, जो आधुनिक दौर में मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें.

feedback@chauthiduniya.com

शोध के मुताबिक़, हरी चाय ग्लूकोमा और आंखों की बीमारियों के लिए काफी फ़ायदेमंद हो सकती है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी घोषणाएं कहां और क्यों गुम हो जाती हैं?

आमतौर पर एक सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कोई योजना बनाती है या उसकी घोषणा करती है और बाद की कोई सरकार आकर उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देती है. इसके अलावा कई मौक़ों पर (ख़ासकर किसी आपदा के वक़्त) सरकार की तरफ़ से मदद की घोषणा की जाती है, लेकिन वक़्त बीतने के साथ ही वह अपना वायदा भूल जाती है. ख़ासकर, चुनाव से ठीक पहले तो सत्ताधारी दल घोषणाओं की बौछार कर देता है और चुनाव ख़त्म होने के बाद अपनी घोषणाओं को भूल जाता है. ज़ाहिर है, उसके पीछे वोट की राजनीति अपना काम करती है. लेकिन, सवाल यह है कि आम आदमी क्या करता है? आख़िर यह कैसे संभव है कि सरकार अपने ही वायदों से मुकर जाए और आम आदमी ख़ामोशी से उसे स्वीकार भी कर ले. दरअसल, आम आदमी की ख़ामोशी ही सरकार या नेताओं को अपने वायदों, घोषणाओं या किसी स्वीकृत योजनाओं से पीछे हटने की ताक़त देती है. ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम सरकार से पूछें कि अमुक योजना को ठंडे बस्ते में आख़िर क्यों डाला गया, अमुक योजना के क्रियान्वयन में देरी क्यों हो रही है? वजह क्या है और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इस अंक में हम ऐसी ही एक सरकारी योजना के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसकी घोषणा हुए वर्षों बीत गए, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो सका है. करेली, मध्य प्रदेश से जितेंद्र गुप्ता ने हमें पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक सरकारी घोषणा से अवगत कराया है. मामला 40 साल पुराना और रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. 1960-70 के दौरान रेल मंत्रालय ने छिंदवाड़ा-करेली-सागर रेल लाइन का सर्वे कराया था. जितेंद्र गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक़, इस रेल लाइन की कुल लंबाई 245 किलोमीटर है और वर्ष 2000 में इस योजना के लिए 735 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक इस योजना पर अमल नहीं किया जा सका है. ज़ाहिर है, यह योजना ठंडे बस्ते में रख दी गई है. हम इस अंक में इसी मुद्दे से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल जितेंद्र गुप्ता कर सकते हैं.

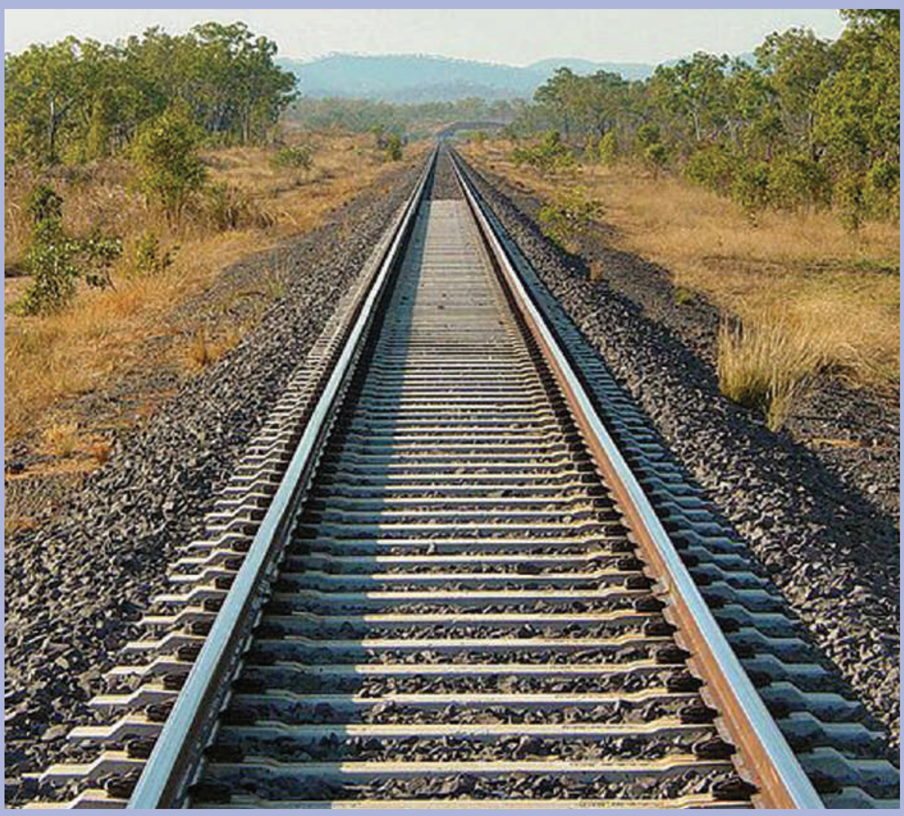

इसके अलावा इसी तरह के मिलते-जुलते मुद्दों पर अगर कोई व्यक्ति सरकार से सवाल पूछना चाहता है तो वह भी इस आवेदन का इस्तेमाल कर सकता है. इसके लिए सिर्फ़ आपको अपने विषय से संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग का पता बदल देना है. चौथी दुनिया सूचना क़ानून से जुड़ी आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

सरकारी योजनाओं की स्थिति जानने के लिए आरटीआई आवेदन (रेल मंत्रालय)

सेवा में, दिनांक....

लोक सूचना अधिकारी
एडवाइजर (पीजी) सह लोक सूचना अधिकारी-3
सेंट्रल कोऑर्डिनेशन
कमरा संख्या-471, चतुर्थ तल
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली.

विषय : सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

1960-70 के दशक में रेल मंत्रालय ने छिंदवाड़ा-करेली-सागर रेल लाइन का सर्वे कराया था, लेकिन अब तक इस योजना पर काम शुरू नहीं हो सका है. इस संबंध में कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं. (अगर इस मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज या अखबार में छपी खबर की कतरन हो तो उसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हुए इस आवेदन के साथ लगा सकते हैं)

1. क्या 1960-70 के दशक में रेल मंत्रालय ने छिंदवाड़ा-करेली-सागर रेल लाइन का सर्वे कराया था. यदि हां, तो उस सर्वे रिपोर्ट (निष्कर्ष) की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
2. सर्वे के बाद अब तक इस योजना/परियोजना पर केंद्र सरकार/रेल मंत्रालय की तरफ से क्या-क्या कार्रवाई की गई है? इसका संक्षिप्त विवरण दें.
3. क्या इस रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने अब तक किसी बजट का आवंटन किया है? यदि हां, तो कितना?
4. अब तक इस रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू न होने की वजह क्या है और इस रेल लाइन से जुड़ी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण दें.
5. प्रस्तावित रेल लाइन किन-किन मार्गों से होकर गुजरने वाली है? पूर्ण विवरण दें.

मैं इस आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम....
हस्ताक्षर....
पता....

ज़रा हट के

एक हरी चाय की प्याली हो...

अब आप बेड टी के तौर पर हरी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आंखों से संबंधित बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. यह हमारा नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है. तो फिर देर किस बात की, आप भी हरी चाय की प्याली को अपनी आदतों में शुमार कीजिए. शोध के मुताबिक़, हरी चाय ग्लूकोमा और आंखों की बीमारियों के लिए काफी फ़ायदेमंद हो सकती है. इसे एंटी ऑक्सिडेंट के तौर पर जाना जाता है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गजब की है. वैज्ञानिकों का शोध यह दर्शाता है कि लेंस, रेटिना एवं आंख के ऊतक कैसे इस तत्व को अवशोषित करते हैं.

ची पी पांग एवं उनके सहयोगियों ने इस हरी चाय में पाए जाने वाले तत्व को कैटिंस कहा है. इसमें बड़ी मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है, जो आंखों की रक्षा करता है. इसके अलावा इसमें काफी मात्रा में विटामिन-सी, विटामिन-ई और जिनेक्सथिन पाए जाते हैं. हालांकि अब भी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हरी चाय में जो कैटिंस पाया जाता है, वह पेट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से होकर आंख के ऊतकों तक पहुंचता है. विश्लेषण के बाद यह बात सामने आई कि आंखों की जो संरचना है, उसके लिए यह काफी उपयुक्त है. आंखें अधिक मात्रा में कैटिंस अवशोषित करती हैं. उदाहरण के तौर पर रेटिना काफी अधिक मात्रा में गैलोकैटीन अवशोषित करती है, जबकि एक्यूवेस ह्यूमर एपीगैलोकैटीन को अवशोषित करता है. हरी चाय में पाया जाने वाला कैटिंस 20 घंटे तक आंखों में होने वाले ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक़ , हरी चाय आंख के ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के लिए काफी लाभदायक है. यह शोध एग्रीकल्चर और फूड केमेस्ट्री नामक जरनल में प्रकाशित किया गया है.

पति को बेचने का विज्ञापन

यक़ीन नहीं होता, लेकिन बात सौ फ़ीसदी सच है. एक महिला ने अपने पति से आजिज आकर उसे बेचने का फ़ैसला किया है. उसने बाकायदा विज्ञापन भी दे दिया है. अब देखने वाली बात यह है कि उसे ख़रीदार कब मिलता है. वे जमाने लद गए, जब महिलाएं चाहरदीवारी में कैद रहती थीं. अब तो वे घर की ड्योढ़ी लांघ कर देश-दुनिया चला रही हैं. इस क्रम में अगर उन्हें किसी का दमन भी करना पड़े तो वे परहेज नहीं करेंगी. ऐसे ही एक मामले में एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर उसे बेचने का मन बना लिया है. लिहाज़ा विज्ञापन भी दे दिया. अब ज़रा सोचिए, उस पति पर क्या गुज़रती होगी, जिसे बेचने पर मोहतरमा आमादा हैं. हालांकि पति को बेचने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है. महिला का आरोप है कि उसका पति काम नहीं करता है. जबसे शादी हुई है, तबसे उसने किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की. सही बात है, नाकाम पति किस काम का! यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया निवासिनी इस महिला ने अपने पति को बेचने के लिए ईबे नामक ऑनलाइन वेबसाइट पर विज्ञापन दे दिया. समाचारपत्र हेराल्ड सन के मुताबिक़, सोनिया सिमेंस नामक यह महिला अपने 35 वर्षीय कवि पति से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि अपनी नाकामी के कारण उसके पति ने बेटे के जन्म के बाद परिवार की कोई आर्थिक मदद नहीं की. सोनिया ने पति की क़ीमत 25,000 डॉलर लगाई है. उसने वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन में लिखा है कि उसके पति कविता के माध्यम से एक भी पैसा नहीं कमा सके और यही कारण है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहती है.

राशिफल

दिल्ली, 10 मई-16 मई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार के सहयोग से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. परिवार में किसी नए सदस्य के आने की उम्मीद है. इसके अलावा आप क़रीबी लोगों के साथ घूमने जाने की भी योजना बना सकते हैं. आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): पुराने प्रोजेक्ट समय से पूरे हो जाएंगे और साथ ही नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बनी हुई है. हालांकि ख़र्च काफी होगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें. परिवार की महिला सदस्यों की ओर से मदद मिलेगी. यह सप्ताह आपके लिए नई ख़ुशियां लेकर आएगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून): कड़ी मेहनत और काफी कोशिशों के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है. बातचीत द्वारा अपने और लव पार्टनर के बीच लड़ाई ख़त्म करनी होगी. काम के सिलसिले में किसी अधीनस्थ कर्मचारी से बातचीत करेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): थोड़ी परेशानी के बाद व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी. व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फ़ायदेमंद साबित होगी. भावनात्मक समस्या से आर्थिक नुक़सान हो सकता है, अत: इस ओर विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. यात्रा करने से बचें, क्योंकि इसमें काफी ख़र्च होने के साथ-साथ असुविधा भी हो सकती है. परिवार की ओर से ख़ुश करने वाली ख़बरें मिलेंगी. आय के नए रास्ते बनेंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से फ़ायदा मिलेगा. कहीं घूमने जाने से ख़ुशी मिलेगी. अपने होम टाउन जाने से बचें, वरना बिना वजह तनाव होगा. पैसा समझदारी के साथ निवेश करें, फ़ायदा अवश्य होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): व्यवसायिक तौर पर आप थोड़ा अकेला महसूस करेंगे और अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करेंगे. परेशानियां दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत महसूस होगी. किसी क़रीबी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय बन सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): कुछ घटनाओं से आप व्यवसायिक जीवन में बेहद ख़ुश हो जाएंगे. फाइनेंस को बेहतर तरीक़े से मैनेज करें. मज़बूत इच्छाशक्ति की बदौलत आप इस हफ्ते अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे. किसी भी तरह की परेशानी से निपटने में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): स्वास्थ्य को लेकर काफी ख़र्च हो सकता है. अगर आपने इस ओर ध्यान न दिया तो समस्या बढ़ सकती है. इस सप्ताह कहीं दूर की यात्रा न करें तो बेहतर होगा. आपकी ज़्यादातर परेशानियां सप्ताह के अंत तक ख़त्म हो जाएंगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना आपको आंख, कान या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. परिवार की ख़ुशियां लौटने में अभी थोड़ा समय और लगेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. इस दौरान अपने काम के प्रति सचेत रहें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): आर्थिक फ़ायदे के योग हैं. आप कोई ज़मीन-जायदाद ख़रीदने की योजना बनाएंगे. किसी महिला का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. यात्रा के संबंध में विशेष सतर्कता बरतें. सप्ताह का अंत आते-आते समस्याएं कम होने लगेंगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): आपका स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. परिवार की परेशानियां चिंता बढ़ा सकती हैं. काफी समय से अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाने की संभावना है. परिवार में किसी मामले को लेकर तकरार हो सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

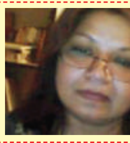

उसे अपनी नियति का पता था, फिर भी वह अपने पाकिस्तानी आकाओं का कहना मानती रही. और, उसकी गिरफ़्तारी इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय एवं देश के ख़ुफ़िया तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है

प्यार, पैसा और गद्दारी

पैसे का लोभ, ऊंचा उड़ने की हसरत और वासना की आग इंसान को क्या से क्या बना देती है. महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता इंसान ग़लत–सही के बीच का फ़र्क़ भूल जाता है और अक्सर कुछ ऐसा कर बैठता है, जिसे हम गद्दारी कहते हैं. माधुरी गुप्ता का गुनाह यही है. 53 साल की अधेड़ उम्र में शारीरिक और भौतिक सुखों की चाहत ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह दुश्मनों के इशारों पर नाचने लगी. वह देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां ऐसे लोगों तक पहुंचाने लगी, जो उसके हमवतनों के कातिल हैं. आईएसआई के डबल एजेंट मेजर राणा के प्यार का भूत इस कदर सवार हो गया कि माधुरी पाकिस्तान को ही अपना घर मानने लगी और इस्लाम को अपना मजहब. आज उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं, कोई गिला–शिकवा नहीं और न ही कोई डर.

मेजर राणा वर्ष 2007 से पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है. लेकिन राणा एवं माधुरी की प्रेम कहानी की शुरुआत इससे पहले ही हो चुकी थी, शायद तब, जबकि वह कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में थी. राणा से उसकी पहली मुलाकात एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कराई और फिर शुरू हुआ प्यार और सेक्स का ऐसा खेल, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था तक पर सवाल खड़े कर दिए. राणा के प्यार और पैसे के मोहपाश में बंधी माधुरी का देशप्रेम देशद्रोह में कब बदल गया, यह समझने के लिए न तो उसके पास समय था और न ही मानसिक शक्ति. कुआलालंपुर से भारत लौटने तक माधुरी राणा के प्रेम में इस तरह रच–बस चुकी थी कि पाकिस्तान जाने के लिए उसकी बेकरारी हर पल बढ़ती जा रही थी. उसने इसीलिए उर्दू सीखी, पाकिस्तान में अपनी पोस्टिंग के लिए आला अधिकारियों के सामने अर्जियां दीं और फिर जब वह पाकिस्तान पहुंची तो उनका प्यार परवान चढ़ने लगा. दोनों बराबर मिलने–जुलने लगे और फिर परतें उधड़ने लगीं, देश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर माधुरी के शरीर तक की.

माधुरी इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में प्रेस इंफॉर्मेशन डिवीज़न में ग्रेड बी अधिकारी थी और उसका मुख्य काम उर्दू अख़बारों में छपी भारत संबंधी ख़बरों पर नज़र रखना था. इस पद पर रहते हुए संवेदनशील जानकारियों तक उसकी पहुंच ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन शक़ की सुई तब घूमी, जब माधुरी दूसरे मामलों में भी दख़ल देने की कोशिश करने लगी. वह भारतीय दूतावास के अधिकारियों के विदेश दौरों के बारे में जानने की कोशिश में लगी रहती थी. अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय अभियान से जुड़ी हर सूचना वह अपने आशिक को देती थी, यहां तक कि काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में भी उसका हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. माधुरी अक्सर अकेले बाहर आती–जाती थी, जबकि पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों को देखते हुए वहां पदस्थापित भारतीय अधिकारी ऐसा जोखिम उठाने से बचते हैं. माधुरी का असल मकसद तो जिन्ना मार्केट की तंग गलियों में राणा से मिलना होता था, जहां वह पैसे की भूख के साथ ही अपनी हवस भी मिटाती थी.

इस्लामाबाद से दिल्ली पहुंचते ही माधुरी को जब पुलिस ने रोका तो उसके चेहरे पर ख़ौफ़ का नामोनिशान तक नहीं था. था तो सिर्फ़ आश्चर्य, इसलिए कि पकड़े जाने में इतनी देर कैसे हो गई. उसे अपनी नियति का पता था, फिर भी वह अपने पाकिस्तानी आकाओं का कहना मानती रही. और, उसकी गिरफ़्तारी इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय एवं देश के ख़ुफ़िया तंत्र के लिए एक बड़ा झटका है. रॉ के पाकिस्तान सहित कई देशों में अपने एजेंट हैं. यदि माधुरी के पास इन लोगों की कोई जानकारी रही होगी, तो वह निश्चित तौर पर अब तक न केवल उसे आईएसआई को दे चुकी होगी, बल्कि रॉ को अब अपना नेटवर्क दोबारा बनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं माधुरी से नज़दीकियों का फ़ायदा उठाकर आईएसआई ने उच्चायोग के अंदर कोई यंत्र न लगा रखा हो, जिससे सारी जानकारियां उन तक ख़ुद ही पहुंचती रहें. इतना ही नहीं, माधुरी अपनी सूचनाएं राणा के अलावा और किन लोगों तक पहुंचाती थी, यह भी जांच का विषय है. राणा के अलावा आईएसआई के एक और एजेंट के साथ संबंध होने की बात उसने ख़ुद कबूली है. सेना के एक शीर्ष अधिकारी और कश्मीर के एक डॉक्टर दंपत्ति के साथ उसके संबंधों की भी जांच हो रही है. शक़ के दायरे में इस्लामाबाद में रॉ के स्टेशन हेड आर के शर्मा भी हैं और विदेश एवं गृह मंत्रालय के कई शीर्ष अधिकारी भी.

जांच का विषय यह नहीं है कि माधुरी ने कौन–कौन सी जानकारियां राणा को दीं, बल्कि असल मुद्दा तो यह है कि इस काम में उसके साथ और कौन–कौन लोग शामिल थे. सरकार को यह भी जांच करनी चाहिए कि जब पिछले दो सालों से माधुरी इस काम में लगी थी तो अधिकारियों की नज़र उस पर कैसे नहीं पड़ी. राणा उससे मिलने कई बार भारतीय उच्चायोग में भी आता था. कभी पत्रकार बनकर तो कभी वीजा आवेदन के सिलसिले में. उच्चायोग की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वह बार–बार अंदर आने में कैसे सफल हुआ, सरकार को इसका भी जवाब तलाशना चाहिए. एक सवाल और, दुश्मनों के हनी ट्रैप में फंसने का माधुरी गुप्ता का यह मामला पहला नहीं है. जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर गोर्शकोव तक, ऐसे कई वाकये सामने आ चुके हैं, जब भारतीय अधिकारी रूप और पैसे के जाल में फंसकर देशद्रोह पर उतर आए हैं. आख़िर हमारे अधिकारियों की ट्रेनिंग इतनी कमज़ोर क्यों है कि वे देशहित की बजाय गद्दारी का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं.

आज माधुरी गुप्ता का नाम हर किसी की ज़ुबान पर है, लेकिन यदि इस मामले की पूरी जांच–पड़ताल न की गई तो कल एक और माधुरी गुप्ता पैदा हो जाएगी. इसमें कोई संदेह नहीं है. फिर कोई अपनी प्यास मिटाने के लिए अपने देशवासियों का ख़ून बहाने को तैयार हो जाएगा. वह यह भूल जाएगा कि उसकी सूचनाओं के बल पर आईएसआई जैसे संगठन दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और मुंबई से लेकर वाराणसी तक ख़ून की नदियां बहाने का ताना–बाना बुनते हैं. सरकार के पास आज मौक़ा है कि वह इन सभी सवालों के जवाब तलाशे, वरना कल कहीं देर न हो जाए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विश्व की कुख्यात महिला जासूस

माता हारी : पूरी दुनिया में महिला जासूसों की चर्चा होते ही माता हारी का नाम सबसे पहले आता है. 1876 में नीदरलैंड में जन्मी माता हारी का असली नाम गेरत्रुद मार्गरेट जेल था और पेशे से वह एक डांसर थी. भारतीय नृत्यों में भी वह पारंगत थी, लेकिन उसका असली पेशा अपने शरीर और अदाओं के सहारे बड़े लोगों की जासूसी करना था. कई देशों के शीर्ष सेना अधिकारियों, मंत्रियों, राजशाही के सदस्यों से उसके नज़दीकी रिश्ते थे और वह फ्रांस एवं जर्मनी दोनों की डबल एजेंट थी. 1917 में फ्रांस में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई.

मेलिता नारवुड : मेलिता नारवुड कहने को तो इंग्लैंड की प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थी, लेकिन उसका काम वहां रहकर सोवियत गुप्तचर संस्था केजीबी के लिए जासूसी करना था. कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति उसके झुकाव को भांपते हुए केजीबी ने 1940 के दशक में उसे अपना एजेंट नियुक्त कर लिया और शीतयुद्ध के दौरान अगले चार दशकों तक उसने कई अहम जानकारियां सोवियत अधिकारियों को उपलब्ध कराईं. एक गोपनीय परमाणु शोध संस्थान में काम करते हुए नारवुड के लिए संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन हैरत की बात यह है कि पकड़े जाने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया.

ब्रिटा टॉट : डेनमार्क में पैदा हुई ब्रिटा टॉट की शादी स्वीडन के राजपरिवार में हुई थी. इसके एक दशक बाद स्वीडन और डेनमार्क के बीच युद्ध शुरू हो गया और टॉट अपने जन्म के देश के लिए जासूसी करने लगी. महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियों के अलावा वह स्वीडन के राजा चार्ल्स 8 की हत्या की साजिश में भी शामिल थी. पकड़े जाने पर उसे पहले ज़िंदा जला देने का दंड दिया गया, लेकिन बाद में माफी देकर डेनमार्क वापस भेज दिया गया.

स्टीफेनी जूलियाना वान होहेनलोहे : बला की ख़ूबसूरत और जर्मनी में ऊंचे संपर्कों वाली स्टीफेनी लंदन में रहती थी और हिटलर के लिए जासूसी करती थी. वहां उसने इंग्लैंड के कई शीर्ष अधिकारियों, जिसमें राजशाही से लेकर कैबिनेट के सदस्य भी शामिल थे, को अपने रूप के जाल में फंसाया और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर उसे हिटलर तक पहुंचाया. दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद उसे लंदन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा.

एलिजाबेथ बेंटले : एलिजाबेथ बेंटले द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए जासूसी करती थी और नाज़ियों से जुड़ी अहम जानकारियां वहां तक पहुंचाती थी. हालांकि, अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद उसने अचानक ही रूस से अपने सारे संपर्क तोड़ लिए और अमेरिका को 150 से भी ज़्यादा सोवियत जासूसों के बारे में बताकर गुमनामी के अंधेरे में खो गई.

लोना कोहेन : लोना कोहेन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लंदन में रहते हुए अपने पति के साथ मिलकर सोवियत संघ के लिए जासूसी करती थी. कुख्यात पोर्टलैंड स्पाई रिंग के गठन में भी उसकी अहम भूमिका थी.

वर्जीनिया हॉल : इंग्लैंड के स्पेशल ऑपरेशंस एक्ज़ीक्यूटिव के एजेंट के रूप में काम करते हुए वर्जीनिया हॉल ने नाज़ियों के ख़िलाफ़ जासूसी करते हुए कई कारनामे किए. उसकी बहादुरी के किस्से अभी भी मशहूर हैं. कहा जाता है कि 1930 के आसपास ही उसका एक पैर कट चुका था, लेकिन 1944 में पकड़े जाने के डर से वह पैदल ही भागकर स्पेन पहुंच गई.

हेमाडपंत बोले, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. हो सकता है कि वह स्वयं न आएं और कोई अन्य स्वरूप धारण कर पधारें.

साई सार्वभौम हैं

वर्ष 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमाडपंत को एक स्वप्न आया. बाबा एक संन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमाडपंत को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहां भोजन करने आऊंगा, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें न तो बाबा और न ही कोई अन्य संन्यासी दिखाई दिया. वह अपनी स्मृति दौड़ाने लगे और अब उन्हें संन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो आई. यद्यपि वह बाबा के सानिध्य का लाभ गत सात वर्षों से उठा रहे थे और उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु यह आशा कभी न थी कि बाबा उनके घर आकर भोजन करके उन्हें कृतार्थ करेंगे. बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए वह अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक संन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहां पधारेंगे. इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना. उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की. जवाब में हेमाडपंत ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न के बारे में सब कुछ सच–सच बता दिया. तब वह संदेहपूर्वक पूछने लगीं कि क्या यह भी कभी संभव है कि बाबा शिरडी के उत्तम पकवान त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में रूखा–सूखा भोजन करने के लिए पधारेंगे. हेमाडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है. हो सकता है, वह स्वयं न आएं और कोई अन्य स्वरूप धारण कर पधारें. इसलिए थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है. इसके बाद भोजन की तैयारियां शुरू हो गईं. दो पंक्तियां बनाई गईं और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया. घर के सभी कुटुंबी–पुत्र, नाती, लड़कियां एवं दामाद आदि ने अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया. जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकतापूर्वक राह देख रहा था. जब मध्यान्ह हो गया और कोई भी न आया, तब द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई. अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है. वैश्वदेव (अग्नि) को औपचारिक आहुति देकर श्रीकृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया. फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट सुनाई पड़ी. हेमाडपंत ने शीघ्र उठकर सांकल खोली और दो व्यक्तियों को द्वार पर खड़े हुए पाया.

इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है तो उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं. आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं और अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए. इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे, ऐसा कहकर उन्होंने पुराने अख़बार में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाल उसे खोलकर मेज पर रख दिया. काग़ज़ के आवरण को ज्यों ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर आश्चर्य हुआ. बाबा का चित्र देखकर वह द्रवित हो गए. उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया. उनका मस्तक बाबा के श्रीचरणों में झुक गया. वह सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है. कौतूहलवश उन्होंने आगंतुकों से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहां से प्राप्त हुआ. जवाब मिला कि उन्होंने इसे एक दुकान से ख़रीदा था. इसका पूर्ण विवरण वे किसी अन्य मौक़े पर बताएंगे. उन्होंने कहा कि कृपया आप अब भोजन कीजिए, क्योंकि सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं. हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजनगृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया. सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया. चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होने लगी और आश्चर्य भी कि यह सब कैसे घटित हुआ. इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वप्न में दिए गए अपने वचन को पूर्ण किया.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज्ञानोदय

- दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते हैं, इसलिए सबके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए.

  -प्रेमचंद

- द्वेष बुद्धि को हम द्वेष से नहीं हटा सकते. प्रेम की शक्ति ही इसे मिटा सकती है.

  - आचार्य विनोबा

- केवल वही व्यक्ति बेकार नहीं, जो बैठा रहता है. बल्कि वह भी बेकार है, जिसकी योग्यता का पूर्ण लाभ नहीं लिया जाता .

  -सुकरात

- कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है, जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है.

  -सावरकर

- प्रलय होने पर समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति महाविपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते.

  -चाणक्य

- फूल चुनकर एकत्र करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में निरंतर फूल खिलते रहेंगे.

  -रवींद्र नाथ ठाकुर

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj

Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

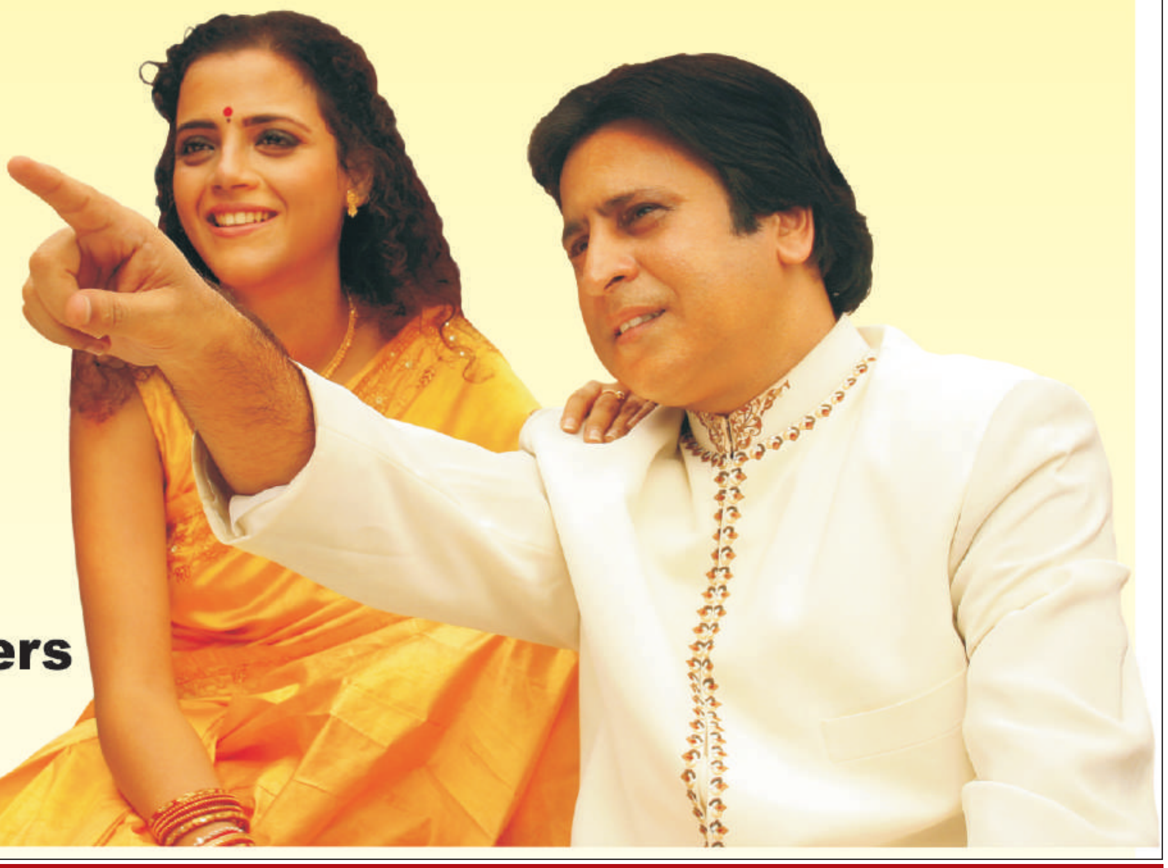

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

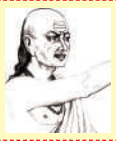

आचार्य चाणक्य एक ख़ास तरह के विचार की नुमाइंदगी करते हैं. उन्होंने जो विचार सदियों पहले रखे थे, वे आज भी समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखा रहे हैं.

शहादत से उठते सवाल

अनंत विजय

मुंबई पर आतंकवादी हमले के जख्म अभी हरे हैं. लगभग डेढ़ साल बाद तमाम जांच-पड़ताल के बावजूद मुंबई पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल अब भी मुंह बाए खड़े हैं. मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक काम्टे की पत्नी विनीता काम्टे की किताब *टू द लास्ट बुलेट* मुंबई पुलिस और उसके कुछ आला अफसरों पर संगीन इल्ज़ाम लगाती है. अपने पति की शहादत के बाद विनीता काम्टे ने उनकी मौत के बारे में तथ्यों की जांच-पड़ताल करना तय किया. उन्हें यह उम्मीद थी कि मुंबई पुलिस से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुंबई पुलिस ने तथ्यों को छुपाने और विनीता को परेशान करने की सारी कोशिशें कीं. संवेदनहीन मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि जिस अफसर ने अपनी ज़िम्मेदारियों से आगे जाकर पुलिस फोर्स और देश के लिए अपनी जान दे दी, उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए.

26 नवंबर की काली रात जब मुंबई पुलिस के तीन जांबाज़ अफसर-एटीएस चीफ हेमंत करकरे, पूर्वी ज़ोन के एडिशनल कमिश्नर अशोक काम्टे एवं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल की गोलियों के शिकार बने तो मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ़ से यह बात फैलाई गई कि वे तीनों हेडलेस चिकन की तरह मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे. इस वजह से वे आसानी से आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए. लेकिन, विनीता की किताब ने यह साबित किया है कि वे तीनों एक साथ नहीं थे और न ही बेवजह मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए आतंकवादियों का निशाना बने. अशोक काम्टे पूर्वी ज़ोन के इंचार्ज थे और जिस इलाक़े में आतंकवादियों ने हमला किया, वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था. किताब के मुताबिक़, अशोक काम्टे को यह निर्देश दिया गया कि वह स्पेशल ब्रांच के दफ्तर के क़रीब पहुंचें, जिसके पास की इमारत में आतंकवादियों के होने की आशंका थी. शुरुआत में तो हेमंत करकरे एवं विजय सालस्कर भी एक साथ नहीं थे. हेमंत करकरे को जब यह पता चला कि आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर हमला कर दिया है तो वह भी सीधे स्टेशन पर जा पहुंचे थे, जहां पहुंच कर उन्हें पता चला कि आतंकवादी कामा अस्पताल की तरफ़ चले गए हैं तो अस्पताल के पास पहुंच कर करकरे ने पुलिस कंट्रोल रूम को रात ग्यारह बजकर चौबीस मिनट पर रेडियो संदेश भेजा कि हम कामा अस्पताल पहुंच गए हैं. यहां फायरिंग और ग्रेनेड ब्लास्ट हो रहे हैं. हमें कामा अस्पताल को घेर लेना चाहिए. हम लोग एसबी-2 दफ्तर की तरफ़ हैं. एक पुलिस टीम को कामा अस्पताल के सामने की तरफ़ से भेजिए. इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामने की तरफ़ से भेजी जाने वाली फोर्स अपने सहयोगियों के साथ क्रॉस फायरिंग में न फंसे. साथ ही वहां मौजूद के एल प्रसाद से कहिए कि वह सेना से उनके कमांडो के लिए अनुरोध करें.

ग्यारह बजकर अट्ठाइस मिनट पर करकरे ने फिर से एक बार अपनी योजना कंट्रोल रूम को समझाई, जिसे कंट्रोल रूम ने ग्यारह बजकर तीस मिनट पर नोट करने का संदेश भेजा. यह वह वक़्त था, जब मुंबई पुलिस को इस बात का इल्म तक नहीं था कि यह आतंकी हमला है, लेकिन उस वक़्त के एटीएस चीफ करकरे ने इसे भांपते हुए न केवल आतंकवादियों को घेरने की योजना बना डाली, बल्कि आर्मी से कमांडो मंगवाने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया था. विनीता ने अपनी इस किताब में पुलिस

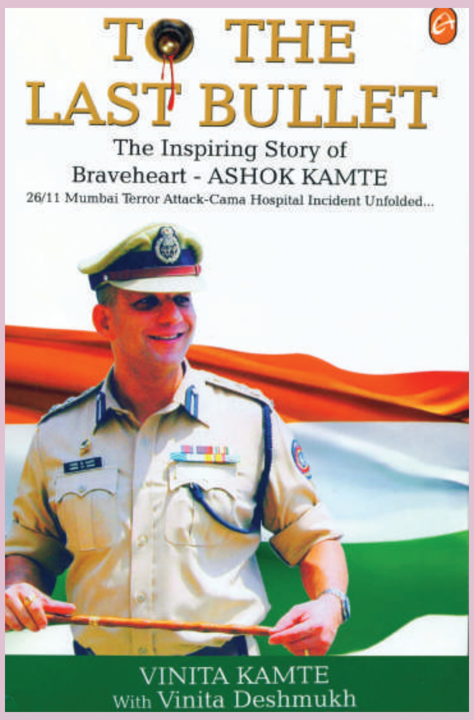

के लॉग रिकार्ड से यह साबित कर दिया कि करकरे की बात पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने सुनी ज़रूर, लेकिन उस पर न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई पुलिस फोर्स कामा अस्पताल के सामने की तरफ़ से भेजी गई. नतीजा यह हुआ कि आतंकवादी इस्माइल और अजमल कसाब फायरिंग करते हुए कामा अस्पताल के फ्रंट गेट से होते हुए रंग भवन लेन में पहुंच गए. रास्ते में उन दोनों आतंकवादियों ने एक होंडा सिटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, लेकिन कामा अस्पताल से दो मिनट की दूरी पर मौजूद पुलिस मुख्यालय से कोई रेस्पांस नहीं मिला. अगर यह बात सही है तो इस लापरवाही के लिए मुंबई पुलिस के ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए.

लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद काम्टे, सालस्कर और करकरे ने ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई. उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि करकरे के अनुरोध के बावजूद कंट्रोल रूम सो रहा है. जब रात के बारह बजकर एक मिनट पर तीनों जांबाज़ रंग भवन की तरफ़ से आगे बढ़े तो काम्टे ने सड़क के किनारे की झाड़ी में हलचल देखकर गाड़ी से ही पोजीशन लेकर अपनी एके-47 से उस दिशा में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें आतंकी कसाब जख्मी हुआ, जिसकी वजह से उसे पकड़ना आसान हो पाया. लेकिन आतंकी इस्माइल ने पोजीशन लेकर फायरिंग की और तीनों जांबाज़ों को अपनी गोलियों का शिकार बना लिया. आतंकवादियों ने तीनों जख्मी अफसरों को गाड़ी से खींचकर नीचे फेंक दिया और उनकी क्वालिस लेकर फरार हो गए. तीनों अफसर बारह बजकर चार मिनट से बारह बजकर उनचास मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे. अगर समय पर उन्हें इलाज मिल जाता तो बहुत संभव है कि वे बच जाते, क्योंकि चालीस मिनट बाद जब सालस्कर को अस्पताल ले जाया गया तो उनकी सांसें चल रही थीं. सवाल यह उठता है कि जब कंट्रोल रूम को मालूम था कि तीनों पुलिस अफसर कार्रवाई के लिए तैयार हैं तो उनकी योजना पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया. कंट्रोल रूम में तैनात अफसरों ने कामा अस्पताल के फ्रंट साइड से पुलिस फोर्स क्यों नहीं भेजी. कंट्रोल रूम ने अपनी लापरवाही से दोनों आतंकवादियों को न सिर्फ़ निकल जाने का मौक़ा दिया, बल्कि इसी लापरवाही ने तीन जांबाज़ अफसरों की जान भी ली. विनीता की अपने पति की मौत से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की राह में मुंबई पुलिस द्वारा रोड़े अटकाए गए, लेकिन सूचना के अधिकार ने मुंबई पुलिस को उस रात की बातचीत का ब्योरा देने पर मजबूर कर दिया, जिससे इन लापरवाहियों का राज खुला. इस पूरी किताब में उस वक़्त कंट्रोल रूम के इंचार्ज और अब महाराष्ट्र एटीएस के मुखिया राकेश मारिया पर भी संगीन इल्ज़ाम हैं. विनीता का कहना है कि मारिया ने बारह बजकर छप्पन मिनट पर पुलिस कमिश्नर से हुई बातचीत में करकरे की लोकेशन के बारे में अनभिज्ञता क्यों जताई, जबकि करकरे ने पुलिस कंट्रोल रूम को ग्यारह बजकर चौबीस मिनट पर ही अपने कामा अस्पताल के पास होने की सूचना दे दी थी. विनीता का दूसरा आरोप है कि मारिया ने इस बात से इंकार क्यों किया कि उसने ही काम्टे को कामा अस्पताल के पास बुलाया था, जबकि कॉल लॉग इस बात की चीख-चीखकर गवाही दे रहे हैं.

किताब के दूसरे हिस्से में अशोक काम्टे के करियर और उनके परिवार के बारे में विस्तार से लिखा है. काम्टे जहां भी गए, वहां पर उन्होंने अपनी जांबाज़ी और दिलेरी से लोगों का दिल जीत लिया. इस किताब से मुंबई पुलिस की संवेदनहीनता और एक महिला का अदम्य साहस सामने आता है, जिसने तमाम दिक़्क़तों और दु:ख के बावजूद न केवल एक लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने पति की बहादुरी और मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों की घोर लापरवाही से भी सबको अवगत कराया. हमले के दौरान मुंबई पुलिस की लापरवाहियों की जांच करने वाली राम प्रधान कमिटी की रिपोर्ट में उस वक़्त के कमिश्नर हसन गफूर की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन राकेश मारिया की भूमिका पर यह रिपोर्ट भी ख़ामोश है. क्या इन आरोपों की कभी जांच हो पाएगी. क्या सरकार में यह साहस है कि वह इन खामियों को उजागर करने में तत्परता दिखाए या फिर कमीशन और रिपोर्ट में उलझा कर इन नाकामियों को दबा दिया जाएगा. दूसरे की संभावना ज़्यादा है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

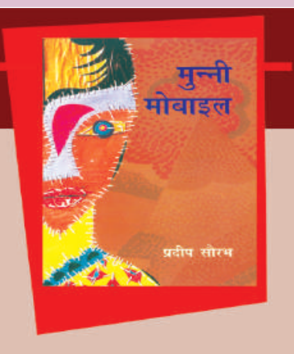

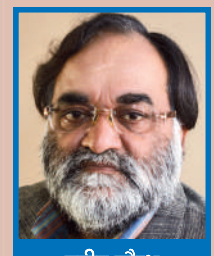

प्रदीप सौरभ

इस बीच एक प्रस्ताव आया. प्रस्ताव लाने वाले रेडियो में काम करने वाले उनके मित्र थे. बोले, तुम्हारी पत्नी तलाक चाहती है. तो इसमें समस्या क्या है? आनंद भारती बोले, तलाक का मुक़दमा तो कोर्ट में पेंडिंग है.

वह शादी में किए गए ख़र्चे की मांग कर रही है.

कितना मांग रही है?

बैठकर बात कर लो और मामले को ख़त्म करो, मित्र का जवाब था.

तुम ही तय कर बता दो, आनंद भारती इस पचड़े में अपनी तरफ़ से कोई पहल नहीं करना चाहते थे.

बात आई गई और ख़त्म हो गई. कुछ दिन बाद आनंद भारती के दोस्त का फोन आया, एक लाख की मांग आई है.

कोई बात नहीं, दे दूंगा. लेकिन उन्होंने शर्त रख दी, तलाक होने के बाद पैसे दूंगा. उससे पहले एक लाख का बैंक ड्राफ्ट बनाकर तुम्हारे पास जमा रहेगा. तलाक मिलने के बाद तुम बैंक ड्राफ्ट उसको दे देना. आनंद भारती इस पर कुछ जोड़-तोड़ नहीं करना चाहते थे. एक रिश्ता जो प्रेम और विश्वास की बुनियाद से शुरू हुआ था, वह उसकी नीलामी नहीं करना चाहते थे.

बात तय हो गई. कोर्ट में म्यूचुअल तलाक की अर्जी लगा दी गई. कुछ सप्ताह बाद कोर्ट में तारीख़ पड़ी. मजिस्ट्रेट ने दोनों से पूछा, आप लोग अलग रहने को तैयार हैं. कोई संभावना साथ रहने की नहीं है क्या? इस पर दोनों ने न की मुद्रा में सिर हिला दिया. मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिया. दोनों आज़ाद हो गए.

कैसी विडंबना थी और कोर्ट का कैसा रिवाज़ था कि कोर्ट के कर्मचारी दोनों को बधाई दे रहे थे. वे मिठाई के लिए पैसे मांग रहे थे. ढिठाई और बेहयाई का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इन क्लर्कों के लिए हर काम घूस और रिश्वत से इस कदर जुड़ा है कि संबंध बने या टूटे, उन्हें सिर्फ़ अपने रुपयों से मतलब होता है. यहां एक घर टूट गया है और उनके लिए यह टूटन भी बधाई का हिस्सा थी.

कोर्ट के बाहर आनंद भारती जब शिवानी से मिले तो दोनों की नज़रें एक पल के लिए ठहर गईं. आनंद भावुक हो गए थे और शिवानी की आंखों का सूनापन भी आनंद ने देख लिया था. आनंद शिवानी से कुछ कहना चाहते थे, पर यों ही खड़े रह गए थे. शिवानी को रेडियो के उनके

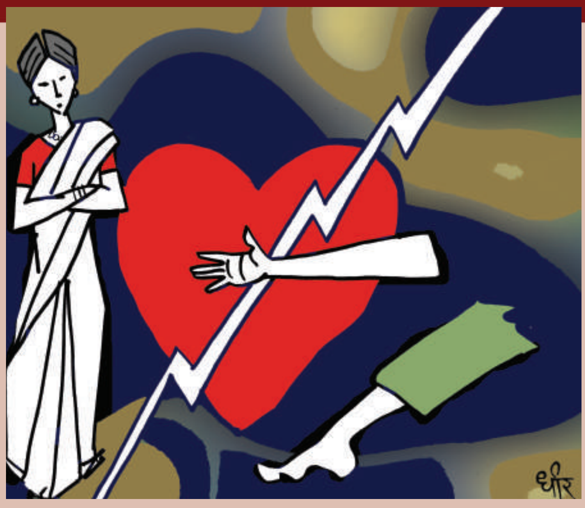

दोस्त से एक लाख का वह ड्राफ्ट लेकर कानपुर के लिए निकलना था. आनंद ने पुराने ख़ूबसूरत पलों की यादों से गीले हुए अपने मन को समझाते हुए शिवानी से कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हें रेडियो तक छोड़ सकता हूं. इतना वक़्त साथ गुजारा है, कुछ पल साथ चलोगी तो...शिवानी चुपचाप आकर आनंद की कार में बैठ गई. वह कार, जिसमें कभी उन दोनों का बराबर का अधिकार था और जिसमें वह कई बार इकट्ठे घूमा करते थे.

दोनों कार में बैठकर रेडियो की ओर रवाना हुए तो इंडिया गेट के पास पहुंच कर आनंद भारती ने अपनी कार किनारे खड़ी कर दी और शिवानी से कुछ पल यहां बैठने का आग्रह किया. आनंद भारती जब इंडिया गेट के लॉन पर शिवानी के साथ बैठे तो उनकी भावुकता आंखों की नमी में तब्दील हो गई थी. दोनों के बीच ख़ामोशी पसरी हुई थी. आनंद उसकी आंखों में झांकते हुए एकबारगी कह गए, शिवानी, हम काग़ज़ पर किए हस्ताक्षर के तहत भले ही अलग हो गए हैं, पर मैं आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं. सूफी का भविष्य बहुत क़ीमती है. कम से कम उसकी खातिर ही सही, तुम मेरे साथ अब भी चल सकती हो. सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा...

अगले अंक में जारी...

चाणक्य इस दौर में भी प्रासंगिक हैं

ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो इस बात पर चहक सकते हैं कि आख़िर आज भी आचार्य चाणक्य प्रासंगिक हैं. यह वही तबका है, जिसने 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद के भारत को ही असली भारत मान लिया है. जब उदारीकरण की बयार बही तो वह अपने साथ बेहतर जीडीपी आंकड़े और शेयर बाज़ारों में उछाल लेकर तो आई, लेकिन उसने भारत को अंदर से खोखला कर दिया. जिस इंडिया का निर्माण उसने किया, उसमें हर प्राचीन भारतीय विचार की अहमियत घटती गई और पश्चिमी विचार को ही सोलह आने सच मानकर लोग उस पर अमल करने लगे. दुर्भाग्यपूर्ण तो यह भी है कि लोग पहले दर्ज़े के हिंदुस्तानी बनने के बजाय दूसरे दर्ज़े के अमेरिकी बनने को ही अपना लक्ष्य मानने लगे. इस प्रक्रिया में कई भारतीय आदर्शों की तरफ़ से देश ने मुंह मोड़ा. लेकिन उदारीकरण के तक़रीबन दो दशक गुज़रने के बाद अब यह मालूम पड़ रहा है कि जिस व्यवस्था की नींव मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रखी थी, वह बिल्कुल खोखली है. देश और हर एक नागरिक के सामने आज समस्याओं का अंबार है. समाधान का रास्ता नहीं सूझ रहा है. ऐसी ही परिस्थिति में भारत के अपने मौलिक विचार प्रासंगिक हो जाते हैं.

आचार्य चाणक्य एक ख़ास तरह के विचार की नुमाइंदगी करते हैं. उन्होंने जो विचार सदियों पहले रखे थे, वे आज भी समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखा रहे हैं. हां, शर्त बस इतनी है कि कोई उनकी तरफ़ निगाह उठाकर देखना तो चाहे. आज जिस तरह से जीवन के तक़रीबन हर क्षेत्र में हर चीज उलझी हुई नज़र आ रही है, उसे सुलझाने में चाणक्य के विचार अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं. मालूम हो कि चाणक्य विशाल मगध राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे. उन्होंने चंद्रगुप्त को राज सिंहासन तक पहुंचाने का कार्य किया था. वह ऐसे अनोखे, अद्भुत और कुशल राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने मगध देश से नंद राजाओं की राजसत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी. चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, पर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की वजह से वह चाणक्य कहलाए. कुटिल राजनीतिक विशारद होने की वजह से उन्हें कौटिल्य भी कहा गया. चाणक्य की शिक्षा-दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी. चाणक्य और चंद्रगुप्त का एक ही समय है. यह समय है 325 ईस्वी पूर्व का. 325 ईस्वी पूर्व और 2010 के बीच सदियों का अंतर है, पर उस वक़्त चाणक्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, इसे एक उदाहरण के ज़रिए समझना ज़्यादा आसान है. चाणक्य के मुताबिक़, आदर्श राज्य संस्था वही है, जिसकी योजनाएं प्रजा को उसकी भूमि, धन-धन्यादि पाते रहने के मूलाधिकार से वंचित करने वाली न हों और उसे लंबी-चौड़ी योजनाओं के नाम से कर-भार से आक्रांत न कर डालें. वह कहते हैं कि देश

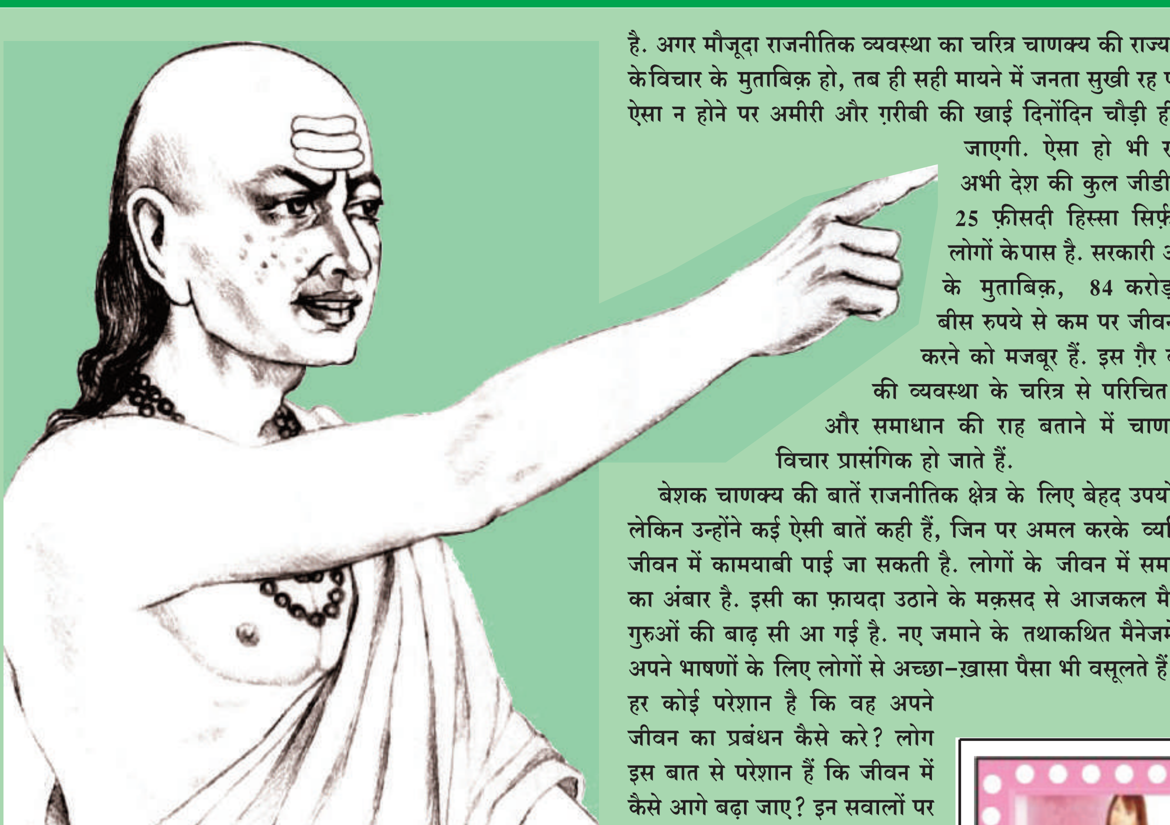

के विकास की योजनाएं राजकीय व्यय में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए. राजा के लिए एक हिस्सा सुनिश्चित करके प्रजा के टुकड़ों के भरोसे लंबी-चौड़ी योजना छेड़ बैठने को वह प्रजा का उत्पीड़न मानते थे.

चाणक्य के इन विचारों के संदर्भ में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो उनकी प्रासंगिकता ख़ुद-बख़ुद स्पष्ट हो जाती है. मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था नीतियों का निर्धारण प्रजा को ध्यान में रखकर नहीं कर रही है, बल्कि कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर कर रही है. आम लोगों पर रोज नए-नए कर लादे जा रहे हैं. विकास योजनाओं के नाम पर लोगों का शोषण ख़ुद सरकार कर रही है. दिल्ली में इस साल राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है. इस पर अरबों रुपये ख़र्च हो रहे हैं. इस ख़र्च को जुटाने के मक़सद से दिल्ली सरकार यहां की जनता पर तरह-तरह से जुल्म कर रही है. बिजली और पानी की क़ीमत बढ़ा रही है, बस के किराए बढ़ा रही है. नए-नए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के ज़रिए जनता से वसूली कर रही है. चाणक्य के शब्दों में यह प्रजा का उत्पीड़न है. अगर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र चाणक्य की राज्य संस्था के विचार के मुताबिक़ हो, तब ही सही मायने में जनता सुखी रह पाएगी. ऐसा न होने पर अमीरी और ग़रीबी की खाई दिनोंदिन चौड़ी ही होती जाएगी. ऐसा हो भी रहा है. अभी देश की कुल जीडीपी का 25 फ़ीसदी हिस्सा सिर्फ़ 100 लोगों के पास है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, 84 करोड़ लोग बीस रुपये से कम पर जीवन बसर करने को मजबूर हैं. इस ग़ैर बराबरी की व्यवस्था के चरित्र से परिचित कराने और समाधान की राह बताने में चाणक्य के विचार प्रासंगिक हो जाते हैं.

बेशक चाणक्य की बातें राजनीतिक क्षेत्र के लिए बेहद उपयोगी हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं, जिन पर अमल करके व्यक्तिगत जीवन में कामयाबी पाई जा सकती है. लोगों के जीवन में समस्याओं का अंबार है. इसी का फ़ायदा उठाने के मक़सद से आजकल मैनेजमेंट गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है. नए जमाने के तथाकथित मैनेजमेंट गुरु अपने भाषणों के लिए लोगों से अच्छा-ख़ासा पैसा भी वसूलते हैं. आज हर कोई परेशान है कि वह अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करे? लोग इस बात से परेशान हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए? इन सवालों पर परेशान होने के बजाय समस्याओं का हल तलाशने की ज़रूरत है और यहीं पर आचार्य चाणक्य इस दौर में भी प्रासंगिक लगने लगते हैं. वह कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि जो भी महान हुआ है, वह बहुत बड़ा भविष्यदृष्टा रहा है. आचार्य चाणक्य के साथ भी ऐसा ही है. उन्होंने जो बातें कही हैं, वे उस वक़्त भी उतनी ही प्रासंगिक थीं, जितनी आज हैं. अगर गंभीरता और गहराई के साथ चाणक्य के विचारों को समझा जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके विचार आज से हज़ार साल बाद भी इतने ही प्रासंगिक होंगे. ऐसा भी नहीं है कि लोग आचार्य चाणक्य के विचारों की प्रासंगिकता से बेख़बर हैं. लोग उनके विचारों को समझते हैं. यही वजह है कि साल 2009-10 का पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तीन बार आचार्य चाणक्य के कथन का उल्लेख किया. उन्होंने इसके ज़रिए यह बताने का प्रयास किया कि आर्थिक नीतियों को तैयार करने में आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा ली गई. हालांकि उनकी नीतियों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि चाणक्य के किसी विचार के आधार पर उन्होंने नीतियों का निर्धारण किया है. चाणक्य की जिस राज्य व्यवस्था की अवधारणा की चर्चा पहले की गई है, उस पर तो प्रणब मुखर्जी का बजट पूरी तरह ख़ारिज हो जाता है.

बहरहाल, चाणक्य की प्रासंगिकता की बात करते हुए इस दौर की बुनियादी इंसानी प्रवृत्ति पर विचार करना बेहद ज़रूरी है. अक्सर होता यह है कि हम अपने पास की चीज को छोड़ देते हैं और दूर की चीजों के दीवाने हो जाते हैं. विदेशियों के विचारों की मिसाल अक्सर दी जाती है, लेकिन देशी विद्वानों की उतनी चर्चा नहीं होती है. सही मायने में कहा जाए तो आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे पुराने मैनेजमेंट गुरु थे. उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के प्रबंधन का रास्ता सुझाया.

हिमांशु शेखर
feedback@chauthiduniya.com

धूल, धूप और गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं आंखें. लेकिन, आप उचित देखभाल के ज़रिए आंखों को किसी भी नुक़सान से बचा सकते हैं.

दिल्ली, 10 मई-16 मई 2010 चौथी दुनिया

तकनीक की नई मंज़िल

एक जमाना था, जब मूक फ़िल्में बना करती थीं. इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट और फिर आधुनिक तकनीक ने रंगीन फ़िल्में देखने का मौक़ा दिया. वर्तमान में 3-डी तकनीक की बदौलत फ़िल्म देखने का नया और अद्‌भुत अनुभव मिल रहा है. इस पर ग़ौर करते हुए सैमसंग ने बीडीसी 6900 ब्लू-रे प्लेयर लांच किया है, जो अब 3-डी फुल एचडी प्ले बैक की सुविधा सीधे आपके घर में पहुंचाएगा. यह प्लेयर सैमसंग के 3-डी इको सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें पहले से 3-डी एचडीटीवी रेंज, 3-डी एक्टिव ग्लासेज़ और 3-डी कंटेंट शामिल हैं. इसके ज़रिए अब आप 3-डी पिक्चर क्वालिटी, उन्नत कनेक्टिविटी और जोरदार सराउंड साउंड की सुविधा पा सकते हैं.

स्लीक और स्टाइलिश सैमसंग बीडीसी 6900 मल्टी कोडेक है यानी यह डिव एक्स, डब्ल्यूएमए, डब्ल्यूएमवी, एचडी-जेपेग, एमकेवी एवं एमपी-4 जैसे सभी फॉर्मेट प्ले कर सकता है. ऊपरी हिस्से में लगा स्पर्श संवेदी कंट्रोल इसे अल्ट्रा स्लीक बनाता है. सैमसंग

वर्तमान में 3-डी तकनीक की बदौलत फ़िल्म देखने का नया और अद्‌भुत अनुभव मिल रहा है. इस पर ग़ौर करते हुए सैमसंग ने बीडीसी 6900 ब्लू-रे प्लेयर लांच किया है, जो अब 3-डी फुल एचडी प्ले बैक की सुविधा सीधे आपके घर में पहुंचाएगा.

बीडीसी-6900 के पिछले भाग में लगे कंपोनेंट आउटपुट की बदौलत एकदम स्पष्ट, साफ-सुथरी एवं उत्तम तस्वीरें मिलती हैं. इसके अगले भाग में एक यूएसबी पोर्ट भी लगा है. इसमें एचडीएमआई वर्जन 1.4 वीडियो आउटपुट है, जो 3-डी प्ले बैक को सपोर्ट करता है.

सैमसंग बीडीसी-6900 में 7.1 चैनल एनालॉग आउटपुट है. साथ ही इंटरनल ऑडियो डिकोडर-जैसे डॉल्बी ट्रूएचडी, डॉल्बी डिजिटल एवं डीटीएच-एचडी और डॉल्बी डिजिटल प्लस भी. इससे शानदार मल्टी चैनल एचडी सराउंड साउंड मिलता है और विजुअल इमेज बेहतर बनती है.

सैमसंग बीडीसी-6900 में बिल्ट इन वाइ-फाइ सपोर्ट और इंटरनेट टीवी का नवीनतम संस्करण उपलब्ध है. इससे वेब की बेहतरीन सुविधाएं, डाउन लोडेबल विजेट्स, ब्लॉकबस्टर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, फ्लिकर एवं पैंडोरा जैसे एप्लीकेशनंस सीधे आपके एचडीटीवी पर उपलब्ध होते हैं. आप इस पर तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, यार-दोस्तों से संपर्क बना सकते हैं और डिजिटल कंटेंट को महज़ एक बटन दबाकर पा सकते हैं. सुविधाजनक 1 जीबी इंटरनल मेमोरी में कंटेंट भी स्टोर किया जा सकता है. इसमें ऑलशेयर के मेल से डीएलएनए उपकरणों पर कंटेंट की आसानी से स्ट्रीमिंग की जा सकती है. आप अपने पीसी या मोबाइल पर स्टोर फाइलों को टीवी पर भी देख सकते हैं. सैमसंग बीडीसी-6900 देश भर में सैमसंग डिजिटल प्लाज़ा और अधिकृत खुदरा दुकानों पर उपलब्ध है. क़ीमत है सिर्फ़ 29,990 रुपये.

गोरे मुखड़े पर काला चश्मा

बदलते मौसम के साथ स्टाइल और पहनावा भी बदलता रहता है. गर्मियां मीठे आम के साथ सूर्य की तेज़ किरणों की रोशनी भी लाई हैं. इस मौसम में धूल, धूप और गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं आंखें. लेकिन, आप उचित देखभाल के ज़रिए आंखों को किसी भी नुक़सान से बचा सकते हैं. जब बात आंखों की देखभाल की हो तो सनग्लासेज का नाम सबसे पहले आता है, जो न सिर्फ़ आंखों की रक्षा करते हैं, बल्कि उनकी ख़ूबसूरती में चार चांद भी लगाते हैं. यानी स्टाइल और सुरक्षा एक साथ. रिलायंस रिटेल एवं पर्ल यूरोप की साझीदारी में शुरू हुई वीजन एक्सप्रेस कंपनी ने भारत में यूरोपियन समर सनग्लास कलेक्शन की 280 लेटेस्ट डिज़ाइन पेश किए हैं. कंपनी ने इस बात का ख़ास ध्यान रखा है कि इस रेंज के डिज़ाइन इंटरनेशनल मार्केट को प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए. इस रेंज के सनग्लासेज स्टाइलिश एवं बेहतरीन क्वालिटी के हैं और आंखों की रक्षा करते हैं. युवाओं में फैशन के क्रेज़ को देखते हुए इसे ऐसा बनाया गया है कि यह उन्हें स्मार्ट और मॉडर्न लुक दे सके. इनके शेप और साइज़ सिंपल और स्पोर्टी लुक देने के साथ ही ख़ूबसूरत हैं. प्लास्टिक फ्रेम में इसके स्टाइल को क्लासिक रूप दिया गया है और मेटल फ्रेम में इसे डिज़ाइन कर मॉडर्न लुक. इसमें लगे पोलोराइज्ड लेंस की वजह से धूप में भी साफ़ दिखाई देता है. इन आकर्षक सनग्लासेज की क़ीमत 399 रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके पोलोराइज़्ड वर्जन की क़ीमत 699 रुपये से.

फोन एक और नंबर दो

मोबाइल कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्द्धा के कारण आए दिन नए-नए फीचर्स के साथ अपने हैंडसेट बाज़ार में उतारती रहती हैं. उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए वे मोबाइल के डिज़ाइन, फीचर और रेंज में बदलाव करती रहती हैं, जिसका फ़ायदा उपभोक्ता को होता है. उसे कम दाम में बेहतरीन हैंडसेट मिल जाता है.

भारत की हैंडसेट निर्माता कंपनी ज़ैन मोबाइल्स ने एक्स- 220 के नाम से नया आकर्षक डिज़ाइन वाला फोन मार्केट में उतारा है. यह फोन न सिर्फ़ ख़ूबसूरत है, बल्कि इस्तेमाल में भी आसान है. इसके अलावा यह आजकल की ज़रूरतों को भी पूरा करता है. लांचिंग के मौक़े पर ज़ैन मोबाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश गुप्ता ने बताया कि एक्स-220 न सिर्फ़ स्टाइलिश है, बल्कि इसमें मौजूद तकनीक भी अच्छी है. कई प्रकार के विशेष फीचर्स से लैस होने के बावजूद इसका मूल्य काफी कम है. इस फोन में वीजीए कैमरा एवं 4-जीबी तक बढ़ाई जा सकने वाली मेमोरी है. इसमें मुलाकात, जन्मदिन और किसी ख़ास काम को करने के लिए आप रिमाइंडर लगा सकते हैं और ताज़ातरीन घटनाओं के नोट्स भी रख सकते हैं. एक्स-220 में 4 घंटों का टॉकटाइम देने की क्षमता है और वायरलेस एफएम की सुविधा है, जो एमपी थ्री साउंड क्वालिटी देता है. मोबाइल का एक्स फैक्ट है इसका डुअल कवर सिस्टम, जिसके ज़रिए अपने स्टाइल के अनुरूप यूजर्स लाल और काले रंग के दो कवर एक साथ लगा सकते हैं. मल्टी मीडिया विशेषताओं से लैस इस डुअल जीएसएम सिम फोन की क़ीमत कंपनी ने भारतीय बाज़ार में 1849 रुपये रखी गई है.

पैंटालून फेमिना मिस इंडिया 2010 के कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगियों के साथ अनुपम खेर, विपुल शाह एवं मधुर भंडारकर.

ख़ूबसूरत डिनर सेट इंडियाना

किसी भी चीज़ की अच्छी प्रस्तुति उसे और भी रुचिकर बनाती है. डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट खाना हो, वह भी किसी ख़ूबसूरत डिनर सेट में परोसा हुआ, तो भूख ख़ुद-बख़ुद बढ़ जाती है. खाना सादा हो या मसालेदार, ख़ूबसूरत डिनर सेट उसके प्रति आपकी दिलचस्पी ज़रूर बढ़ा देता है. खाने के शौक़ीन भारतीयों के लिए थाईलैंड की ट्रेडिंग कंपनी श्रीथाई सुपर वेयर इंडिया ने भारत के शहरी खानपान की संस्कृति को पुन: परिभाषित करने के लिए लाइफ स्टाइल मैलमीन वेयर रेंज के तहत इंडियाना डिनर सेट बाज़ार में उतारा है. इंडियाना वास्तव में कला का एक बेहतरीन नमूना है. इस डिनर सेट के रंग एवं डिज़ाइन इस तरह से संयोजित किए गए हैं कि इसमें भोजन और भी स्वादिष्ट प्रतीत होता है. यह 100 प्रतिशत शुद्ध मलमीन से बनाया गया है. इसे सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए गए रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं और भोजन के संपर्क में आने पर ख़राब भी नहीं होते. इस डिनर सेट की ख़ासियत यह है कि इसमें खाना देर तक गर्म रहता है. यह टूटता या दरकता नहीं है और इसे माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 22 एवं 32 पीस के सेट में उपलब्ध इस डिनर सेट की क़ीमत क्रमश: 4250 एवं 5750 रुपये है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मारुति की नई वैगन आर

देश में एसयुवी कारों की बिक्री का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. विदेशी कंपनियों द्वारा छोटी कारों के नए-नए मॉडल भारतीय बाज़ार में पेश किए जा रहे हैं. ऐसे में स्वदेशी कंपनियां भला कैसे पीछे रहतीं. इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया ने भारत स्टेज-4 मानक वाले के-सीरीज़ के इंजन से लैस अपनी छोटी वैगन आर का नया संस्करण पेश किया है. पहले से आकर्षक दिखने वाली नई वैगन आर का इंजन मौजूदा मॉडल से हल्का होगा. इसकी क़ीमत 3.28 लाख से लेकर 3.81 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी का दावा है कि यह पहले से बेहतर यानी 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. जापान में इस्तेमाल किए जा रहे नवीनतम ढांचे पर तैयार की गई नई वैगन आर बीएस-4 प्रदूषण नियंत्रण मानक वाली है और इसमें 998 सीसी का इंजन है. 1999 में उतारी गई वैगन आर की 8.8 लाख कारें बिक चुकी हैं. कंपनी पुरानी सीरीज़ की कार का उत्पादन धीरे-धीरे बंद कर देगी. कंपनी के मार्केटिंग प्रमुख मयंक पारिख ने कहा कि ग्राहकों की पसंद बदल रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मारुति सुज़ुकी अपने उत्पादों को अपग्रेड कर रही है और इसी क्रम में नई वैगन आर पेश की गई है. यह जनरल मोटर्स की शेवरले बीट, फोर्ड की फिगो और ह्युंदे की आई-10 को टक्कर देगी, क्योंकि इन सबकी क़ीमत नई वैगन आर की क़ीमत के लगभग ही है. कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिंजो नाकानीशी ने कहा कि वैगन को नए रूप में पेश करना कंपनी का एक अहम फ़ैसला है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या लीग से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए अकेले ललित मोदी ही दोषी हैं या फिर बोर्ड की भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है?

लीपापोती की तैयारी शुरू

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का तीसरा सत्र ख़त्म हो चुका है, लेकिन लीग से जुड़े विवादों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. कोच्चि टीम की फ्रेंचाइजी को लेकर शुरू हुए ताज़ा विवाद ने पहले केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर की बलि ली तो भ्रष्टाचार और सट्टेबाज़ी के आरोपों के मद्देनज़र 25 अप्रैल को फाइनल मुक़ाबले के ठीक बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के कमिश्नर एवं चेयरमैन ललित मोदी को निलंबित करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. उसके अगले ही दिन चिरायु अमीन को लीग का नया अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया. इसके साथ-साथ तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जो अगले सत्र के लिए लीग की तैयारियों की देखरेख करेगी. फ़िलहाल आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय लीग की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज़ों की जांच-पड़ताल कर रहा है, लेकिन बोर्ड के रुख़ को देखकर यह नहीं लगता कि वह लीग में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के प्रति वाकई गंभीर है. नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जांच से पहले ही बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि पवार के साथ-साथ कई और राजनीतिज्ञों के ख़िलाफ़ तमाम तरह के आरोप सामने आए हैं.

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या लीग से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए अकेले ललित मोदी ही दोषी हैं या फिर बोर्ड की भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है? लीग के कामकाज की देखरेख के लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई थी और नियमों के मुताबिक़, लीग से जुड़े हर मामले पर आख़िरी फ़ैसला लेने का अधिकार इसी के पास था. इसके सदस्यों में बीसीसीआई के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों एवं पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया था. पिछले तीन सालों के दौरान उक्त सभी लोग मोदी के हर फ़ैसले की तारीफ़ में कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन आज जब घपलों की पोल खुलती नज़र आ रही है तो वे अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं. कई सदस्यों ने तो खुलकर कह दिया है कि लीग के अधिकतर फ़ैसले मोदी अकेले ही लिया करते थे और उन्हें कई बार इसकी जानकारी मीडिया से मिलती थी. यदि ऐसा है तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया?

इसी तरह बीसीसीआई द्वारा लीग के नए चेयरमैन की नियुक्ति और तीन सदस्यीय अंतरिम समिति के गठन पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं. नए चेयरमैन चिरायु अमीन लंबे समय से क्रिकेट प्रशासन से जुड़े हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष होने के अलावा वह बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. अमीन पूर्ववर्ती गवर्निंग काउंसिल में भी शामिल रहे हैं और लीग की हर गतिविधि में उनकी भागीदारी रही है. ऐसे में उनके चेयरमैन रहते जांच प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता रह पाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है. लीग की अंतरिम समिति में शामिल किए गए लोगों के ख़िलाफ़ भी यही तर्क दिया जा सकता है. नई समिति के सदस्य रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर एवं मंसूर अली ख़ान पटौदी भी गवर्निंग काउंसिल में शामिल थे. काउंसिल के सदस्य रहते यदि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में असफल रहे तो उन्हें फिर से यह ज़िम्मेदारी देने का औचित्य क्या है?

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल तो शरद पवार की भूमिका को लेकर है. आईपीएल की शुरुआत जब हुई थी, तब पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे. उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी थी और मोदी को लीग का सर्वेसर्वा बनाया था. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि दो नई टीमों की नीलामी प्रक्रिया के दौरान उनके सगे-संबंधियों को स्वेट इक्विटी देने की बात की गई थी. पवार के दामाद मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) से भी जुड़े हैं और इसमें उनके शेयर हैं. आईपीएल के टेलीकास्ट राइट्स के मामले में 80 मिलियन की फैसिलिटेशन फीस के भुगतान को लेकर एमएसएम जांच के दायरे में है और टैक्स अधिकारियों ने उसे फेमा क़ानून के उल्लंघन का दोषी माना है. सट्टेबाज़ी और मैच फिक्सिंग के मामलों में भी उसकी भूमिका संदेह से परे नहीं है. सच यह भी है कि पवार ने मोदी को बचाने के लिए हरसंभव कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार के कड़े रवैये को देखते हुए उन्हें अपने मोदी प्रेम को तिलांजलि देनी पड़ी. बावजूद इसके बोर्ड के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने जांच से पहले ही शरद पवार को क्लीन चिट दे दी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पवार के ख़िलाफ़ कोई आरोप नहीं है. इन सबके पीछे बीसीसीआई का आख़िर वास्तविक उद्देश्य क्या है? कहीं मोदी को बलि का बकरा बनाकर बोर्ड और लोगों को बचाने की साजिश तो नहीं रच रहा? कम से कम अभी तक तो यही लग रहा है. होना तो यह चाहिए था कि भ्रष्टाचार एवं घपलों की बात सामने आते ही सभी संबद्ध लोगों को दूर रखकर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच-पड़ताल कराई जाती और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अंतरिम समिति में नए लोगों को शामिल किया जाता. लेकिन, मौजूदा हालत में इसकी संभावना कम ही दिखती है. ऐसा लगता है, जैसे बोर्ड पहले ही इस मामले में लीपापोती की तैयारी कर चुका है.

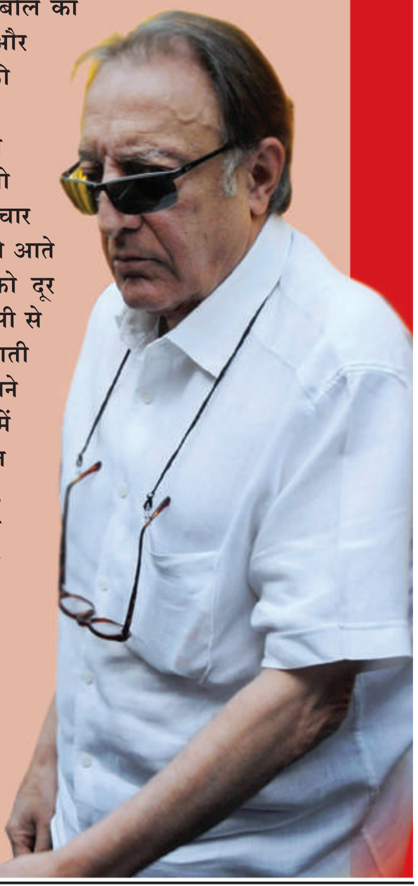

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वुड्स की परेशानियां बरक़रार

वर्ष 2009 के नवंबर-दिसंबर में कई महिलाओं के साथ विवाहेत्तर संबंधों को लेकर विवादों में आए गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स की परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. लंबे समय बाद पिछले महीने मास्टर्स टूर्नामेंट से गोल्फ के मैदान पर वापसी करने के बाद यह लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन पत्नी एलिन नॉर्डग्रेन के कड़े रवैये को देखते हुए ऐसा होता नहीं दिख रहा. हाई प्रोफाइल मॉडल्स, अभिनेत्रियों एवं संदिग्ध चरित्र वाली महिलाओं के साथ संबंधों के खुलासे के बाद वुड्स को कई महीने तक गोल्फ कोर्स से दूर रहना पड़ा था. इस विवाद ने केवल खेल की दुनिया ही नहीं, बल्कि वुड्स के पारिवारिक जीवन को भी झकझोर कर रख दिया. पत्नी एलिन नॉर्डग्रेन के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई. इसके बाद वुड्स ने अपना गुनाह कबूला और घोषणा की कि अपने पारिवारिक जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के बाद ही वह गोल्फ के मैदान में वापसी करेंगे.

अपने अज्ञातवास के बाद मास्टर्स टूर्नामेंट में भागीदारी करके उन्होंने खेल के मैदान पर दोबारा क़दम रखा तो यह लगा कि गोल्फ के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किए जाने वाले वुड्स की परेशानियां अब ख़त्म हो चुकी हैं. लेकिन, ख़बरों के मुताबिक़, एलिन नॉर्डग्रेन अभी भी उनसे ख़फ़ा हैं और तलाक की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं. वुड्स उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं, पर एलिन ख़ुद एवं बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपने लिए नया घर भी तलाश कर रही हैं. वह अपने वकीलों से बातचीत कर रही हैं. यदि वह अपनी बात पर अड़ी रहती हैं तो वुड्स न केवल पारिवारिक रूप से अलग-थलग पड़ जाएंगे, बल्कि उन्हें 600 मिलियन डॉलर का हर्जाना भी देना पड़ सकता है. गोल्फ के मैदान पर टाइगर वुड्स ने अनगिनत चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है. अब देखना यह है कि वह पारिवारिक झंझावातों से कैसे उबरते हैं.

राष्ट्रमंडल खेल : सुरक्षा पर संशय, प्रायोजकों का टोटा

इंडियन प्रीमियर लीग 2010 के दौरान बंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए बम विस्फोट ने राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा को लेकर भी संशय पैदा कर दिया है. बंगलुरू में उक्त विस्फोट तब हुए, जब मुंबई और बंगलुरू की टीमों के बीच मुक़ाबला होने वाला था. हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन मैच के बाद भी स्टेडियम के अलग-अलग हिस्सों से विस्फोटक बरामद किए गए. इस घटना ने विदेशी खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है. हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और सरकार ने चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इस माहौल को दूर करने की कोशिश की, लेकिन आतंकी संगठन जिस तरह बार-बार भारत में होने वाले खेल आयोजनों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए इस डर को पूरी तरह ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता. न्यूजीलैंड के खेल अधिकारियों ने कहा है कि टीम भेजने से पहले वह सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का पूरी तरह जायज़ा लेंगे. कोई आश्चर्य नहीं, यदि दूसरे देश भी इसी रास्ते पर चल पड़ें. राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के लिए सुरक्षा ही चिंता का एकमात्र कारण नहीं है. इसकी शुरुआत में अब छह महीने से भी कम वक़्त बचा है. तैयारियां धीमी चाल से सही, लेकिन अपने आख़िरी चरण में हैं. आयोजक अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं तो पदक की आस लिए खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहे हैं. लेकिन, इन सबके बीच हैरत की बात यह है कि देश में अब तक के सबसे बड़े खेल आयोजन के रूप में प्रचारित किए जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों को प्रायोजकों के लाले पड़ रहे हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां जो क्रिकेट के किसी भी आयोजन में अपने उत्पादों के प्रचार के लिए मुंहमांगी क़ीमत देने को तैयार रहती हैं, राष्ट्रमंडल खेलों से अब तक दूर हैं. सैमसंग, एलजी, एडीडास, मारुति, वीडियोकॉन, वोडाफोन एवं सहारा जैसी कंपनियां खेल आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. आईपीएल जैसी ग्लैमरस खेल प्रतियोगिताओं के दौरान उक्त कंपनियां अपने नए-नए उत्पादों को लांच करती हैं और ख़ास तौर पर विज्ञापन तैयार कराती हैं. वेस्टइंडीज में चल रहे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए प्रायोजकों की कोई कमी नहीं है. जून में आयोजित हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी प्रायोजकों की लंबी लाइन लगी है और वे सब इसके लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं.

कोका कोला अकेली ऐसी बड़ी कंपनी है, जो ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर के रूप में राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी है. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियां जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इंडियन रेलवे और एयर इंडिया ने भी इसके लिए करार किया है, लेकिन हद तो यह है कि अन्य कंपनियां इसके लिए उत्सुक नहीं हैं. उन्हें लगता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लैमर की कमी के चलते इसे टेलीविज़न या मैदान पर दर्शकों का उतना प्यार शायद ही हासिल हो और ऐसे में प्रायोजन के लिए एक बड़ी राशि ख़र्च करना घाटे का सौदा हो सकता है. यही वजह है कि कई कंपनियां तो राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ने से साफ इंकार कर चुकी हैं. लेकिन, यहां बात केवल नफा-नुक़सान की नहीं है. राष्ट्रमंडल खेलों के साथ देश की प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा है और फिर कारपोरेट जगत का कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है. फिर भी राष्ट्रमंडल खेलों के मामले में उनका उदासीन रवैया चौंकाता है और खेलों को बाज़ार के हिसाब से प्रचारित करने में आयोजन समिति की विफलता की कहानी भी बताता है.

गुल ने कर्नल शमशेर सिंह फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले पंजाब के ग्रामीण युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेगी.

बोल्ड इमेज के साइड इफेक्ट

फ़िल्म *मैं हूं ना* से रातोरात स्टार बनी अमृता राव आजकल कहीं गुम सी हैं. हाल में रिलीज़ फ़िल्म विक्टरी, लाइफ पार्टनर और शार्टकट-द कॉन इज ऑन क्या पिटीं, ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने लंबे समय का ब्रेक लेने का इरादा कर लिया हो. अगर उनकी आख़िरी सफल फ़िल्म की बात करें तो सिर्फ़ वेलकम टू सज्जनपुर का नाम ही याद आता है. इस फ़िल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की समीक्षकों ने भी जमकर तारीफ़ की थी, पर उसके बाद तो जैसे उनके करियर को ग्रहण लग गया. किसी फ़िल्म की सफलता और असफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. इन फैक्टर्स में कहानी, निर्देशक से लेकर सह कलाकार भी आते हैं. पर इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इन फ़िल्मों की असफलता का सबसे ज़्यादा नुक़सान उन्हें ही हुआ . अमृता के मुताबिक़, हिट-फ्लॉप का सिलसिला तो चलता ही रहता है. वह जल्द ही ऐसी फ़िल्म लेकर आएंगी, जो दर्शकों का दिल जीतने में सफल हो जाएगी. हालांकि वह यह मानती हैं कि उनकी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज लोग ज़्यादा पसंद करते थे, पर जबसे उन्होंने बोल्ड किरदार निभाने शुरू किए, उनके फैंस की संख्या घटती चली गई. वह जल्द ही अपनी पुरानी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज में वापस आने का वायदा करती हैं, लेकिन तब तक वह फ़िल्मों में अतिथि भूमिकाएं और दूसरी भाषा की फ़िल्मों में काम करके समय काट रही हैं. अब अगर समय ही काटना है तो ठीक है, पर अमृता मैडम, अगर अपने पुराने दौर की तरह फिर से लाइमलाइट में आना है तो आपको जल्द ही कोई नया पैंतरा अपनाना पड़ेगा, वरना पब्लिक किसी को भूलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाती.

लीजा रे की वापसी

सोलह साल की उम्र में अपने परिवार के साथ भारत आईं लीजा रे को उसी वक़्त मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया था. कनाडा में जन्मी लीजा के पिता भारतीय और मां पोलैंड की हैं. फ़िल्म कसूर और वॉटर से बॉलीवुड में छा जाने वाली लीजा को कैंसर हो गया था. मीडिया में मोस्ट ब्यूटीफुल के खिताब से नवाज़ी गईं लीजा काफी समय तक इस बीमारी से जूझती रहीं. कैंसर से छुटकारा पाने के लिए उन्हें स्टेल सेल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ा. ख़ुशी की बात यह है कि वह इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा चुकी हैं. लीजा ने फ़िल्म *वॉटर* के लिए अपने बाल मुड़वाए थे, लेकिन कैंसर के इलाज के दौरान उनके ख़ूबसूरत बाल झड़ गए थे. लेकिन, लीजा परेशान नहीं हुईं. वह कहती हैं कि कैंसर ठीक होने के बाद उनके बाल वापस आ रहे हैं और अच्छे दिखते हैं. अपने बालों को उन्होंने कभी ध्यान से नहीं देखा था. वह कम बालों का पूरा मज़ा ले रही हैं. वह नए जोश के साथ करियर को एक और शुरुआत देने के लिए जल्द ही भारत लौटने वाली हैं. लीजा अब मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा लेखन में भी जलवा दिखाने को बेकरार हैं. वह अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को जल्द ही दुनिया के सामने लाने वाली हैं. अभी हाल में लॉस एंजिल्स में हुए इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल की ओपनिंग उनकी हालिया फिल्म *कुकिंग विद स्टेला* की स्क्रीनिंग से हुई. वह कहती हैं कि इस फेस्टिवल के दौरान हुई कमाई का बीस फ़ीसदी हिस्सा लॉस एंजिल्स के माइलोमा एंड बोन कैंसर रिसर्च को जाएगा. यह संस्था कैंसर की कारगर दवा पर रिसर्च कर रही है. लीजा कहती हैं कि इस तरह की मदद से ही कैंसर की रोकथाम की जा सकेगी. इस नेक काम के लिए लीजा बधाई की हक़दार हैं.

रोम मेरा पसंदीदा शहर है : लारा दत्ता

अक्षय कुमार को अपना आइडियल बताने वाली लारा दत्ता अगली फ़िल्म हाउसफुल में उनकी को स्टार हैं. इस फ़िल्म को लेकर उन्हें काफी उम्मीदें हैं. अपनी फ़िल्मों, निजी ज़िंदगी और शौक़ के बारे में उन्होंने पिछले दिनों चौथी दुनिया की संवाददाता रीतिका सोनाली से खुलकर बातचीत की. पेश हैं प्रमुख अंश :

हाउसफुल की शूटिंग के दौरान की कुछ यादें, जो आप शेयर करना चाहती हों.

हाउसफुल की शूटिंग इटली के दक्षिणी क्षेत्र पुगलिया में हो रही थी. इस दौरान दो-तीन दिनों की छुट्टी मिली तो मैंने अपने दोस्त क्लाराबेल एवं को-स्टार रीतेश के साथ रोम जाकर घूमने की योजना बनाई. आर्किटेक्चर का स्टूडेंट होने की वजह से रीतेश को रोम देखने की इच्छा थी और रोम मेरी पसंदीदा जगहों में भी शामिल है, इसलिए हम लोग वहां घूमने गए. वहां की संस्कृति को जानना, ख़ूबसूरत प्राचीन पिआज्जा गेट एवं त्रेवा फाउंटेन आदि देखना काफी रोमांचकारी रहा. एक आश्चर्यजनक बात जो मुझे अच्छी लगी, वह यह कि रोम में कार चलाकर घूमने पर पाबंदी है. अगर आप दूसरे शहर से कार लेकर आए हैं, फिर भी वहां उसे चला नहीं सकते. अपने पसंदीदा शहर रोम को काम के दौरान देखना काफी अच्छा लगा. वहां की सैर याद करके मैं सबसे ज़्यादा ख़ुश होती हूं.

इंडस्ट्री में आपका सफर कैसा रहा?

मैंने बंगलुरू से आकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश की और यह कोशिश बहुत हद तक सफल भी रही. मैंने एंट्री के वक़्त सोचा भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री में जहां स्टारपुत्रों एवं पुत्रियों की धूम है, अपने क़दम जमा सकूंगी. बांबे डाइंग, सियाराम, सिनर्जी और लॉरियल के विज्ञापन में आने के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उस दौरान मैं अर्थशास्त्र में स्नातक कर रही थी और मॉडलिंग असाइनमेंट भी पूरे कर रही थी. मेरे करियर में यू टर्न तब आया, जब मैंने शहाब दुराजी, रोहित बल एवं रितु बेरी आदि बड़े डिज़ाइनरों द्वारा आयोजित फैशन शो में रैंप पर कैटवॉक किया. मिस यूनिवर्स का ताज जीतने के बाद मैं यूएनएफपीए की गुडविल एंबेसडर बनी और मैंने लगातार एक साल तक 68 देशों में घूमकर एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई. इस दौरान मैंने मशहूर विदेशी डिज़ाइनरों के साथ फैशन शो किया. दो सालों तक न्यूयॉर्क में रेडियो शो होस्ट किया. इसके बाद भारत आने पर बॉलीवुड में क़दम रखा और अब मैं सफलता की ओर बढ़ रही हूं. सच कहूं तो मुझे यह सब सपनों के सफर जैसा लगता है.

एक्टिंग के अलावा क्या शौक़ हैं?

एक्टिंग के अलावा मुझे डांस का शौक़ है. मैं प्रशिक्षित भरतनाट्यम और कत्थक नृत्यांगना हूं. खाली वक़्त में हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग और डांसिंग मुझे बेहद पसंद है. मुझे घूमने का भी शौक है. लंबी छुट्टियां मनाने के लिए मैं जैसलमेर, मालदीव, बारसेलोना, हवाई और भूटान जाना पसंद करती हूं. मुझे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी पसंद हैं.

ख़ुद को मेंटेन कैसे करती हैं?

मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज़ करती हूं, पर कभी-कभी अपना पसंदीदा खाना लेती हूं. मुझे दाल मक्खनी, बिरयानी, थाई और इटैलियन खाना पसंद है.

एवरी डे रूटीन में कुछ ख़ास चीजें, जो आपको पसंद हों...

मैं तकनीक पसंद हूं. मेरे पसंदीदा गैजेट्स आई पॉड, आई फोन, मैक नोटबुक, पीएसपी एवं ड्राइव मीटर हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं. मुझे कार और बाइक भी रखने का शौक़ है. मेरी पसंदीदा कार एसटॉन मार्टिन कंवर्टिबल, ओल्ड वोक्सवैगन बीटल, पोर्क कायने, रेंज रोवर एवं मिनी कुपर हैं और बाइक्स में डुकाट्टी स्पोर्ट और हार्ले डेविडसन पसंद हैं. मुझे पारंपरिक साड़ी अच्छी लगती है और वेस्टर्न फिटिंग गाउन एवं ब्लू जींस भी. मेरा पसंदीदा रंग भारत में शुभ माना जाने वाला लाल है.

गुल की मुश्किल

गालों पर पड़ने वाले ख़ूबसूरत डिंपल्स गुल के मस्तमौला स्वभाव से मेल खाते हैं. अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म रण में नज़र आईं गुल पनाग अब अगली फ़िल्म की तैयारियों में व्यस्त हैं. उनकी अगली फ़िल्म फाट्सो इसी साल के मध्य में रिलीज़ होने वाली है. अभी हाल में गुल ने कर्नल शमशेर सिंह फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले पंजाब के ग्रामीण युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेगी. इस काम से उन्हें जितनी ख़ुशी मिली, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. परेशानी की वजह है एक फोन कॉल. उन्हें यह कॉल चंडीगढ़ से दिन में पच्चीस बार आई, पर कॉल करने वाले ने उनसे कोई बात नहीं की. यह कॉल उनके फैंस की है या किसी और की, इसका पता लगने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा, पर फालतू की सिरदर्दी गुल के पल्ले ज़रूर पड़ गई है. उनके साथ इस तरह की अप्रिय घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं. कुछ दिनों पहले वह अपनी पसंदीदा ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थीं, तब उनके बाथरूम का दरवाज़ा इस कदर बंद हो गया कि उनके लिए उसे खोल पाना मुश्किल था. काफी मुश्किलों के बाद वह बाथरूम से निकल पाईं, तब उनकी जान में जान आई. पर अन्य लड़कियों की तरह उन्होंने अंदर से चीखना-चिल्लाना शुरू नहीं किया. इसकी वजह यह है कि उन्हें एडवेंचर पसंद है और उनकी पसंदीदा ट्रेन शताब्दी में एडवेंचर का अपना ही मजा है. ग़ौरतलब है कि गुल महीने में दो बार शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर ज़रूर करती हैं. ट्रेन का सफर तो ठीक है, पर गुल बाथरूम में फंसकर कैसा एडवेंचर! अब सुनिए गुल की फिटनेस का राज़. इसके लिए न तो वह फिटनेस ट्रेंड अपनाती हैं और न ही बहुत सारी एक्सरसाइज करती हैं. दरअसल वह ट्रेकिंग पर जाना पसंद करती हैं. तनाव दूर करने के लिए वह लंबी दौड़ लगाती हैं. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. उन्हें घूमने का शौक़ है और साल में एक बार वह अपनी एक्स यूवी कार से लद्दाख ज़रूर जाती हैं. वह खाने में संतुलित और पोषक आहार लेती हैं, जिसमें उत्तर भारतीय व्यंजन जैसे दाल, रोटी, सब्जी एवं चावल आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. खाने के साथ गुल सलाद, सब्जियों का जूस और दूध ज़रूर लेती हैं. अच्छी नींद के लिए वह बंगाली रजनीगंधा का तेल लगाती हैं और अपने हाथों-पैरों में क्रीम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ़िल्म रिव्यू

अपार्टमेंट की थ्रिलर कहानी

तनुश्री दत्ता, नीतू चंद्रा, रोहित राय एवं अनुपम खेर स्टारर अपार्टमेंट एक थ्रिलर फ़िल्म है. मुंबई जैसे शहर में घर की चाहत रखने वाले लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही इस फ़िल्म की कहानी का आधार है. यहां की एक सोसाइटी में बने अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेने के लिए तनुश्री को एक किराएदार की ज़रूरत पड़ती है. घर के किराए को शेयर करने के ख्याल से उनका ब्वॉयफ्रेंड रोहित राय उनके घर में रहने आता है, पर किसी शक़ की वजह से तनुश्री उसे घर से निकाल देती हैं और फिर नए किराएदार के रूप में नीतू चंद्रा उनके घर आती है. नेहा (नीतू चंद्रा) तनुश्री को बेहद प्यार करने लगती है और यह प्यार ऐसा रूप ले लेता है कि वह अपने और तनुश्री के बीच किसी को पसंद नहीं करती. कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब तनुश्री की अपने ब्वॉयफ्रेंड से सुलह हो जाती है. रोहित राय के साथ अपनी दीदी तनुश्री को बांटना नेहा को अच्छा नहीं लगता. इससे आहत नेहा कई हिंसक वारदातों को अंजाम देती है. सस्पेंस और थ्रिलर घटनाओं के साथ कहानी आगे बढ़ती है, पर बीच-बीच में बेवजह और अचानक रोमांटिक एवं आइटम सांग की प्रस्तुति दर्शकों को बोर करती है. अभिनय के स्तर पर तनुश्री दत्ता के मुक़ाबले नीतू चंद्रा ने अच्छा काम किया है. कई फ़िल्मों में आइटम सांग और अतिथि भूमिकाएं निभाने के बाद नीतू ने इस फिल्म में ख़ुद को साबित किया. अनुपम खेर की उपस्थिति सीन को और भी जानदार बना देती है. रोहित राय ने भी अच्छा काम किया है, पर मुख्य अभिनेता के तौर पर वह जमे नहीं. बतौर अभिनेता दर्शक ख़ूबसूरत चॉकलेटी चेहरा देखना पसंद करते हैं, जिसके मुक़ाबले रोहित काफी उम्रदराज और परिपक्व लगते हैं. फ़िल्म के संवाद ज़्यादातर भावनात्मक होने के कारण दर्शकों में अंत तक रुचि बनी रहती है. फ़िल्म का निर्देशन अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है और ट्रीटमेंट भी. उम्मीद है कि थ्रिलर फिल्मों के शौक़ीन दर्शकों को यह फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी.

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 10 मई-16 मई 2010
www.chauthiduniya.com

बटाईदारी बिल भ्रम का भंवर

बटाईदारी बिल बिहार में एक अहम चुनावी मुद्दा बन कर उभर रहा है. नीतीश कुमार की लाख सफाई के बावजूद बटाईदारी बिल के लागू होने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे सूबे के किसान और बटाईदार दोनों भ्रम में पड़ गए हैं. अगर जल्द ही यह भ्रम नहीं टूटा तो सामाजिक ताने-बाने को नुक़सान पहुंच सकता है.

सरोज सिंह

सरकार कहती है कि बटाईदारी बिल लागू नहीं होगा, लेकिन विपक्ष का दिल है कि मानता ही नहीं. सरकार कहती है कि जब बंगाल में बटाईदारी बिल लागू नहीं हुआ तो बिहार में कहां से लागू होगा. विपक्ष कहता है कि सरकार की नीयत में खोट है. अगर बिल लागू नहीं करना है तो फिर सरकार इसे पूरी तरह ख़ारिज़ क्यों नहीं कर देती. चूंकि यह चुनावी साल है और मसला ज़मीन से जुड़ा है, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों ही बटाईदारी बिल पर फूंक-फूंककर बोल रहे हैं और लोगों को अपने-अपने हिसाब से समझा रहे हैं. जदयू की तरफ से भ्रम दूर करने के लिए किसान रथ निकला है, तो नौ मई को पटना में किसान महापंचायत में कई विपक्षी नेता बटाईदारी बिल का सच जनता के सामने रखेंगे. मतलब साफ़ है कि आगामी चुनाव में बटाईदारी बिल एक बड़ा मुद्दा बनेगा और नेता एवं दल अपने-अपने हिसाब से इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

भूमि सुधार के लिए गठित बंद्योपाध्याय समिति ने बटाईदारी के संबंध में ढेर सारी अनुशंसाएं की हैं. सरकार ने इस संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सी अशोकवर्द्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो इस बात पर विचार करेगी कि बटाईदारी के संबंध में अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता है या वर्तमान अधिनियम में ही सुस्पष्ट एवं पर्याप्त प्रावधान हैं. भ्रम एवं सियासी पेंच का सिलसिला बस यहीं से शुरू हो जाता है. सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर बटाईदारी बिल को लागू नहीं करना है तो फिर समिति की ज़रूरत ही क्या है? सरकार ने बंद्योपाध्याय समिति की बहुत सारी अनुशंसाओं को ख़ारिज़ किया है. इसी तरह इसे भी पूरी तरह ख़ारिज़ कर देती, पर यहां तो नीयत में ही खोट है. देर-सबेर इस बिल को लागू करने की मंशा के कारण ही फिलहाल इसे समिति को सौंप दिया गया है. लालू प्रसाद का आरोप है कि बटाईदारी क़ानून के सहारे ज़मीन से लोगों को बेदख़ल करने की साजिश नीतीश सरकार रच रही है. सरकार की नीयत साफ़ नहीं है. बिहार में अब किसी के पास फाजिल ज़मीन नहीं है. इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि बटाईदारों को पुश्तैनी अधिकार देने की बात पूरी तरह अव्यवहारिक है. सीपीआई महासचिव ए बी वर्द्धन के अनुसार, अंग्रेजों की तरह नीतीश कुमार पहले आयोग, फिर जांच समिति और उसके बाद कैबिनेट की बैठक का भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. भूमि सुधार नहीं करना था तो बंद्योपाध्याय समिति बनाने की ज़रूरत ही क्या थी. बकौल नीतीश कुमार, मैं सदन में बोल रहा हूं. कहां है बटाईदारी बिल? कोई जरा हमें बता दे बटाईदारी बिल? राजस्व विभाग में कोई कच्चा ड्रॉफ्ट भी कोई बता दे? कहीं नहीं है, जो है, सो सदन के पटल पर रखा जा चुका है. सदन पटल पर इसलिए रखा गया है कि इस पर विचार-विमर्श हो. सरकार ने विभाग के एक अधिकारी की अध्यक्षता में कमिटी बना दी है, अगर विचार-विमर्श का माहौल बनेगा तो देखेंगे कि आज का क़ानून छोड़ दिया जाए या इसमें कुछ सुधार किया जाए या कोई नई बात लाई जाए. सदन के बाहर भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि जो होगा, वह सभी की सहमति से होगा, लेकिन बटाईदारी बिल पर अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं. उनकी राय है कि इस बिल से न तो किसानों का भला होगा और न ही बटाईदारों का. बंद्योपाध्याय समिति की अनुशंसाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इसे पूरी तरह ख़ारिज़ कर देना चाहिए, वरना गांवों में शांति का माहौल प्रभावित होगा. उनका कहना है कि शहर में रहने वाले लोगों का भी गांवों से जुड़ाव इसलिए होता है कि उनकी ज़मीन गांव में है. जब किसी को लगेगा कि गांवों में तो उसका कुछ है ही नहीं, तो गांव से उसका रिश्ता ही टूट जाएगा. रमेश प्रसाद का कहना है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बटाईदारी बिल कहां है? लेकिन सभी जानते हैं कि समिति की अनुशंसा पर 24 घंटे के भीतर बिल तैयार किया जा सकता है. उनका कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो वह बंद्योपाध्याय समिति की बटाईदारी से संबंधित अनुशंसा को रद्द कर दे, जैसा कि सीलिंग संबंधी अनुशंसा को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है. कुल मिलाकर देखें तो स्थिति यह बनती है कि भ्रम के एक घेरे में बटाईदारी बिल कैद है और दोनों ही पक्ष इस घेरे को अपने-अपने तर्कों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन, यह कोशिश जितनी तेज़ी से हो रही है, भ्रम का घेरा उतना ही गहराता जा रहा है. बिहार के गांवों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे लाखों किसानों एवं बटाईदारों को इंतजार है भ्रम के गहराते इस घेरे के टूटने का, क्योंकि जब तक घेरा नहीं टूटेगा, तब तक उनकी सांस अटकी रहेगी.

> भूमि सुधार के लिए गठित बंद्योपाध्याय समिति ने बटाईदारी के संबंध में ढेर सारी अनुशंसाएं की हैं. सरकार ने इस संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सी. अशोकवर्द्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो इस बात पर विचार करेगी कि बटाईदारी के संबंध में अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता है या वर्तमान अधिनियम में ही सुस्पष्ट एवं पर्याप्त प्रावधान है.

बटाईदारी अनुशंसा पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन

अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता है अथवा वर्तमान अधिनियम में ही सुस्पष्ट एवं पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं, इस संदर्भ में आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए सरकार ने डॉ. सी अशोकवर्द्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो इस पर विचार कर यथासमय सरकार को अवगत कराएगी. तदोपरांत सरकार उचित निर्णय लेगी.

feedback@chauthiduniya.com

बटाईदारी पर भूमि सुधार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं

- बटाईदारों की रक्षा के लिए एक अलग बटाईदारी अधिनियम होना चाहिए.
- भूमि पर मात्र दो श्रेणियों के व्यक्ति रहें-
  (क) रैयत, जिसे भूमि पर पूर्ण स्वामित्व, अधिकार तथा हित रहेगा.
  (ख) बटाईदार, जिसे स्वामित्व का अधिकार नहीं, अपितु भूमि पर लगातार जोत-आबाद का अधिकार रहेगा.
- क़ानून में सरल भाषा में बटाईदार की स्पष्ट परिभाषा रहे.
- बटाईदार के पक्ष में एक क़ानूनी मान्यता रहे कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की ज़मीन क़ानूनी तौर पर जोत-आबाद करता हो तो वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति का बटाईदार माना जाएगा.
- खंडन का दायित्व उस व्यक्ति का होगा, जो बटाईदार की स्थिति को चुनौती देता हो.
- हर बटाईदार के पास पर्चा रहे, जिसमें भू-स्वामी का नाम एवं जिस भूखंड पर वह जोत कर रहा है, उसकी संख्या हो. पर्चे की अभिप्रमाणित प्रति भू-स्वामी को दी जाए. बटाईदार का जोत-आबाद का अधिकार अनुवांशिक रहे.
- सहभागितापूर्ण क्षेत्रीय बुझारत करके स्वत्वाधिकार अभिलेख में बटाईदारों के नाम अभिलिखित होने चाहिए.
- ऐसा जनोन्मुख सहभागितापूर्ण क्षेत्रीय बुझारत चलाने के लिए नौकरशाही को पुन: उन्मुख और कौशलीकृत किया जाए.
- इस प्रक्रिया में पंचायतों को पूरी तरह शामिल किया जाए और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि बटाईदारों के नामों के अभिलेखन की परिशुद्धता सुनिश्चित करें.
- उत्पादन का न्यायोचित विभाजन हो. यदि बटाईदार उत्पादन व्यय वहन करे तो उसे उत्पादन का 70 से 75 प्रतिशत मिले. यदि भू-धारी उत्पादन व्यय में सहभागी बने तो उत्पादन का 60 प्रतिशत बटाईदार और 40 प्रतिशत भू-धारी को मिले.
- भू-धारी को मात्र अपनी आजीविका के लिए ज़मीन वापस लेने का अधिकार मिले. तब वह उसे स्वयं जोत-आबाद करेगा. यदि किसी मृत बटाईदार की संतानें बटाईदारी करने से इंकार करें, तब वैसी स्थिति में भू-धारी ज़मीन वापस कर सकता है.
- भू-धारी वापस हुई भूमि में कोई दूसरा बटाईदार नहीं रख सकेगा. यदि वह ऐसा करता है तो भूमि पुन: मूल बटाईदार को चली जाएगी.
- व्यक्तिगत खेती को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि भू-धारी उसी गांव या पड़ोसी गांव का निवासी हो और जिस भूमि को वह वापस करना चाहे, उससे उसकी आय के 50 प्रतिशत से अधिक की आय हो.
- इस नए क़ानून पर चर्चा के दौरान और क़ानून बनने के तुरंत बाद बटाईदारों पर बटाई भूमि सरेंडर करने के लिए दबाव पड़ेगा. जब तक सक्षम राजस्व पदाधिकारी उभय पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं दे, तब तक ऐसे सरेंडर को सही नहीं माना जाएगा.
- बटाईदारी पर्चे की बदौलत व्यवसायिक बैंकों, सहकारिता बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से सांस्थिक ऋण लिए जा सकेंगे.
- अंचलाधिकारी को बटाईदार और भू-धारी के बीच विवाद अधिनिर्णय की शक्ति रहेगी. उसके समक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहना चाहिए. बटाईदार द्वारा वाद दायर करने पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए. प्रथम अपील अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष तथा द्वितीय अपील समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष दायर होनी चाहिए.
- वर्तमान बिहार काश्तकारी अधिनियम में रैयतों और दर-रैयतों के विभिन्न वर्ग आदि से संबंधित सारे प्रावधान विलोपित होने चाहिए, ताकि पुराने बिहार काश्तकारी अधिनियम तथा नए बटाईदारी अधिनियम के बीच क़ानूनी विरोध न हो.
- भू-धारी अपनी ज़मीन किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन अथवा संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होगा, पर इस अंतरण के बावजूद बटाईदार अपने जोत-आबाद के अधिकार का उपयोग करता रहेगा. संपत्ति अंतरण किसी बटाईदार को निष्कासित करने का एक उपकरण नहीं बन सकता.
- बिना विधि की उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए किसी बटाईदार को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा. निष्कासन के आधार पर भू-धारी को तीन लगातार फसलों में उत्पादन का हिस्सा जानबूझ कर न देना और/अथवा भूमि के स्वरूप को इस तरह परिवर्तित करना या क्षतिग्रस्त करना हो सकता है, जिसके कारण सामान्य उत्पादकता में ह्रास आ गया हो.
- इन अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद आयोग विधि विभाग को कानूनेत्तर ठोस तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध कराकर बटाईदारी विधेयक का प्रारूप तैयार करने में मदद करने को इच्छुक होगा. निस्संदेह यह आयोग के वर्तमान संदर्भ बिंदुओं से बाहर रहेगा.

गांव के मुखिया गिरजा देवी के पति से मोबाइल पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह जाति बिरादरी का मामला है.

झारखंड की जनता को जिंदल द्वारा समर्पित वायर रॉड मिल दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली आधुनिकतम मिल है.

हसनपुर विधानसभा में चुनावी तपिश बढ़ी

विकास कुमार

समस्तीपुर क्षेत्र के बाद हसनपुर क्षेत्र की गिनती प्रतिष्ठित क्षेत्रों में होती है. इसका कारण है समस्तीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, वहीं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक गजेंद्र प्रसाद हिमांशु बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं. लालू प्रसाद के शासनकाल के दौरान राजद सुप्रीमो द्वारा क्षेत्र के दिग्गज नेता व तत्कालीन मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के भतीजे सुनील कुमार पुष्पम को विधानसभा की राजनीति में उतारा गया था. तब से लेकर आज तक वह तीन बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. पिछली बार के चुनाव में राजद विधायक पुष्पम से टक्कर लेने उनके चाचा गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जदयू के टिकट पर और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शीला सिंह एवं लोजपा से रामनारायण मंडल चुनावी जंग में उतरे थे, लेकिन बाजी सुनील कुमार पुष्पम के हाथ लगी. अब जबकि आगामी विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के अंतर्गत होना है और हसनपुर क्षेत्र का परिदृश्य बदला–बदला सा है, ऐसे में वहां ज़्यादा गहमागहमी चल रही है. मालूम हो कि पिछले संसदीय चुनाव में ज़िले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र को निकटवर्ती खगड़िया संसदीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है. इससे हसनपुर विधानसभा की राजनीति में समस्तीपुर एवं खगड़िया ज़िले के जदयू सांसद की सक्रियता भी काफ़ी मायने रखती है. ग़ौरतलब है कि पूर्व में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र रोसड़ा (सु.) संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था. नए परिसीमन के मुताबिक़ जब रोसड़ा (सु.) संसदीय क्षेत्र को समाप्त कर समस्तीपुर (सु.) बनाया गया तो इससे रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के सिंघिया विधानसभा को समाप्त कर कुशेश्वरस्थान (सु.) क्षेत्र बनाया गया. इसी प्रकार रोसड़ा विधानसभा सामान्य क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया और ज़िले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र को निकट के दूसरे ज़िले खगड़िया के संसदीय सीट से जोड़ दिया गया है. इस बात को लेकर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण ही बदल गया है और यहां के लोग पिछले संसदीय चुनाव में समस्तीपुर ज़िले की राजनीति से कटे रहे, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा और लोजपा के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान रोसड़ा (सु.) सीट के बदले नवगठित समस्तीपुर (सु.) सीट से चुनाव लड़े और जदयू प्रत्याशी महेश्वर हज़ारी से एक लाख से अधिक मतों से मात खा गए. इस चुनाव में बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल के नेता डॉ. अशोक कुमार को भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हसनपुर के 20, बिथान के 13 और सिंघिया प्रखंड के 4 पंचायत शामिल हैं. बता दें कि हसनपुर विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,18,042 है, जिसमें 1,01,630 महिला एवं 1,16,412 पुरुष हैं. वोटरों में यादव जाति की संख्या सर्वाधिक है और वह हर बार 75 प्रतिशत के करीब मतदान करते हैं. दूसरे स्थान पर मल्लाह जाति के मतदाता हैं और वह 85 प्रतिशत से ऊपर मतदान करते हैं. तीसरे स्थान पर कोयरी, चौथे पर मुस्लिम, पांचवें पर राजपूत एवं छठे स्थान पर कुर्मी मतदाता हैं. इन सभी जातियों के मतदाता 50 से 60 प्रतिशत मतदान करते हैं. इस क्षेत्र में भूमिहार, ब्राह्मण के अलावा पासवान एवं वैश्य भी काफ़ी संख्या में हैं. पिछली बार राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी लोजपा के रामनारायण मंडल को 1,727 मत से पराजित किया था. इस बार नए परिसीमन के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर दोनों पूर्व प्रत्याशी आर–पार की लड़ाई के मूड में हैं और इसके लिए वे कोई भी राजनीतिक समीकरण में अपने को शामिल कर सकते हैं. जैसे–जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहुबलियों की बांहे फुल रही हैं और वे किसी न किसी खेमे में शामिल होने को बेताब हैं. अभी से ही क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सत्ता एवं विपक्ष के समर्थक बूथ कमिटी बनाने की रणनीति में जुट गए हैं. वहीं ज़िला नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व भी इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है.

अर्जुन यादव

गजेंद्र प्रसाद हिमांशु

रामनारायण मंडल

सजंय कुमार मिश्रा

सुनीता सिंह

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सीमावर्ती खगड़िया ज़िले के जदयू सांसद दिनेशचंद्र यादव अक्सर हसनपुर विधानभसा क्षेत्र आते–जाते हैं, जिससे जदयू के संभावित दावेदारों में भी सरगर्मी बनी हुई रहती है. अभी कुछ दिन पहले ही हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिथान प्रखंड प्रमुख विभा देवी को ज़िला जदयू महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष पद पर बिठा देने से प्रखंड प्रमुख के हसनपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा गरम हो गई है. इसी प्रकार ज़िला परिषद क्षेत्र सं 50 से ज़िला पार्षद आशा देवी भी अपने पति जदयू नेता अर्जुन यादव के समर्थन में काफ़ी सक्रिय हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान ज़िला पार्षद आशा देवी के पति खगड़िया संसदीय सीट से जदयू प्रत्याशी दिनेशचंद्र यादव के सारथी बने थे. वह समर्थकों की टोली के साथ गांव–गांव जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राजग गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को आमजनों तक पहुंचाया था, जिसका नतीज़ा रहा कि यादव बाहुल्य इस क्षेत्र में जदयू को तकरीबन 48,000 वोट मिले, जबकि लोकसभा चुनाव से पूर्व हुए 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मात्र 11 हज़ार वोट मिले थे. लोकसभा चुनाव में जदयू को हसनपुर विधानसभा में मिले अपार जनसमर्थन से उत्साहित अर्जुन यादव तभी से क्षेत्र की राजनीति में तत्परता से डटे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लिए कमर कसे हुए हैं.

ज़िला जदयू अध्यक्ष एवं रोसड़ा के पूर्व विधायक अशोक कुमार मुन्ना ने जबसे हसनपुर पंचायत के मुखिया जितेंद्र सिंह को ज़िला जदयू का उपाध्यक्ष बनाया है, टिकट हेतु इनकी भी दावेदारी क्षेत्र में दर्ज हो रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहकर मौजूदा विधायक सुनील कुमार पुष्पम को कड़ी चुनौती देने वाले लोजपा प्रत्याशी रामनारायण मंडल के समर्थक असमंजस की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि लोजपा–राजद गठबंधन के वामपंथी पार्टियों से भी तालमेल के आसार हैं. ऐसी स्थिति में लोजपा के पूर्व प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने 27 अप्रैल को पटना में जदयू प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता ग्रहण की. उनके समर्थक दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं उन्हें जदयू में आमंत्रित किया है, इसीलिए टिकट मिलने की शत प्रतिशत गांरटी है. एक तो जदयू में टिकट की दावेदारी को लेकर पूर्व से ही रस्साकस्सी जारी है. ऐसे में यदि रामनारायण मंडल के लोजपा से जदयू में आ जाने से जदयू कार्यकर्ताओं में खलबली मची है, तो विधानसभा के टिकट हेतु पार्टी में मची खींचतान की स्थिति में पार्टी आलाकमान को यहां काफ़ी माथापच्ची करनी होगी. 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन मात खा गए. गजेंद्र प्रसाद हिमांशु क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में एक हैं, जिन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व भी किया है.

ज़िले के सीमावर्त्ती खगड़िया, बेगूसराय एवं दरभंगा के बीच में स्थित है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र. दोनों ज़िला पूर्व विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के आगमन को लेकर ख़ासे चर्चे में हैं, क्योंकि पूर्व विधायक एवं मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु उनके काफ़ी क़रीबी लोगों में से माने जाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह दमखम से लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं. एकला चलो रे की नीति पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस के युवा प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि हसनपुर कांग्रेस की पुरानी सीट रही है और कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी तमाम दलों को चुनौती देने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं. संजय कुमार मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क अभियान भी प्रारंभ कर दिया है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पीसी स्कूल रामपुर के निदेशक व पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के डिग्रीधारी संजय मिश्रा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी का संदेश गांव–गांव घूमकर मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं. टिकट वितरण में स्वच्छ छवि के युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दिए जाने की राहुल गांधी की रणनीति पर यदि अमल होता है तो कांग्रेस की ओर से संजय कुमार मिश्रा की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है. इन दिनों ज़िले की महिला राजनीति को प्रभावित करने वाली ज़िला परिषद की उपाध्यक्ष सुनीता सिंह एवं उनके बाहुबली पति कुंदन सिंह की भी चर्चा संभावित टिकटार्थियों में होती है. लोजपा से जुड़ी सुनीता सिंह का हौसला बुलंद है और वह राजनीति में कुछ भी होने से इंकार नहीं करती.

> बता दें कि हसनपुर विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,18,042 है, जिसमें 1,01,630 महिला एवं 1,16,412 पुरुष हैं. वोटरों में यादव जाति की संख्या सर्वाधिक है और वह हर बार 75 प्रतिशत के करीब मतदान करते हैं. दूसरे स्थान पर मल्लाह जाति के मतदाता हैं और वह 85 प्रतिशत से ऊपर मतदान करते हैं. तीसरे स्थान पर कोयरी, चौथे पर मुस्लिम, पांचवें पर राजपूत एवं छठे स्थान पर कुर्मी मतदाता हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मतदाता दूसरी बार एकमा का इतिहास लिखेंगे

विजयेंद्र कुमार

नवसृजित एकमा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर दावेदारों के बीच घमासान की स्थिति कायम है. समाजवादी राजनीति के मजबूत गढ़ के रूप में कभी सारण प्रमंडल में शुमार मांझी विधानसभा क्षेत्र का एकमा महत्वपूर्ण अंग माना जाता था. नए परिसीमन के बाद एकमा का अलग अस्तित्व कायम हुआ. एकमा का अलग अस्तित्व कायम हो जाने से प्रतिनिधित्व को लेकर दलीय प्रतिबद्धता का अभाव दिखता है. दावेदारों में कुछ पुराने चेहरे को छोड़ शेष नए चेहरों की भरमार है, जो आगामी चुनाव के मद्देनज़र मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए जनसंपर्क की मुहिम तेज कर दिए हैं. गठबंधन की राजनीति के चलते दलीय आधार पर टिकट की चाह को नज़रअंदाज कर अधिकांश दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी अमादा हैं. बहरहाल राजग, राजद–लोजपा, कांग्रेस और बसपा के कई संभावित उम्मीदवार मतदाताओं के बीच अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं. मगर, गठबंधन की राजनीति में सीटों के ताल–मेल को लेकर संशय की स्थिति बरक़रार है.

नए परिसीमन के तहत एकमा विस क्षेत्र में कुल 36 पंचायत को शामिल किया गया है, जिनमें एकमा प्रखंड के कुल 21 पंचायतों सहित मांझी के सात व लहलादपुर प्रखंड के सभी आठ पंचायतें शामिल हैं. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 12 हज़ार 885 है, जिनमें राजपूत 42 हज़ार, यादव 19 हज़ार, ब्राह्मण 18 हज़ार, कुर्मी कुशवाहा 16 हज़ार, भूमिहार 12 हज़ार, अल्पसंख्यक 17 हज़ार और दलित समुदाय 28 हज़ार के साथ शेष अन्य जाति के मतदाता हैं. ग़ौरतलब है कि इसके पूर्व 1952 में एकमा विस क्षेत्र अस्तित्व में आया था. उस वक्त पहली बार इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी स्व. लक्ष्मी नारायण सिंह ने जीत हासिल कर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. इसके बाद इस क्षेत्र को मांझी और बनियापुर विस क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया. नए परिसीमन के अंतर्गत एकमा विस क्षेत्र में पूर्व के मांझी विस क्षेत्र के 18 एवं बनियापुर के 18 पंचायतों को शामिल किया गया है.

2005 में हुए विधानसभा चुनाव में मांझी से निर्वाचित जदयू विधायक व नीतीश सरकार में गन्ना विकास राज्य मंत्री गौतम सिंह का घर गंजपर और बनियापुर से निर्वाचित जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ़ धूमल सिंह का गांव भजौना शामिल है. वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानकारों का कहना है कि नए परिसीमन ने इन दोनों नेताओं को असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. चर्चा यह भी है कि मंत्री सिंह की रुचि मांझी से चुनाव लड़ने की है, जबकि धूमल सिंह महाराजगंज से लड़ सकते हैं.

उधर इस सीट को लेकर राजद–लोजपा की राजनीति से जुड़े कई दावेदारों की मुहिम परवान चढ़ने लगी है. इसका सूत्रपात तीन माह पहले ख़ुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. राम बहादुर सिंह की जन्म भूमि हरपुर में जाकर कर दिया है. उन्होंने स्व. राम बहादुर सिंह को राजनीतिक संत की संज्ञा देते हुए उनके पुत्र इंजीनियर संजय सिंह को राजनीति संरक्षण देने की बात कही थी. इसके कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारण प्रवास के दौरान हरपुर गांव पहुंचकर स्व. राम बहादुर सिंह के आदर्शों की दुहाई देते हुए क्षेत्र की राजनीति को नए सिरे से हवा प्रदान कर दी. लालू प्रसाद ने गोपालगंज दौरे के क्रम में कई दफ़ा एकमा में अपना कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र की राजनीतिक माहौल को समय से पूर्व ही गति प्रदान कर दी है. इसी वज़ह से राजद दावेदारों की संख्या में इजाफ़ा हो गया है. इस क्रम में राजद खेमे से क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता व सारण ज़िला राजद के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र कुमार सिंह उर्फ़ भवानी मुन्ना की गतिविधियां ज़ोरों पर है. मुन्ना सांसद उमांशकर सिंह के करीबी सहयोगियों में से एक हैं. राजद खेमे से क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक व सांसद उमाशंकर सिंह के करीबी माने जाने वाले डॉ. एस कुमार भी राजद के सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर टिकट के दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. इसके अलावा लोजपा के प्रदेश सचिव व बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे देव कुमार सिंह अपनी ईमानदार व स्वच्छ छवि की बदौलत क्षेत्र की राजनीति को एक नया रूप देने के लिए मतदाताओं के बीच अभियान तेज कर दिए हैं. उनका कहना है कि गठबंधन की राजनीति में नवसृजित एकमा विधानसभा क्षेत्र लोजपा के खाते में आएगा. वह महाराजगंज सांसद उमाशंकर सिंह के अनुमंडलीय सांसद प्रतिनिधि भी हैं.

इस क्षेत्र से प्रबल दावेदार के रूप में सारण ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष व सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ़ मुन्ना सिंह का जनसंपर्क अभियान पूरे परवान पर है. उनका कहना है कि जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए अपने कार्यों की बदौलत उनका चुनाव लड़ना तय है. वह हर हाल में चुनाव लड़ने के मूड में हैं. अन्य दावेदारों में बसपा के एकमात्र दावेदार के तौर पर युवा नेता व क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार पटेल का भी नाम चर्चे में है. कांग्रेस के दावेदारों में प्रकाश सिंह उर्फ़ महेश सिंह, धनंजय सिंह, नरेंद्र प्रताप मिश्रा व एन पी सिंह कुंदन का नाम सामने आता है.

नए परिसीमन के तहत होने वाले आगामी विस चुनाव को लेकर सारण की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले कई दिग्गजों की निगाहें भी इस सीट पर लगी हुई हैं. महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की इस मामले में चुप्पी संभावित उम्मीदवारों के साथ ही मतदाताओं के बीच एक अबुझ पहेली बनी हुई है. वहीं कुछ प्रभावशाली उम्मीदवारों की चहलकदमी ने मांझी व बनियापुर क्षेत्र के कई सशक्त दावेदारों को परेशानी में डाल दिया है. जानकारों का कहना है कि नए परिसीमन में पहली बार होने वाले नवसृजित एकमा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान इतिहास दोहरा सकता है.

भवानी मुन्ना

देव कुमार सिंह

धनंजय सिंह

धूमल सिंह

डॉ. एस. कुमार

ई. संजय सिंह

महेश सिंह

उत्तम कुमार पटेल

विधानसभा क्षेत्र एकमा

feedback@chauthiduniya.com

प्यार की सज़ा हुक्का-पानी बंद

अरविंद नाथ तिवारी

एक प्रेमी युगल ने शादी क्या कर ली. गांव वाले उसके जान के दुश्मन बन गए. उसके परिजनों को गांव वालों ने जीना मुहाल कर दिया है. उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया है. उसके परिवार से गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है. आख़िर उस प्रेमी युगल का क़सूर क्या है. सिर्फ़ यही न कि उसने प्यार किया और उससे शादी कर ली है, तो क्या प्यार करने की उसे सजा मिली है. प्रेमी युगल पंचायत के फरमान के डर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं. यह घटना है वाल्मीकि नगर थाना के संतपुर गांव की. जहां की पंचायत ने इस नवविवाहित जोड़े पर एक लाख इक्कावन हज़ार रुपये जुर्माना के साथ ही गांव के अंदर हुक्का पानी तक बंद कर दिया है. एक बार फिर समाज के ठेकेदारों ने इन्हें निर्वासित जीवन जीने क लिए बाध्य कर दिया है. पंचायत और मुखिया का फरमान ही इस गांव में कानून की तरह है. पंचायत ने इस शादी को नाजायज़ करार दे दिया. पंचायत ने उसके परिजनों को धमकी दी है कि गांव से भागकर शादी करने वाले बेटा–पुतोहु को गांव की पंचायत में हाज़िर करो वरना तुम सबकी ख़ैर नहीं है. चौथी दुनिया ने गांव पहुंचकर छानबीन की तो पता चला कि भागने वाले प्रेमी का नाम इंद्रदेव मरदनिया और उसके पिता का नाम भिखारी मरदनिया हैं. लड़की का नाम फुलमती और उसके पिता का नाम रामचंद्र काजी है. फुलमती के माता–पिता से मिलना चाहा तो पता चला है कि घर पर कोई नहीं है. फिर इंद्रदेव मरदनिया के घर पर उसके पिता भिखारी मरदनिया से मुलाकात हुई. वह पंचायत के डर से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था. काफी हिम्मत देने के बाद उसने बताया कि दो माह पहले गांव के पंचायत ने मुझे बुलाया. पंचायत में गांव के उप मुखिया जगनारायण गुरु, बंशराज महतो गुमश्ता, धनराज महतो, बृजराज महतो, रामचंद्र काजी आदि उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का इंद्रदेव रामचंद्र काजी की लड़की को भगा ले गया है. दोनों को बुलाओ, नहीं तो इंद्रदेव की लाश भी हम मंगवा सकते हैं. तुम पर एक लाख इक्कावन हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इसके साथ ही गांव के अंदर तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद किया जाता है. गांव के कुएं से तुम्हार पानी पीना बंद किया जाता है. गांव का कोई दुकानदार तुमको सामान नहीं देगा. भीखारी की पत्नी रेशमी ने कहा कि मेरे दो लड़के हैं. इंद्रदेव बड़ा है. उसकी शादी दोन जंगल के शेरवा गांव में हुआ था. दो साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई और अपने पीछे दो वर्ष के बेटे दीपक को छोड़ गई. दीपक को गांव के लोग बिस्कुट तक दुकान से नहीं लेने देते हैं. मेरी दो बेटी भी है. बड़ी बेटी का नाम धनराजी और छोटी का नाम कनकलता है. भीखारी ने आगे बताया कि फुलमती ने पंचायत के सामने अपने पिता के पास रहने से इंकार कर दिया है. उसने बताया कि हम दोनों कोर्ट में शादी कर लिए हैं. फिर भी पंचायत का फरमान पूर्ववत जारी हैं. 13 अप्रैल को एसपी के जनता दरबार में उन्होंने अपनी सुरक्षा का गुहार और गांव से हुक्का पानी बंद करने के विषय में बताया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जब गांव की मुखिया गीरजा देवी के पति से मोबाइल पर बात हुई तो कहा कि जाति बिरादरी का मामला है. गांव के उपमुखिया जगनारण गुरु का कहना था कि अब किसी भी लड़की के जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे. इंद्रदेव बहुत खराब लड़का है. वह गांव की कई लड़कियों का जीवन तबाह कर चुका है.

यह कहने पर कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है तो उनका जबाब था कि दोनों झुठ बोलते हैं. अगर शादी की है तो पंचायत के समक्ष हाजिर होकर कागज क्यों नहीं दिखलाते. मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी छानबीन करे. इस मसले पर पुलिस मुख्यालय स्थित डीएसपी एसडी रजक का कहना था कि पुलिस के सामने मामला आया है. इस पर कार्रवाई की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड : औद्योगीकरण के नए युग का सूत्रपात

नवल किशोर सिंह

देश में मैन ऑफ स्टील के रूप में खास पहचान बना चुके भारतीय उद्योग जगत के शिखर पुरुष स्व. ओपी जिंदल के सपनों को साकार कर रहा है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. इसने हजारीबाग ज़िला अंतर्गत पतरातु में मेगा स्टील प्लांट लगाकर उद्योग जगत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने पिछले 24 अप्रैल को जिंदल कंपनी के नए स्टील प्लांट का उद्घाटन किया. इसके साथ ही सूबे में औद्योगीकरण के नए युग का सूत्रपात हुआ. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ऐसी पहली बड़ी कंपनी है, जिसने झारखंड में मेगा प्लांट लगाकर उत्पादन शुरू कर दिया है. टाटा स्टील, एचइसी और बोकारो स्टील के बाद जिंदल कंपनी ने इस्पात का बड़ा कारखाना स्थापित किया है. पतरातु प्रखंड के बलकुदरा में जिंदल ने झारखंड के औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय जोड़ दिया है. पहले चरण में छह मिलियन टन के वायर रॉड मिल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने किया. वायर रॉड मिल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यहां तार, छाते की कमानी, स्पोक, ट्रांसमिशन लाइन के तार आदि का उत्पादन होगा. पहले चरण में तीन एमटी का प्लांट लगाया गया है, जिसकी लागत करीब 15 हज़ार करोड़ रुपये है. झारखंड की जनता को जिंदल द्वारा समर्पित वायर रॉड मिल दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली आधुनिकतम मिल है. झारखंड राज्य के गठन के बाद जेएसपीएल के वायर रॉड मिल को पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है. पूरा प्लांट प्रदूषण रहित और स्वचालित है. इसकी विशेषता यह है कि यह भारत में सबसे कम क्षेत्रफल में लगाया जाने वाला स्टील प्लांट है. तीन मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को मात्र 550 एकड़ ज़मीन में लगाया गया है. बलकुदरा में जेएसपीएल प्रबंधन द्वारा बिजली के लिए कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है. यह पावर प्लांट स्टील मेकिंग में अनुपयोगी गैस द्वारा चलाया जाएगा. इसके लिए पानी की व्यवस्था नककरी डैम से की गई है. पूरे प्लांट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया गया है. कुल मिलाकर कहा जाए तो बलकुदरा में जिंदल का प्लांट लगने से उद्योग जगत में एक नई क्रांति आई है. देश के प्रख्यात उद्यमी, सांसद व जेएसपीएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक नवीन जिंदल ने अपने पिता व भारतीय उद्योग जगत के शलाका पुरुष स्व. ओपी जिंदल के सपनों को साकार करते हुए उद्योग जगत की नई इबारत लिख दी है. फलक को छूने के जिंदल के जज्बे का ही प्रतिफल है बलकुदरा का जेएसपीएल प्लांट. महज तीन वर्ष आठ महीने में जिंदल ने बीमार बासल को पुनर्जीवित कर दिया. वर्तमान में बासल जिंदल नगर के रूप में मशहूर हो चुका है. इस सफर की कहानी भी अनूठी है. 15 अक्टूबर 1997 को बासल फैक्ट्री बंद हो चुकी थी. 28 अगस्त 2006 में इस फैक्ट्री को खरीदने का टेंडर भरा. एक सितंबर 2006 को हाईकोर्ट में ओपन टेंडर हुआ, जिसमें 108.96 करोड़ रुपये की बोली लगाकर जेएसपीएल पहले स्थान पर रहा. सात सितंबर 2006 को बासल प्लांट जेएसपीएल का हो गया. 17 सितंबर 2006 को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नवीन जिंदल पहली बार बासल पहुंचे. 9 जनवरी 2007 को लिक्विडेटर ने बासल कंपनी का ताला खोलकर जेएसपीएल के हवाले कर दिया. 10 जनवरी 2007 को जेएसपीएल ने अपनी परंपरा के अनुरूप प्लांट के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया. 18 मार्च 2007 को 6 मिलियन टन क्षमता के प्लांट का शिलान्यास किया गया. इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित कई राजनैतिक हस्तियां मौजूद थीं. 19 मार्च 2010 से नवनिर्मित वायर रॉड मिल से उत्पादन शुरू हुआ और 24 अप्रैल 2010 को विधिवत उद्घाटन के बाद इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया. अक्टूबर 2010 से जेएसपीएल के रीबार मिल से भी उत्पादन शुरू हो जाने की पूरी संभावना है. इसकी तैयारी भी चल रही है. इस मिल की उत्पादन क्षमता 10 लाख टन प्रतिवर्ष होगी. बदहाल बासल की दशा बदलने में तकरीबन 10 वर्षों का समय लग गया, लेकिन दस वर्षों बाद जो दशा और दिशा बदली है वह ऐतिहासिक है. इस क्षेत्र के निवासियों की खुशियों की गठरी जिस विकास रथ पर सवार होकर आई है, उस रथ के सारथी देश के युवा उद्यमी नवीन जिंदल बने. जिंदल ने महज चार वर्षों की अल्पावधि में इस क्षेत्र के हताश एवं निराश निवासियों में आशा की नई किरणों का संचार किया और बदहाल बासल को विकास की नई रोशनी से जगमग कर जिंदल नगर में तब्दील कर दिया. क्षेत्र के लोगों के मुताबिक़ जिंदल ने जो कहा वह कर दिखाया.

उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह, उपमुख्यमंत्री रघुवर दास, सुदेश महतो, उद्योगमंत्री हेमलाल मुर्मु, श्रममंत्री उमाकांत रजक सहित कई अन्य जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं.

जन सहयोग में ही हमारी सफलता छिपी है : नवीन जिंदल

जेएसपीएल के वाइस चयेरमैन सह एमडी नवीन जिंदल ने प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि जनता के सहयोग और ख़ासकर स्थानीय ग्रामीणों के स्नेह से ही हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल हुए हैं. यह तो शुरुआत है. हमें अभी बहुत दूर तक जाना है. जन सहयोग में ही हमारी सफलता छिपी है. हमारा उद्देश्य महज़ कारखाना लगाना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास को प्रमुखता से देखना भी है. हम स्व. ओपी जिंदल के सपनों को साकार करने में जुटे हैं.

दूर तक जाएगी रोशनी : सुबोधकांत

केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि नवीन जिंदल का यह क़दम एक मिसाल है. उन्होंने जो चिराग जलाया है, उसकी रोशनी दूर तक होगी. जिंदल सही में जिंदादिली का दूसरा रूप है.

बदलाव ख़ुद के बूते लाना होगा : शिबू

प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने कहा कि समूह की भलाई के लिए गांव–गांव में लोगों को ख़ुद तत्पर होना होगा. अपनी तरक्की के लिए ख़ुद राह चुननी होगी. लोगों को अपने अंदर ऐसी काबिलियत लानी होगी कि वह औद्योगिक विकास में सहयोगी बनें. राज्य में उद्योग तो लग रहे हैं, लेकिन सही मायने में यहां के लोगों का विकास नहीं हो रहा है. उद्योग के साथ इलाक़े के विकास को प्राथमिकता देने का जिंदल का प्रयास सराहनीय है.

पारदर्शी नीति बने : वीरभद्र

केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा के समुचित उपयोग के लिए पारदर्शी नीति बनाने की ज़रूरत है. साथ ही क़ानून–व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखना होगा. देश में स्टील की मांग बढ़ी है. सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां स्टील उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सुर्ख़ियों में आने लगे हैं नए - पुराने चेहरे

नीरज कुमार

पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं. अब देर शाम तक गांवों में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. पुराने नेता जिनकी क्षेत्र में अपनी पहचान है, वे पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, लेकिन नए उत्साही युवा नेता चुनाव के पूर्व ही शुभकामनाओं का बैनर और पोस्टर लगवाकर मतदाताओं का दु:ख दर्द बांटते गांवों की पगडंडियों पर देर शाम चहलक़दमी करते नज़र आने लगे हैं. वैसे चक्रवात प्रभावित इस विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी करने का बाजार गर्म है. अधिकतर प्रत्याशी देर शाम तक जनता से उनका दु:ख दर्द सुनते हैं, वहीं रात में पार्टी के आलाकमान से टिकट देने की गुजारिश करते हैं. इनमें से अधिकतर नेताओं का कहना है कि जनता ने इस बार उन्हें मौक़ा दिया तो क्षेत्र के विकास व कायाकल्प करने के लिए वे अपनी पूरी ताक़त झोंक देंगे. नए परिसीमन के तहत होने वाले चुनाव में लिहाज़ा अभी से ही उम्मीदवार रणनीति बनाने में जुट गए हैं. यहां से विगत चुनाव में भाजपा के प्रदीप दास ने राजद के अफाक आलम को हराया था. वर्ष 2000 में अफाक आलम ने ज़िला परिषद की सदस्यता छोड़कर कसबा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ. वहीं 2005 फरवरी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें विजय मिली, लेकिन राज्य में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को विधानसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण उनको विधायक के पद से हाथ धोना पड़ा. पुन: 2005 के चुनाव में राजद के प्रत्याशी के रूप में उन्हें दूसरा स्थान मिला. आने वाले चुनाव के संबंध में उनका कहना है कि वर्तमान में वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिससे कांग्रेस से टिकट मिलना उन्हें लगभग तय है. मैंने अपने क्षेत्र की जनता का लगातार नि:स्वार्थ सेवा किया है, जिसका फल जनता मुझे जरूर देगी, लेकिन वर्तमान में पुराने चेहरे के अलावा कई चर्चित युवा प्रत्याशियों के नाम उभरकर सामने आ रहे हैं, जिनमें नवीन सिंह कुशवाहा, मो.शहनवाज आलम, संजय मिर्धा आदि प्रमुख हैं. नवीन सिंह कुशवाहा ने पूर्णिया लोकसभा से विगत चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी. परिणामस्वरूप कसबा विधान सभा पर उनकी पैनी नज़र है. स्थानीय मतदाताओं के अनुसार अभी हाल में आए चक्रवातीय तूफान प्रभावित परिवारों को मदद व लगातार विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा मतदाताओं के मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा कर रही है. नवीन सिंह कुशवाहा का कहना है कि वर्तमान राजनीति में ईमानदार युवाओं की मांग है, पुराने नेताओं के कोरे आश्वासन से जनता का मोह भंग हो चुका है अत: जनता की आशा अब मुझ जैसे युवाओं पर आ टिकी है. उनका कहना है कि मैंने निर्दलीय या किसी राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है. वैसे धमदाहा व सदर पूर्णिया के स्थानीय मतदाता इन दोनों विधान सभा में से किसी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में समय आने पर सोचा जाएगा. कसबा विधानसभा से युवा जुझारू, कर्मठ उम्मीदवार के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी से मो. शहनवाज आलम का नाम उभर कर सामने आ रहा है. शहनवाज के समर्थन में पूर्णिया लोजपा के ज़िलाध्यक्ष माधव सिंह का कहना है कि स्थानीय जनता में उनकी अपनी अलग पहचान है. लोजपा से उनको टिकट मिलना तय है, वहीं कुछ स्थानीय जनता का कहना है कि राजनिति में शहनवाज जैसे युवा कर्मठ एवं स्वच्छ छवि वाले नेताओं को जगह मिलनी चाहिए. ख़ुद शहनवाज का कहना है कि मैंने बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा के लिए राजनीति में क़दम रखा है. वैसे नेताओं से अब मतदाता भी दूरी बनाने लगे हैं, जो सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीति करते हैं. अत: आने वाले चुनाव में रामविलास के स्वच्छ छवि से प्रेरित होकर मैंने जो अपनी दावेदारी पेश की है, उसमें स्थानीय जनता का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा. वहीं कांग्रेस से टिकट की दावेदारी में युवा प्रत्याशी संजय मिर्धा का नाम चर्चा में है. मिर्धा का कहना है कि मैं विगत 15 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं. मैंने कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर 5 नवंबर 2009 को प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया और लगभग 7000 व्यक्तियों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराया. युवा कांग्रेस अध्यक्ष नदीम जावेद के कार्यों में मैंने सहयोग किया. मेरे कार्यों से बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. खालीद रसीद सवा, बिहार कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद खान और कनवेनर नुरुलहोदा प्रभावित हैं. विगत दिनों आए चक्रवाती तूफान से हुए जान–माल के नुक़सान का जायजा लेकर राहत कार्यों में मैंने अपनी तरफ से भी सहयोग किया. आज कसबा विधानसभा की जनता मेरी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है. वहीं कुछ स्थानीय जनता और उनके समर्थकों का कहना था कि कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए, जिससे कि उनके नेतृत्व में कसबा विधानसभा में विकास की गंगा बह सके.

मो.शहनवाज आलम

नवीन सिंह कुशवाहा

अफाक आलम

संजय मिर्धा

विधानसभा क्षेत्र कसबा

feedback@chauthiduniya.com

मोनालिसा की मौजूदगी के बावजूद फ़िल्म में उनकी अदाओं का जादू कम नहीं पड़ा. हालांकि लवी शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज थीं.

एड्स से भी ख़तरनाक रहस्यमय बीमारी

बिहार में एक अजीबोग़रीब बीमारी का मामला सामने आया है. बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसके हाथ खराब हो जाते हैं और कुछ समय बाद उसे लकवा मार जाता है. फिर उसके पूरे शरीर पर फोड़े होने लगते हैं. बच्चा तो जिंदा रहता है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी जो मौत से भी बदतर हो जाती है.

मां किरण देवी के साथ विकलांग बच्चें.

एक ऐसी बीमारी जो एड्स से कम ख़तरनाक नहीं है. क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी कुछ करने लायक नहीं बचता है. इसकी गिरफ्त में आए लोग पहले शरीरिक तौर पर और फिर मानसिक तौर पर विकलांग हो जाते हैं. यह बीमारी वहां के डॉक्टरों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है. यह मामला है मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी प्रखंड के अंधेरी ग्राम का.

यह व्यथा है मधुबनी ज़िला के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के अंधेरी ग्राम के एक परिवार की. अपने चार बच्चों को अपनी आंखों के सामने एक–एक कर विकलांग होते देख मां किरण देवी ख़ुद को असहाय महसूस करती है. उसका पति मिथिलेश मजदूरी कर किसी तरह दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं. इलाज के लिए पैसा जुटाने में वो ख़ुद को असक्षम और नि:सहाय महसूस करते हैं. सबसे बड़ा बेटा चंद्र कुमार झा महज़ ग्यारह वर्ष की उम्र से ही आंशिक रूप से विकलांग होने लगा. अब चंद्र इक्कीस वर्ष का हो गया है, लेकिन शारीरिक रूप से पूरी तरह विकलांग हो चुका है. शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग चंद्र आज सिर्फ़ पानी पीकर जी रहा है. शरीर पर बड़े–बड़े घाव निकल आए हैं. छोटी बहन अर्चना 19 एवं आशा 17 वर्ष की है. ये दोनों बहनें तो किसी तरह भोजन तो कर पाती हैं, लेकिन विकलांगता उन पर इस कदर हावी है कि ये दोनों चलने में भी असमर्थ हो चुकी हैं. सबसे छोटी बेटी इंद्रा कुमारी 13 साल की है. वह भी अब चलने–फिरने में भी परेशानी महसूस कर रही हैं. अब सवाल उठता है कि आख़िर वह कौन सी बीमारी है, जो बढ़ती उम्र के साथ इस परिवार की खुशियों को निगलती जा रही है. इस सवाल का जवाब आम लोगों के लिए रहस्य और चिकित्सकों के लिए चुनौती बन गई है.

स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर दरभंगा चिकित्सा अस्पताल तक का दरवाज़ा खटखटा चुकी किरण देवी डाक्टरों की दलील से नाख़ुश हैं. उन्हें अब तक यह समझ में नहीं आया कि क्यों ग्यारह वर्ष की एक निश्चित उम्र पूरा करते ही उनके स्वस्थ्य बच्चे विकलांग होने लगते है. पिता मिथिलेश झा अपनी ग़रीबी के सामने विवश हैं. उन्हें सरकारी सहायता मिलने की आशा है, लेकिन अब तक उसे सहायता नहीं मिली है. बीपीएल परिवारों की सूची में दर्ज़ इस परिवार को किसी भी तरह की सरकारी सहायता न मिलने का भी मलाल है. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इस बीमारी से निपटने के लिए अब तक विशेष कार्य की योजना तैयार क्यों नहीं की गई? आख़िर क्यों चिकित्सा पदाधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नज़र आते हैं? इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेनीपट्टी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आर के सिंह दावा करते हैं कि इस बीमारी का नाम ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि संतुलित आहार की कमी तथा वंशानुगत प्रभाव के कारण होता है. वहीं मधुबनी ज़िला के सिविल सर्जन डा. एम. शब्बीर अहमद का कहना है कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है. इस तरह की बीमारी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है. पीड़ित परिवार को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. इस संबंध में प्रमंडलीय स्वास्थ्य सेवा के दरभंगा क्षेत्र के उप निदेशक डॉ. रामेश्वर साफी ने हर संभव चिकित्सा मुहैया कराए जाने की बात कही है. उन्होंने विशेष टीम गठित करने का निर्देश जारी करते हुए भौगोलिक परिवेश की जांच का भी आदेश दिया है.

भारतेंद्र
feedback@chauthiduniya.com

स्वच्छता अभियान की हवा निकली

संपूर्ण राज्य को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया स्वच्छता अभियान एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान कोसी प्रमंडल के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल ज़िले में दम तोड़ती नज़र आ रही है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की यात्रा के बाद विभागीय स्तर पर जिस गति से इन योजनाओं का कार्यान्वयन होना चाहिए, इसका कार्यान्वयन उस तरीके से नहीं हो सका है. इस यात्रा के दौरान आनन–फानन में जहां–तहां शौचालयों का निर्माण करवाकर विभागीय दलाल, ठेकेदार और माफिया सरगना मालामाल हो गए हैं.

बताते चलें कि 2006 में शुरू हुआ संपूर्ण स्वच्छता अभियान कोसी प्रमंडल के तीनों ज़िले के सुदूर गांवों आज तक धरातल पर नहीं उतर सका है, जबकि सरकार के द्वारा सहरसा ज़िले के तीन पंचायत पहाड़पुर (सिमरी बख्तियारपुर), पटुआहा (कहरा) एवं बड़सम (सोनवर्षा) को निर्मल ग्राम घोषित कर वहां के ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को पुरस्कृत भी किया गया है, लेकिन हाल यह है कि इन पंचायतों में लाखों की राशि ख़र्च होने के बावजूद आज भी महिला, पुरुष, वृद्ध और बच्चे खुले मैदान में शौच करने को विवश हैं, जबकि इन तीनों पंचायतों में इस योजना के तहत पैसा को पानी की तरह बहाया गया है. विभाग का दावा है कि 1501 शौचालयों का निर्माण हुआ है. पर हाल यह है कि बीपीएल परिवारों के घर में शौचालय नज़र नहीं आ रहा है. अगर कहीं शौचालय दिख रहा है तो वह प्राय:

शौचालय का हाल

अनुपयोगी ही है. खासकर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड की पहाड़पुर पंचायत की हालत यह है कि शौचालय निर्माण हेतु लाई गईं सीटें यहां–वहां पड़ी मिल सकती हैं. गांव के एक टोले में एक ही स्थान पर सैकड़ों सीटें रखी हुई हैं. इस योजना के तहत शुरू में 15 सौ रुपये की राशि में एक शौचालय का निर्माण कराना था. कई पंचायतों के मुखिया को एक लाख 20 हज़ार की अग्रिम राशि भी दे दी गई, लेकिन हक़ीक़त यह है अब तक एक भी शौचालय नहीं बनाए गए हैं. अब पुन: लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2500 रुपये में शौचालय बनाए जा रहे हैं. मगर, आवंटन समय पर नहीं होने के कारण निर्माण कार्य में जुटे ग़ैर सरकारी संगठन भी सुस्त पड़ गए हैं. इस योजना पर 18 जुलाई 2007 से 31 मार्च 2009 तक 2 करोड़ 29 लाख 2 हज़ार 968 रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर शौचालयों की संख्या नगण्य है. यहां तक कि अपने काग़जी सबूतों को मजबूत बनाने के लिए पंचायतों में कुछ लोगों को शौचालय की सुविधा मुहैया करवाई गई है. उनका नाम संचिकाओं में वर्णित है, लेकिन सरकारी अक्षमताओं पर आधिकारीगण चुप हैं. क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं. ग़ौरतलब है कि कई लोगों को मनमाने ढंग से प्रोडक्शन सेंटर मिला, वे भी सरकार को समय पर राशि उपलब्ध नहीं करा सके. जब तक इस योजना को अभियान का रूप नहीं दिया जाता, तब तक उसकी सफलता पर प्रश्न चिह्न लगता रहेगा. इंजीनियर राम अयोध्या ठाकुर कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव, ज़िला जल एवं स्वच्छता समिति सहरसा का कहना है कि ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया था, लेकिन जो काम में शिथिलता बरत रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है और अब नए संगठनों से काम कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं.

एस.सोनी
feedback@chauthiduniya.com

लवी का फ़िल्मी फंडा

आमतौर पर यह माना जाता है कि मल्टीस्टारर फ़िल्मों में काम करने से कोई भी अभिनेत्री लाइमलाइट में नहीं आ पाती हैं. इसलिए ज़्यादातर अभिनेत्रियां उन्हीं फ़िल्मों में काम करती हैं, जिसमें सिर्फ़ उनके ही जलवे दिखाई दें, लेकिन भोजपुरी फ़िल्मों की ग्लैमडॉल और सेंसेशनल ब्यूटी लवी रोहतगी की बात ही अलग है. इस संदर्भ में उनकी राय जरा हट के है. उनका मानना है कि जिन फ़िल्मों में ज़्यादा स्टारर्स होते हैं, उनमें काम करने का अपना अलग ही मजा है. इन फ़िल्मों में बड़े स्टार्स के साथ काम करने का अनुभव मिलता है. इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको जमे हुए स्टार्स के बीच अपनी प्रतिभा दिखाने का मौक़ा मिलता है. वैसे लवी का कहना काफी हद तक सही भी है. उनकी कुछ फ़िल्मों पर नज़र डालें तो ज़्यादातर फ़िल्में मल्टीस्टारर ही रही है. चाहे वह रवि किशन, विनय आनंद और मोनालिसा स्टारर फ़िल्म खटाईलाल मिठाईलाल हो या फिर कमाल ख़ान और मोनालिसा अभिनीत मुन्ना पांडे बेरोज़गार हो. ग़ौरतलब है कि इन दोनों ही फ़िल्मों में भोजुपरी फ़िल्मों की सेक्सी बाला मोनालिसा लवी की कोस्टार थीं. मोनालिसा की मौजूदगी के बावजूद फ़िल्म में उनकी अदाओं का जादू कम नहीं पड़ा. हालांकि लवी शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज थीं. कुछ लोगों ने उनको मशविरा भी दिया था कि करियर के शुरुआती दौर में अगर वह बतौर लीड एक्ट्रेस काम नहीं करेंगी तो फिर वह साइड आर्टिस्ट बनकर ही रह जाएंगी. पर लवी ने रिस्क लिया और आज उनका नाम भोजपुरी फ़िल्मों की खूबसूरत और ए क्लास अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार किया जाता है. लवी आगे भी ऐसी फिल्मों में काम करने से परहेज नहीं करेंगी, जिसमें उनका साइड रोल हो या आइटम सांग. लवी के इस क़दम से निर्माता निर्देशक तो ख़ुश होंगे ही. अब कुछ अभिनेत्रियों को उनसे सबक लेने की ज़रूरत है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 10 मई–16 मई 2010

www.chauthiduniya.com

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

उमा भारती

वापसी की राह आसान नहीं

एक वह भी दिन था, जब साध्वी उमा भारती भाजपा के ताक़तवर नेताओं में शुमार होती थीं. प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में ख्याति अर्जित करने वाली उमा केंद्रीय मंत्री बनीं, फिर मध्य प्रदेश जैसे सूबे की मुख्यमंत्री. वक़्त की मार देखिए, आज पार्टी में उनका कोई नामलेवा नहीं बचा. वह घर वापस होना चाहती हैं, लेकिन घरवाले नहीं चाहते कि ऐसा हो.

संध्या पांडे

मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उमा भारती फैक्टर की चर्चा ज़ोरों पर है. भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य सरकार का हर नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि उमा की वापसी मध्य प्रदेश की राजनीति को किस हद तक अस्थिर कर सकती है. उमा ने अपनी स्वयं की पार्टी से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में वापसी के अंतिम प्रयास शुरू कर दिए हैं. कभी देश में एक तूफ़ानी नेता के रूप में ख्याति अर्जित करने वाली उमा इन दिनों हाशिए पर हैं. भाजपा को राज्य में सत्ता सौंपने वाली उमा भारती के साथ आज किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता खड़ा नहीं होना चाहता. उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस लौटेंगी या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी स्वयं के स्थापित तंत्र को अस्थिर कर उमा की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी? जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पिछले एक माह से भाजपा स्वयं खोज रही है. प्रदेश स्तर पर उमा के विरोध में एक आंधी चल रही है. राज्य का कोई भी नेता यह नहीं चाहता कि उमा भारती प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भाजपा का झंडा थामे. राज्य की राजनीति में उमा की वापसी एक बड़ी अस्थिरता का संकेत है.

उमा भारती ने वर्ष 2003 में भाजपा को दिग्विजय सिंह के विरुद्ध सत्ता में लाने का काम किया था. राजनीतिक हालात यह संकेत देते हैं कि उमा की अनुपस्थिति में वर्ष 1998 की तरह ही एक बार फिर बाजी राजनीतिक प्रबंधन के ज़रिए दिग्विजय सिंह के पक्ष में जानी थी. अचानक राजनीतिक परिदृश्य में उमा भारती की उपस्थिति ने भाजपा के स्थापित नेताओं के सारे समीकरण बदल दिए थे. उमा भारती ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रमुखता देते हुए वरिष्ठ नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित राजनीति को न सिर्फ़ रोका था, बल्कि राज्य में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया था. गांव से लेकर शहर स्तर तक के कार्यकर्ता सरकार के विरोध में उमा भारती के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे. वर्ष 2009 में राज्य ने उमा भारती को जन नेता के रूप में स्वीकार करते हुए बहुमत की सरकार उनके हवाले की. उमा भारती बतौर मुख्यमंत्री अपने छह माह के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक मर्यादा, शुचिता एवं ईमानदार कठोर प्रशासन की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकीं. इस दौरान परिवारवाद के भरोसे उमा भारती भ्रष्टाचार के दलदल में इस तरह गिर गईं कि उन्हें एक मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर पाना राजनीतिक मर्यादाओं के प्रतिकूल था. उन्होंने राज्य में प्रशासन तंत्र का मनोबल तोड़ना और भाजपा की रीतियों–नीतियों को सार्वजनिक मंच से नकारना शुरू कर दिया. भाजपा के बड़े नेता उमा भारती के विरुद्ध किसी उपयुक्त मौक़े की तलाश में थे.

पद से हटने के साथ ही राजनीति में उमा भारती के दिन ख़राब हो गए. जन नेता के रूप में ख्याति पाने वाली उमा अपने बड़बोलेपन और अति आत्मविश्वास के चलते भाजपा के शीर्ष नेताओं से सीधे भिड़ गईं. उन्होंने राज्य में स्वयं के बल पर एक नए राजनीतिक दल का गठन किया. अब उमा भारती उस दल को छोड़कर भाजपा में वापसी का मार्ग खोज रही हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य में उमा की ज़रूरत उन्हें कहीं नहीं है. वास्तव में उमा भारती स्वयं अब मध्य प्रदेश में आधारहीन हो चुकी हैं. एक आंधी के रूप में प्रदेश में स्थापित उनकी ख्याति पारिवारिक विवादों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समाप्त हो चुकी है. उमा के सामने अब कोई विकल्प शेष नहीं है कि वह सिर झुका कर, भाजपा हाईकमान से माफी मांगकर और अपने गुरु समेत संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का दबाव बनाकर किसी तरह पार्टी में वापस लौटें. कहा जा रहा है कि उमा की वापसी से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अस्थिर हो सकती है. पिछले सात सालों से चल रही राज्य सरकार से असंतुष्ट भाजपाइयों की संख्या कम नहीं है. उमा भारती की वापसी राज्य में एक नए खेमे को जन्म देगी, जिस पर स्वयं उमा की निगाहें टिकी हुई हैं. असंतोष के स्वर बढ़ने के साथ–साथ राज्य सरकार के संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. भाजपा सरकार वर्तमान में कैलाश विजयवर्गीय सहित कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार और कदाचरण की समस्या से जूझ रही है. सरकार के पास अधिकारियों को नियंत्रित करने और प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए वैचारिक संसाधनों का अभाव है. भाजपा के प्रदेशस्तरीय नेताओं के बीच असंतोष का एक ज्वालामुखी धीरे–धीरे सुलग रहा है. इस बात से प्रदेश के मुखिया भी वाक़िफ़ हैं. इन स्थितियों में उमा भारती की वापसी भाजपा के लिए वरदान नहीं, अभिशाप ही सिद्ध होगी. वैसे भी राज्य में ऐसे किसी आंदोलन की रुपरेखा नहीं बनाई जा रही, जिसमें उमा भारती की मंच पर उपस्थिति अनिवार्य हो. पार्टी सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के चुनावों को सामने रखकर हिंदूवादी छवि की सुरक्षा के लिए उमा भारती को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है. राम मंदिर आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ीं उमा भारती उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू वोटों को प्रभावित करने के लिए अपनी विशिष्ट भाषण शैली का इस्तेमाल कर सकती हैं. भाजपा को यह लगता है कि संघ की बात न मानना भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़े संकट का कारण बन सकता है.

मध्य प्रदेश के नेताओं का मत है कि यदि भाजपा हाईकमान को उमा भारती की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है तो उनके लिए पार्टी में वापसी का मार्ग उसी राज्य से तैयार किया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश जीतने के प्रयास में मध्य प्रदेश को दांव पर लगा देना राजनीतिक समझदारी नहीं मानी जा सकती. दल के केंद्रीय नेतृत्व में बैठे कई नेता भी उमा भारती को मौजूदा राजनीति में अहम नहीं मानते. यह सोच विकसित हो रही है कि उमा भारती के साथ अब जनसैलाब नहीं, बल्कि इतनी बदनामी और समस्याएं आएंगी, जिनसे निपट पाना राज्य स्तर पर संभव नहीं है. उमा भारती ने स्वयं द्वारा निर्मित भारतीय जनशक्ति पार्टी को छोड़ दिया है. भाजपा के पूर्व चिंतक गोविंदाचार्य भी उमा की सक्रियता के लिए प्रयासरत हैं. भाजपा हाईकमान यह समझ नहीं पा रहा है कि मध्य प्रदेश से उठने वाले विरोध को वह अनुशासन की किस तलवार से दबा सकता है. उमा भारती भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक चरित्र बन चुकी हैं. उनका धार्मिक चरित्र भी राजनीति में आने के बाद एक सांप्रदायिक रंग ले चुका है. इन स्थितियों में सीमित विकल्प के सहारे उमा भारती अपनी नई राजनीतिक पारी के लिए किसी उपयुक्त मंच की तलाश में बार–बार भाजपा के दरवाज़े पर ही दस्तक़ देने के लिए बाध्य हैं. यह बात अलग है कि इस बार उनका स्वागत करने के स्थान पर उन्हें धकेलने वालों की संख्या कहीं अधिक है.

उमा भारती को सबसे अधिक नुकसान उनके नासमझ सलाहकारों एवं परिवारीजनों ने ही पहुंचाया. अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उमा भारती भाई स्वामी प्रसाद लोधी एवं भतीजे सिद्धार्थ पर नियंत्रण रख पाने में अक्षम रहीं. वहीं दूसरी ओर राजनीति की बाराहखड़ी भी न समझने वाले सलाहकारों ने उमा भारती के लिए राजनीति को एक मंडी बना दिया. इसी समूह ने उनकी सरकार को ठेकेदारी, तबादले और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया. उमा ने स्वयं कभी प्रदेश की राजनीति को क़रीब से नहीं देखा था. केंद्रीय स्तर पर राज्यमंत्री रहीं उमा भारती के लिए राज्य की राजनीति एक खिलवाड़ बन चुकी थी. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस की सत्ता से

शिवराज सिंह चौहान

अलग हुए मठाधीश नई सरकार को अस्थिर करने का उपयुक्त मार्ग खोज ही रहे थे. इसी दौरान बारीक़ से बारीक़ घटनाएं मीडिया में टिप्पणी का माध्यम बनती रही. नतीजतन, जिस जनता ने उमा भारती को अपना नेता मानकर कमान सौंपी थी, उसे भी महसूस होने लगा कि राज्य की सत्ता एक कमज़ोर शख्स के हाथों में जा चुकी है. उमा भारती के विरोध के लिए उनके ही दल के संगठन में बैठे नेता भी निरंतर प्रयासरत थे. लेकिन, स्थितियों को देखते हुए कोई यह कह पाने में सक्षम नहीं था कि इस सत्ता को चुनौती दी जानी चाहिए. एक बार उमा भारती ने क़ानूनी प्रकरण के कारण जैसे ही सत्ता छोड़ी, वापसी के सभी मार्ग तत्काल बंद कर दिए गए. उमा भारती द्वारा नाराज़गी में शुरू की गई राम–रोटी यात्रा एक राजनीतिक शिगूफा बनकर रह गई. यहीं से उमा के पतन की शुरुआत हो गई, जो मीडिया के सामने लालकृष्ण आडवाणी को खुली चुनौती देने के साथ नए दल के गठन के रूप में समाप्त हुई. उमा भारती मध्य प्रदेश के लिए अब भाजपा की आवश्यकता नहीं है. वर्तमान में चल रहे शासन तंत्र में उमा की उपयोगिता न के बराबर है. भाजपा हाईकमान यदि साध्वीनुमा इस युवा नेता को किसी अन्य राज्य में उपयोग के लायक मानता है तो उसे स्वयं कोई नया मार्ग तैयार करना होगा.

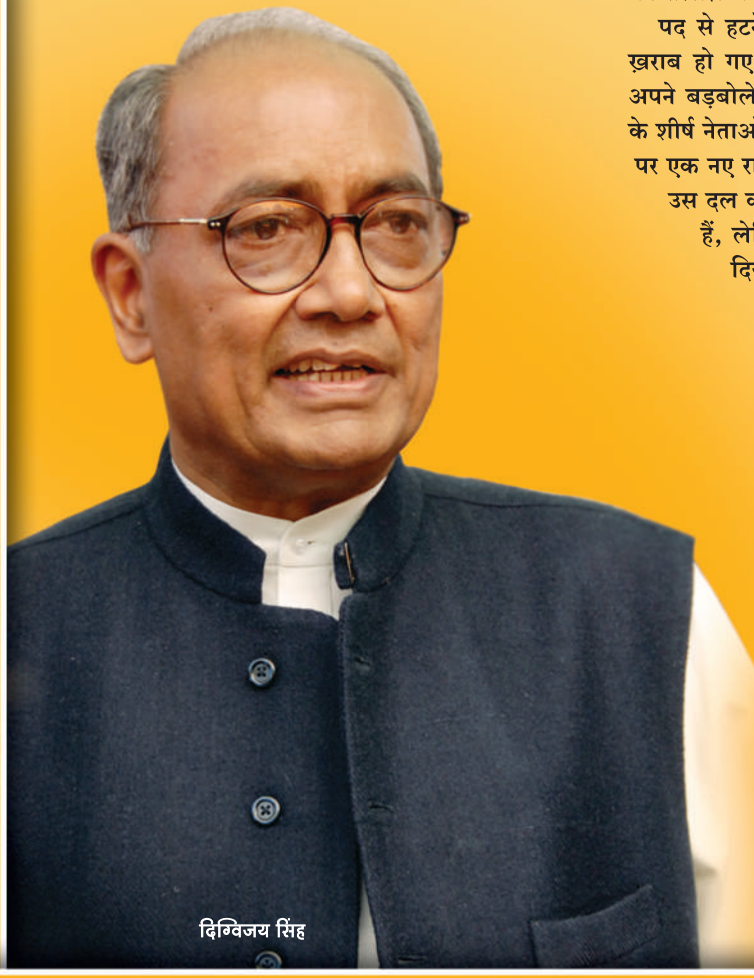
दिग्विजय सिंह

feedback@chauthiduniya.com

पिछले दिनों राज्य के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के प्रवास के दौरान भी इन समस्याओं से निपटने की दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया.

सार-संक्षेप

मध्य प्रदेश-अंधेर नगरी, चौपट राजा

मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी अजूबा नहीं है. हाल ही में खंडवा के विकास आयुक्त कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्टेनो ने 32 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर उनसे लाखों रुपयों की अवैध कमाई कर ली, लेकिन मामला प्रकाश में आते ही इसे दबा दिया गया. खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 14 नवंबर 2008 को विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त के नाम से एक आदेश जारी हुआ, इसमें कहा गया था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर आवेदकों को सूची के अनुसार वेतनमान एवं पदांकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है. इस सूची में चार सुपरवाइजर, 24 सहायक तथा 4 भृत्यों की नियुक्ति के आदेश निकाले गए. नियुक्ति पाने वाले सभी खंडवा के निवासी थे और सभी को खंडवा में ही नियुक्ति मिली. लेकिन जब ये कर्मचारी नौकरी करने कार्यालय पहुंचे तब फ़र्ज़ीवाड़ा उजागर हुआ, लेकिन इस मामले को चुपचाप दबा दिया गया. ठगे गए बेरोज़गारों का गुस्सा शांत करने के लिए फ़र्ज़ीवाड़ा करने वाले स्टेनो को कार्यालय से हटा दिया गया, लेकिन इस धोखाधड़ी और सरकारी ठगी के मामले की शिकायत भोपाल में विकास आयुक्त कार्यालय को भी नहीं की गई और न ही पुलिस में इस बारे में कोई रिपोर्ट लिखाई गई. ठगी के शिकार युवकों का कहना है कि नौकरी देने के एवज में स्टेनो रमन ने उनसे 15 से 25 हज़ार रुपये तक वसूले हैं. जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की. अब बताया जाता है कि मामले की दफ्तर में ही छानबीन की जा रही है.

सरकारी विवाह में फ़र्ज़ी दुल्हनें

मध्यप्रदेश सरकार की कन्यादान योजनाएं शुरू से ही अफसरों और कर्मचारियों के घपले, घोटालों और फ़र्ज़ीवाड़े के लिए बदनाम रही हैं. लेकिन इस योजना में आज तक सुधार नहीं हुआ है. अब भी विवाहों की संख्या बढ़ाने और सरकारी प्रोत्साहन राशि में घपला करने के लिए फ़र्ज़ी विवाह रचाए जाते हैं और मुख्यमंत्री को भी धोखे में रखा जाता है. हाल ही में बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी में आयोजित कन्यादान योजना में 207 जोड़ों का पंजीकरण किया गया. इनका विवाह सरकारी कन्या विद्यालय के प्रांगण में भव्य समारोह आयोजित कर संपन्न कराया गया. सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़ों को अफसरों ने उपहार वितरित किए. उपहार वितरण के समय एक नवविवाहिता पर उसकी जान पहचान वाले की नज़र पड़ी, तब उसने तुरंत अफसरों को बताया कि यह दुल्हन कुंवारी नहीं, बल्कि तीन बच्चों की अम्मा है और उसने अपने पति के साथ केवल सरकारी उपहार और धनराशि पाने के लिए कर्मचारियों की मिली भगत से कन्यादान योजना में हिस्सा लिया है. यह भी पता चला है कि 207 में से 6 युवतियां ऐसी थीं जो पहले से विवाहित हैं और गर्भवती भी हैं.

मंत्रियों को चाहिए नए एयर कंडीशनर

गर्मी के मौसम में दिन में सूरज आग बरसा रहा है और मध्य प्रदेश के प्रायः सभी गांव और शहरों में भीषण गर्मी से जनता त्रस्त है. पानी और बिजली की कमी ने जनता की परेशानी और भी बढ़ा दी है, लेकिन इसके राज्य में जनता की सरकार को सबसे ज़्यादा चिंता अफसरों और मंत्रियों की सुख सुविधा की ही है. राज्य में बिजली की बचत और सरकारी ख़र्च में मितव्ययता के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 13 अगस्त 2009 को राज्य मंत्रालय में सभी अफसरों और मंत्रियों के एयर कंडीशनर बंद करा दिए थे. बरसात और सर्दी में तो मंत्रियों और अफसरों ने बिना एयर कंडीशनर के काम चला लिया, लेकिन गर्मी आते ही सबसे पहले आईएएस अधिकारियों ने अपने कक्षों में बंद पड़े एसी चालू करने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया. मंत्रीमंडल की बैठक में सबसे पहले अफसरों ने यह मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री ने एयर कंडीशनर चालू करने के आदेश दे दिए. एयर कंडीशनर चालू तो हो गए हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनकी हालत बिगड़ चुकी है. कई एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं करते हैं तो कई अचानक बंद हो जाते हैं. अब मंत्री और अफसर मिलकर अपने लिए सैकड़ों की संख्या में नए एयर कंडीशनर ख़रीदना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि पुराने एयर कंडीशनर चलाने से बिजली ज़्यादा ख़र्च होती है, इसलिए बिजली की बचत के लिए नए एसी ख़रीदे जाने चाहिए. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बात को मान लिया है और पहली किस्त में मंत्रियों के कक्षों में नए एयर कंडीशनर लगाने पर विचार भी किया गया है. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री के. एल. अग्रवाल ने माना है कि बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लगाना ज़रूरी है, इसलिए पुराने एयरकंडीशनरों को बदला जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किसान पुत्र का राज और किसान आंदोलन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ख़ुद को किसान पुत्र कहते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें सूबे के किसानों की दयनीय हालत का अंदाज़ा नहीं है. अगर उन्हें वास्तव में किसान पुत्र होने के सही मायने समझने हैं तो पिछले कुछ सालों से बढ़ते किसान आंदोलनों पर गौर करने की ज़रूरत है.

मध्य प्रदेश सरकार की कृषि और किसान हितैषी नीतियों की पोल राज्य में हर साल होने वाले किसान आंदोलनों से खुल जाती है. राज्य सरकार ने किसान आंदोलनों का लाठी-गोली से दमन तो किया, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. स्वयं को किसान पुत्र कहलवाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस प्रायोजित किसान संगठनों के सम्मेलन को किसान महापंचायत का नाम देकर किसानों के समर्थन में हवा बनाई और सफलता भी हासिल की, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य में खेती पिछड़ी है और किसान बदहाल हैं. विशेषकर लघु और सीमांत किसानों की हालत दयनीय हो गई है. बड़े शहरों के निकट के कई गांवों में छोटी जोत के किसान खेती अलाभकारी होने के कारण अपनी भूमि बेचकर अन्य व्यवसायों में लग गए हैं. ऐसे भी अभागे किसान भी हैं, जो किसी कारण ज़मीन न बेच पाने की स्थिति में रोज़ी-रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए हैं.

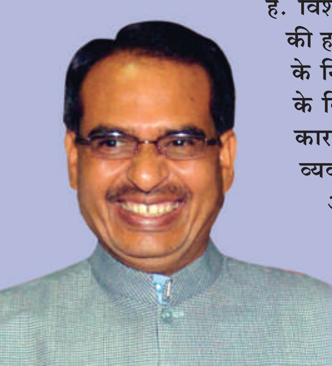

राज्य में बिजली संकट को चुनावी मुद्दा बनाने के बाद सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के कोई प्रयास नहीं किए. इस कारण राज्य में घोर बिजली संकट है और इससे सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए समय पर उन्हें बिजली नहीं मिल पाती. इसलिए राज्य में कई जगह छोटे-बड़े किसान आंदोलन हुए हैं. इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की कमी के कारण भी किसानों ने आंदोलन किए और कई स्थानों पर तो लूट भी की. गृह विभाग द्वारा हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा हुआ है. किसान पहले से ही बिजली और पानी के लिए परेशान हैं, उस पर सरकार किसानों को आंदोलन पर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005 में जहां केवल 67 किसान आंदोलन हुए, वहीं वर्ष 2009 में 206 बार किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी. किसान आंदोलन विभिन्न कारणों से हुए, लेकिन समस्याएं आज भी जस की तस हैं. यही हाल श्रमिक आंदोलनों का है. वर्ष 2005 में 164 श्रमिक आंदोलन हुए, लेकिन वर्ष 2009 में इन आंदोलनों की संख्या 252 हो गई. कर्मचारी आंदोलनों का भी यही हाल है. वर्ष 2005 में प्रदेश भर में 314 कर्मचारी आंदोलन हुए, वर्ष 2009 में इनकी संख्या 548 हो गई.

वर्ष 2009 में किसान समस्याओं को लेकर हुए उग्र आंदोलनों को दबाने-कुचलने के लिए पुलिस ने 35 बार बल प्रयोग किया. इनमें 17 बार अश्रुगैस, 8 बार हवाई फायर, 4 बार लाठीचार्ज, 5 बार निषेधाज्ञा और एक बार कर्फ्यू के ज़रिए किसान आंदोलन का दमन किया गया. इन दिनों राज्य में गेहूं की सरकारी ख़रीद बड़े पैमाने पर की जा रही है. 150 से अधिक स्थानों पर गेहूं ख़रीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन कई केंद्रों पर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मंडी एवं सरकारी कर्मचारियों के शोषण-उत्पीड़न से परेशान किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कहीं-कहीं तो ख़रीद व्यवस्था का बहिष्कार भी करने लगे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आतंक के साए में जी रहा है कटनी

अरविन्द वर्मा

कटनी ज़िला इन दिनों विभिन्न आपराधिक वारदातों का केंद्र बनता जा रहा है. इस क्षेत्र में जुए, सट्टे और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों का खूब बोलबाला है. पुलिस की निष्क्रियता के वज़ह से यहां अवैध शस्त्रों का आवागमन और व्यापार भी आम है. पिछले दिनों राज्य के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के प्रवास के दौरान भी इन समस्याओं से निपटने की दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया.

मध्य प्रदेश का औद्योगिक ज़िला कटनी इन दिनों आपराधिक वारदातों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या में इस क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है. ज़िले के बहोरीबंद क्षेत्र में पिछले फरवरी माह में चंदाबाई नाम की एक दलित महिला को जिंदा जलाकर मार डालने की वारदात पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. इसके अलावा रीठी क्षेत्र में पुलिसवालों द्वारा रात के अंधेरे में घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने और बाद में गांववालों द्वारा पुलिस की पिटाई की वारदात भी जांच के अभाव में लंबित है. पिटे हुए पुलिसवालों ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की.

ज़िला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड में मां की उपस्थिति में बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पुलिसवाले की पिटाई की घटना भी वर्तमान में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में एक पूंजीपति के प्रभाव में आकर दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता की घटना की जांच भी अब तक नहीं हो पाई है. ऐसे शहर में जहां जुआ सट्टा, गांजा, स्मेक, अवैध क़ब्ज़े, अवैध शस्त्रों का परिवहन और अन्य सामाजिक अपराध बड़ी संख्या में हो रहे है. यहां पुलिस तंत्र का निष्क्रिय होना चिंता का विषय है.

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता पिछले दिनों कटनी प्रवास पर आए थे. स्थानीय पत्रकारों द्वारा बार-बार इन घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके. गुप्ता अपनी यात्रा के दौरान स्वजातीय बंधुओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खोए रहे. कटनी में क़ानून की स्थिति के बारे में बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के बारे में एक विस्तृत व्याख्यान दे डाला. मंत्री जी ने अपने प्रवास के दौरान विभागीय ज़िम्मेदारी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया. ज़िला पुलिस प्रशासन मंत्री जी की सेवा में इस तरह जुटा रहा कि अधिकारी और अर्दली के बीच भेद कर पाना मुश्किल था.

स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की प्रतियोगिता बनाए रखी. परिणामत: कटनी क्षेत्र की क़ानून-व्यवस्था पर चर्चा पूरी तरह अधूरी रह गई.

feedback@chauthiduniya.com

महंगाई केवल राजनीतिक मुद्दा है

महंगाई का शोर केवल एक राजनैतिक मुद्दा है. महंगाई को लेकर न तो राजनीतिक दल गंभीर हैं और न ही जनता में कोई ख़ास गुस्सा या बेचैनी है. मंहगाई के मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को वामपंथी दलों और कुछ अन्य दलों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया था. भोपाल में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल एस का कुछ हिस्सों में असर है, लेकिन कुल 13 पार्टियों के मोर्चे का बंद का आह्वान भोपाल में ज़्यादा सफल नहीं हो पाया. केवल कुछ इलाक़ों में वामपंथी दलों की ट्रेड यूनियनों की सक्रियता से बंद कहीं-कहीं सफल रहा. एक वामपंथी कार्यकर्त्ता बनवारी आजाद ने बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस से तो हमें इस बंद के लिए किसी प्रकार के सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर उम्मीद थी कि वह मुद्दा आधारित राजनीति के लिए जब सभी विरोधी दलों से सहयोग चाहती है, तो उसे महंगाई जैसे सबसे बड़े मुद्दे पर बंद के आह्वान को सफल बनाने में भी सहयोग देना चाहिए था, लेकिन बंद के दौरान भाजपा नेताओं और भाजपा समर्थक व्यापारियों की दुकानें सबसे पहले खुलीं और पूरे दिन खुली रहीं. इतना ही नहीं, कुछ भाजपा नेताओं ने तो छोटे दुकानदारों को कारोबार बंद न करने की सलाह देकर बंद को असफल बनाने में सहयोग दिया.

समाजवादी कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद यादव का कहना है कि लोकसभा में महंगाई को लेकर बजट पर कटमोशन लाने वाले भाजपा के नेता सड़क पर महंगाई के विरोध में दूसरों का सहयोग नहीं करना चाहते इससे साफ़ है कि भाजपा के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है.

कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय ने मंहगाई के मुद्दे को लेकर होने वाले आंदोलनों को स्टंट बताया और कहा कि वामपंथी दल भी राज्यों में सत्ता में है और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल एस भी राज्यों में सत्ता में रह चुकी है. इन दलों के नेताओं को भली प्रकार मालूम है कि महंगाई रोकने के लिए राज्य सरकार के क्या दायित्व और अधिकार हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने मुनाफाख़ोरी, जमाख़ोरी को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए.

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अब्दल मजीद ख़ान का आरोप है कि मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में दलहनों और गन्ने की फ़सल की पैदावार घटी है. राज्य में शक्कर उत्पादन भी हर साल घट रहा है. ऐसे में यदि दालों और शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए राज्य सरकार को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राज्य में अनाज दलहन और गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करना चाहिए. मजीद ख़ान ने कहा कि भाजपा व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी हैं इसलिए भाजपा जमाख़ोरों, मुनाफाख़ोरों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं करती है. मजीद ख़ान ने कहा कि यदि भोपाल के बाज़ार में लौकी, कद्दू और पुदीना के दाम बढ़ते हैं, तो इसके लिए यूपीए सरकार कैसे ज़िम्मेदार हो सकती है, जबकि ये सब्जियां भोपाल के आसपास ही पैदा होती हैं और मंडी में तथा खुदरा बाज़ार में बिचौलियों और दलालों के भारी मुनाफे के कारण इन सब्जियों के दाम बढ़ते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकारी आंकड़ों से खुलासा होता है कि कोयले और तेल की खपत बढ़ने के बावजूद उत्पादन दर में कमी आई है.

बीहड़ों में तब्दील होती उपजाऊ भूमि

विनय दीक्षित

कहने को तो भारत कृषि प्रधान देशों की श्रेणी में आता है, इसके बावजूद हम गेहूं से लेकर अन्य खाद्य पदार्थों का आयात करने पर मजबूर हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास अन्न पैदा करने के लिए उपजाऊ भूमि और अन्य साधनों की कमी है. यहां तो 800 एकड़ कृषि योग्य भूमि ही बीहड़ों में तब्दील होकर बर्बाद हो रही है.

मनुष्य धरती की संतान है, इसलिए मनुष्य सब कुछ पैदा कर सकता है, लेकिन धरती पैदा नहीं कर सकता है. दुनिया में, और खासकर हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 2020 तक 125 करोड़ हो जाएगी. ऐसे में धरती की कमी हमारे लिए एक समस्या बन सकती है. ऐसे में बर्बाद हो रही या उजाड़ हो रही बीहड़ भूमि को समतल बनाकर उसे मनुष्य के काम आने लायक रूप देना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के कच्छार में एल्यूवियल मिट्टी के कारण लाखों हेक्टेयर भूमि उबड़-खाबड़ होकर बीहड़ के रूप में व्यर्थ पड़ी हुई है. इसके साथ ही भूमि में कटाव के कारण हर साल हज़ारों एकड़ उपजाऊ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है. मध्य प्रदेश में 6.30 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ भूमि है, जिसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के उत्तरी अंचल में बसे ज़िला भिंड, मुरैना एवं श्योपुर में स्थित है. भिंड मुरैना एवं श्योपुर ज़िलों में ही हर वर्ष लगभग 800 हेक्टेयर भूमि बीहड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसकी अनुमानित क़ीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है. उत्तर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राजस्थान के लगे हुए ज़िले इटावा, उरई, जालौन, आगरा, धौलपुर, भरतपुर आदि का यह अंचल यहां डाकुओं के आतंक से जाना जाता है. वहीं दूसरी ओर प्रकृति के प्रकोप से यह अभिशाप बीहड़ बाहुल्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा है.

सामाजिक एवं सर्वोदय कार्यकर्ताओं के प्रयासों से इस क्षेत्र में डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण के कारण मुक्ति मिल जाने से एक नई आशा की किरण का उदय हुआ है. परंतु इस आशा की किरण का पूर्ण लाभ इस क्षेत्र की जनता को तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक सदियों से बने बीहड़ों को कृषि भूमि एवं वन भूमि में नहीं बदल दिया जाता, जिसकी अभी तक गंभीर उपेक्षा हुई है. चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर ज़िलों में चंबल, सिंध, क्वारी, बेसली, सीप, सोन, कूनों एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा अत्यंत उपजाऊ भूमि को बीहड़ों में परिवर्तित कर दिया गया है. संभाग के 16.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 3.10 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ों में रुपांतरित हो चुकी है जो कि संभाग के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत है, जिसकी क़ीमत खरबों रुपये हैं. यह भी अनुमानित है कि लगभग 800 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि प्रति वर्ष बीहड़ में बदलती जा रही है. यदि बीहड़ भूमि को बीहड़ बनने से नहीं रोका गया तो अगली शताब्दी तक भिंड, मुरैना, श्योपुर ज़िले पूरी तरह से बीहड़ में परिवर्तित हो जाएंगे एवं इस बीहड़ की सीमा ग्वालियर एवं दतिया ज़िलों को छूने लगेगी.

चंबल संभाग की अधिकांश भूमि एल्यूवियल होकर भी हल्के किस्म की है. इस भूमि में रेत,सिल्क, मिट्टी, कंकड़ मिला हुआ है. बरसात होने पर पानी पूरी तरह से भूमि के अंदर नहीं जाता, अपितु ढाल पर ही बहने लगता है. पहले छोटी नाली बनती है, धीरे-धीरे बड़ी नाली में, फिर गहरे नालों में और अंत में बीहड़ों का रूप लेती चली जाती है. भिंड, मुरैना, श्योपुर ज़िलों में अलग-अलग गहराई के बीहड़ हैं. 0 से 1.5 मीटर गहराई के 0.738 लाख हेक्टेयर, 1.5 से 5 मीटर के 1.265 लाख हेक्टेयर, 5 मीटर से 10 मीटर की गहराई के 0.615 लाख है एवं 10 मीटर से अधिक गहराई के 0.489 लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि अनुमानित है. पूर्व ग्वालियर स्टेट के बंदोबस्त के अनुसार मुरैना तहसील का बीहड़ का क्षेत्रफल तहसील के कुल क्षेत्रफल का 21 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1989 में यह बीहड़ क्षेत्र लगभग दो गुना होकर 42 प्रतिशत हो गया था. इसी प्रकार भिंड तहसील के कुल क्षेत्रफल का 49 प्रतिशत बीहड़ क्षेत्रफल है जो कि अब बीहड़ बनने की तीव्र रफ्तार एवं बीहड़ रोकने के गंभीर उपाय न होने से अब यह बीहड़ क्षेत्रफल लगभग तिगुना हो गया होगा.

50 गांवों का अस्तित्व ख़तरे में

चंबल, कछार में अब तक भूमि के कटाव से जो नुकसान हो चुका, उसे अनदेखा किया जाता रहा है, लेकिन आगे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है. जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के भूगर्भ शास्त्र विभाग द्वारा किए गए शोधकार्य से पता चला है कि चंबल घाटी में जिन 213 गांवों का अध्ययन किया गया, उनमें से 14 गांव तो उजड़ने की कगार पर हैं, क्योंकि बीहड़ इन गांवों से केवल 100 मीटर दूर रह गए हैं और ये बीहड़ कभी भी फैलकर इन गांवों को लील सकते हैं. इनके अलावा 23 गांवों में बीहड़ अभी 200 मीटर दूर हैं और 13 गांवों में 500 मीटर दूर बने बीहड़ इन गांवों को लीलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सेटेलाईट चित्रों से इन गांवों की तस्वीर आई है.

भूगर्भ अध्ययन शाला, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के विभाग प्रमुख प्रोफेसर एसएन महापात्रा का कहना है कि शोधकार्य से यह पता चला है कि चंबलघाटी में हो रहे मिट्टी के अपरदन की वज़ह से लगभग 50 गांवों पर बीहड़ में तब्दील होने का ख़तरा मंडरा रहा है. अब इस बात को लेकर शोध किया जा रहा है कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सके.

बीहड़ के नज़दीकी गांव खुशहाली और समृद्धि से कोसो दूर हैं. मिट्टी के लगातार कटाव से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है. कृषि योग्य भूमि लगातार बीहड़ों में बदलती जा रही है, ऐसे में इन गांवों के किसानों का जीवन काफ़ी कठिन और समस्याग्रस्त हो गया है. इस समस्या से चिंतित शोधकर्ता अब इस अध्ययन में जुटे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि घाटी का कटाव रुक जाए और हज़ारों घर बर्बाद होने से बच जाए. हालांकि शोधकर्ताओं को भरोसा है कि वे जल्दी ही किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, जिससे इन गांवों को बीहड़ बनकर उजड़ने से रोक लिया जाएगा. मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्गेनिक कार्बन, पोटेशियम, पीएच जिसमें हाईड्रोजन आयंस होते हैं. मृदा की अम्लीय एवं क्षारीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं. बारिश होने पर मृदा में मौजूद ये पोषक तत्व बह जाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सार-संक्षेप

दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है

छत्तीसगढ़ में बल्गी, सिंघाली, बांकी मोंगरा और रजगामार क्षेत्रों में 11 फरवरी से 16 अप्रैल के दौरान छह अलग-अलग दुर्घटनाएं हुई है. औद्योगिक क्षेत्र और खदानों में होने वाली इन दुर्घटनाओं में दो व्यक्तियों की जान गई है और छह अन्य घायल हुए है. साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों में सुरक्षा के आभाव के कारण और अधिकारियों की कार्य के प्रति उदासीनता के कारण आतंक का माहौल बना हुआ है. परंपरा के अनुसार होने वाली किसी भी दुर्घटना की लीपा-पोती जांच के नाम पर फाइल दबाकर कर दी जाती है. मुख्यालय के अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और संसाधनों की उपस्थिति कभी श्रमिकों के आतंक को समझ पाने में सफल नहीं होती है. हादसों की जांच के लिए आने वाले अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण निर्मित करने के लिए कोई सलाह प्रबंधन को देते है इसमें संदेह है.

मां-बाप को बेटे ने मिलाया

जबलपुर. तलाक के बाद अलग-अलग रह रहे मां बाप को एक करने में उनके ही बेटे ने भूमिका निभाई. माता-पिता ने खुशी-खुशी 15 वर्ष के सुमित की इच्छा को पूरा करने के लिए एकबार पुन: विवाह कर लिया. 1994 में गोरखपुर निवासी संजय देवधर का विवाह जलगांव निवासी सजली के साथ हुआ था. इन दोनों से कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, पर वर्ष 2002 में इन दोनों के मध्य आपसी विवाद के चलते तलाक हो गया. उस समय पुत्र सुमित की उम्र सात वर्ष थी. अदालत ने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी पिता को सौपी. आठ साल तक अलग रहने के बाद जब सुमित की उम्र 15 वर्ष की हुई, तो उसने अलग हुए मां-बाप को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे पुन: पति पत्नी के रूप में अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करें. सुमित की इच्छा का सम्मान करते हुए संजय और सजली ने पूरे रीति रिवाज के साथ पुन: विवाह कर लिया.

छात्रों के साथ अन्याय

विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित शासकीय माधव महाविद्यालय 19 वर्ष के इतिहास में कई बार चर्चा में रहा है. प्रोफेसर अग्रवाल की कथित हत्या समेत कई मामलों में इस महाविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा. इस महाविद्यालय में विधि समुदाय के छात्रों को प्रवेश संबंधी नियमों की पूरी जानकारी संशोधित प्रकार में उपलब्ध नहीं है. यही कारण है कि महाविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता के बाद भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता. संस्थान के विद्यार्थी विरेंद्र पटरिया के अनुसार एल.एल.बी. की परीक्षा 57 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बाद एल.एल.एम. में प्रवेश के लिए वे केवल इसलिए पीछे रह गए क्योंकि संस्थान की बोधिका में 60 प्रतिशत अंक एल.एल.एम. के लिए अनिवार्य लिखे गये थे जबकि अब नियम बदल गए है. एक अन्य आवेदक भंवर मालवीय के अनुसार यदि बोधिका में सही नियम अंकित होते, तो अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या सामान्य वर्ग के 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता था. छात्र नेता मोहम्मद अनवर के अनुसार महाविद्यालय का विधि विभाग एक राजनैतिक अखाड़ा है. यहां के प्रोफेसर उंची पहुंच वाले है, जिसके कारण परीक्षा परिणामों का प्रभाव उन पर कभी नही पड़ता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ताप बिजली घर : खपत ज़्यादा, बिजली उत्पादन कम

बिजली संकट झेल रहे मध्यप्रदेश में पिछले सात वर्षों में विद्युत उत्पादन दर में बारह प्रतिशत की कमी आई है. वर्ष 2002-03 से लेकर 2008-09 तक राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता 2772.5 से बढ़कर 2932.5 मेगावाट जरूर हो गई है, लेकिन कोयला और तेल की खपत बढ़ने से वास्तव में उत्पादन कम हो रहा है.

अधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थापित क्षमता के मुकाबले इतना कम उत्पादन चौकाने वाला है. इसकी वजह प्रदेश के ज्यादातर ताप बिजली घरों का बूढ़ा हो जाना और समय-समय पर रखरखाव नहीं होना माना जा रहा है. इसके अलावा घटिया कोयला भी इसका एक बड़ा कारण है.

सरकारी आंकड़ों से खुलासा होता है कि कोयले और तेल की खपत बढ़ने के बावजूद उत्पादन दर में कमी आई है. प्रदेश के ताप बिजली घरों में कोयले की खपत 2002-03 में एक करोड़ 15 लाख 865 मीट्रिक टन थी, जो 2009-10 में बढ़कर एक करोड़ 21 लाख 67 हज़ार 336 मीट्रिक टन हो गई है. कोयला खपत में 3 लाख 69 हज़ार 471 टन के इस इजाफे के बावजूद बिजली उत्पादन दर में 11.72 फीसदी की गिरावट ही आई है. इसी तरह ताप बिजली घरों में तेल की खपत 2002-03 में 41 हज़ार 842 किलो लीटर थी, जो 2009-10 में बढ़कर 57 हज़ार 441 किलो लीटर हो गई. तेल खपत में 15 हज़ार 599 किलो लीटर की इस बढ़ोतरी के बाद भी उत्पादन दर में करीब 12 प्रतिशत की कमी आ गई. इसका सीधा सा अर्थ है कि बूढ़े हो चुके ताप विद्युत संयंत्र कोयला और तेल ज्यादा खा रहे हैं और उत्पादन कम दे रहे हैं.

पूर्व ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति का कहना है कि ताप विद्युत संयंत्रों के रखरखाव और उनकी मरम्मत पर विद्युत उत्पादन कंपनियां कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि सरकार की ओर से उन पर लगातार उत्पादन करते रहने का दबाव बना हुआ है. इस कारण ज़्यादातर संयंत्र की उत्पादन क्षमता घटी है और अचानक जब-तब उनमें खराबी आ जाने से उत्पादन ठप्प हो जाता है. श्री प्रजापति ने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नए विद्युत संयंत्र लगाने में भी राज्य सरकार की कोई रूचि नहीं है. भारत सरकार के सहयोग से दो

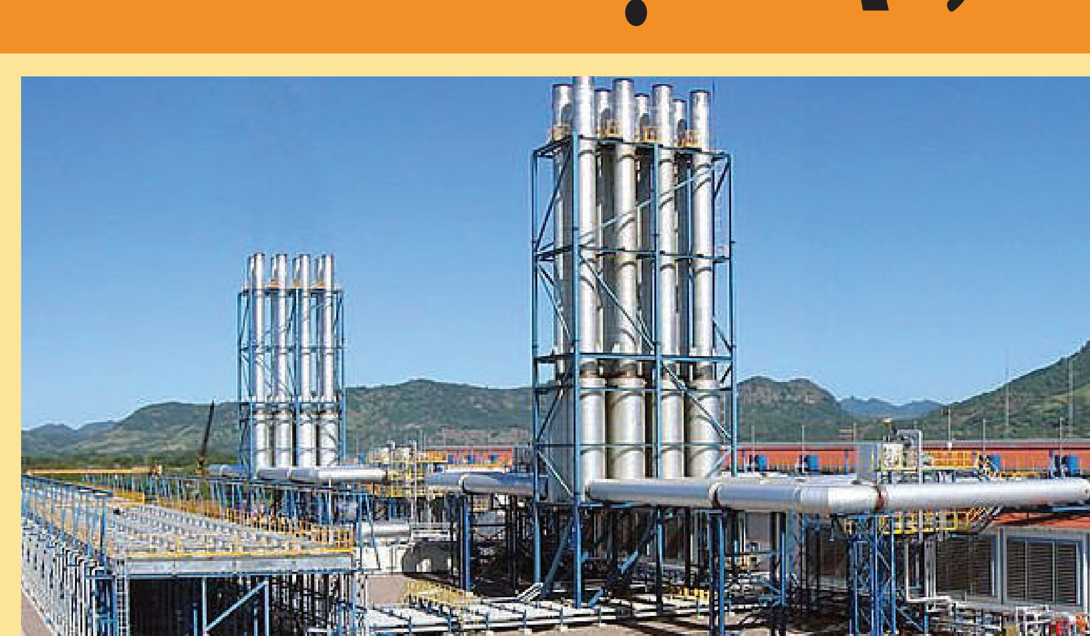

बड़ी बिजली परियोजनाएं मध्य प्रदेश में मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके लिए उचित भूमि का आवंटन नहीं कर पाई है. इस कारण इनका काम शुरू नहीं हो सका है. इसके अलावा निजी क्षेत्र की कई बिजली कंपनियां सरकार के साथ करारनामा करने के बाद राज्य के असहयोगी रवैये से दुखी होकर वापस चली गई हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष अर्थात् वर्ष 2010-11 में सरकार ने राज्य में किसी नई बिजली परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव राज्य की योजना में रखा ही नहीं है. इससे लगता है कि सरकार बिजली संकट के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है.

बिजली नहीं, लेकिन बिल आ रहे हैं

मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की अंधेरगर्दी का नमूना हरदा जिले के छैगांव माखन विकास खण्ड के ग्राम दुगवाड़ा में हाल ही देखने को मिला. लगभग 200 मकानों वाले इस आदिवासी जनसंख्या बहुल गांव में पिछले दस वर्षों से बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को प्रतिमाह बिजली वितरण कंपनियों से बिजली के बिल मिल रहे हैं और अब बिलों का भुगतान न करने के कारण वसूली के नोटिस भी दिए जा रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार दस वर्ष पहले कांग्रेस सरकार ने ग्रामीणों को एक बत्ती कनेक्शन योजना के तहत इस गांव में बिजली उपलब्ध कराई थी और आदिवासियों के बिजली बिल माफ कर दिए थे, लेकिन इसके बाद बिजली संकट के कारण गांव में पहले बिजली कटौती हुई, फिर बकाया शुल्क होने के नाम पर बिजली काट दी गई. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति के माध्यम से गांव में बिजली की आपूर्ति और बिजली शुल्क की वसूली होती है. सहकारी समिति ने बताया कि उनके गांव में दस साल से बिजली नहीं हैं और पूरा गांव अंधेरे में हैं फिर भी बिजली वितरण कंपनियां लोगों को हजारों रुपयों के विद्युत शुल्क बकाया के बिल थमा रही हैं. गांव वालों की इस व्यथागाथा को सुनने वाला कोई नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सौंदर्य की मिसाल भेड़ाघाट

आरती पटेल

रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए. ये पंक्तियां यदि प्रकृति की एक मनोहारी स्वप्न भूमि भेड़ाघाट के लिए कही जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. जबलपुर से भोपाल की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबलपुर नगर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट नाम का एक छोटा सा गांव है. संगमरमरी चट्टानों से सजा ये गांव नर्मदा नदी के तट पर बसा है. मानचित्र में इसकी स्थिति 23`8" उत्तर, 78`48" पूर्व, एमएसएल 408 मीटर है. पश्चिम मध्य रेल के इलाहाबाद तथा इटारसी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से स्टेशन भेड़ाघाट की दूरी 5 किलोमीटर है. आंखों को सुकून देकर मन मोह लेने वाले झरने, संगमरमरी चट्टानें और अपने आकर्षक दृश्य के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है.

नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे सिर्फ़ नदी न मानकर देवी मां अमृतस्य का नाम माना गया है. यह देश के उत्तर तथा दक्षिण को सांस्कृतिक रूप से विभाजित करती हुई उत्तरी अंचल के विंध्य पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक से निकलती है. अमरकंटक के उद्गम स्थल से 327 किलोमीटर के पश्चिम की ओर बहने के बाद नर्मदा भेड़ाघाट के संगमरमरी नगरी में प्रवेश करती है. यहां पर नदी अपनी चौड़ाई की तिहाई भाग तक सिकुड़ जाती है और नदी 32 मीटर की ऊंचाई वाली शक्तिशाली एवं अद्भुत संगमरमरी चट्टानों के मध्य से लगभग 3.22 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होकर निकलती है. यह भेड़ाघाट का ऐसा सौंदर्यमयी अद्भुत दृश्य है जो संभवत: विश्व में अद्वितीय है.

भारत वर्ष की सभी नदियों में यह एक ऐसी नदी है जो भेड़ाघाट में पत्थरों का सीना चीरकर प्रवाहित होने वाली प्रसिद्ध नदियों में अतुलनीय है. स्वच्छ पारदर्शी चौंधियाने वाला शांत जल, कल–कल, क्षल–छल करता तट का निर्माण करने वाली संगमरमरी चट्टानों के विस्तृत नीले गगन के नीचे आश्चर्यजनक चकाचौंध छंटा उत्पन्न करती है. सफ़ेद बर्फीली चोटियों के नीचे परिवर्तित होने वाला सूर्य प्रकाश अपने तेज़ को खोकर सोने की गेंद की तरह परिवर्तित हो जाता है. सबसे ख़ूबसूरत नज़ारा तो रात का होता है जब आसमान में फैले तारे और चांद, भेड़ाघाट के शांत जल में चमकते हैं. ऐसा लगता है मानो करोड़ों जुगनू जल में आईने की तरह अपनी ख़ूबसुरती निहार रहे हों और चांद पानी में ज़रा सी हलचल से नृत्य शुरू करने लगता हो. चांदनी रात में जब जल विस्तार दूर–दूर तक आसमान से जुड़ा दुधिया रंग की चादर के समान परिवर्तित हो जाता है तब यह किसी सपने की दुनिया से कम नहीं होता. ऐसे में खड़ी नुकीली रंग–बिरंगी चट्टानों के बीच नौकायन निश्चय ही अद्भुत आनंद देने वाला होता है. इस अनंत सौंदर्य से आंखें नहीं थकतीं और कान निर्जन एकांत में पानी की लगातार होने वाली कल–कल, छल–छल की ध्वनि सुनते नहीं अघाते. इस पावन और ताकतवर नदी के एक संकरे स्थान पर जहां गहराई वाली विपरीत तटों की संगमरमरी चट्टानें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, उसे यहां रहने वाले लोगों ने बंदर कूदनी नाम दिया है.

यात्री विश्रामगृह के निकट विशाल जल राशि की गहराई 51.51 मीटर है. यहां की दरार पहले सबसे शक्तिशाली झरने का निर्माण करती है. विशाल जल राशि का पत्थरों से टकराकर तेज रफ्तार से नीचे गिरना और रफ्तार इतनी की पानी का 40 प्रतिशत भाग धुएं की तरह ऊपर वातावरण में फैल जाता है. इस तरह का परिवेश इतना अद्भुत और इंद्रधनुषीय होता है, जिसे देख पर्यटकों के अल्फाज़ों में धुंआधार की तारीफ़ ही हो सकती है. नर्मदा पर भेड़ाघाट में वाण–कुंड तथा रूद्र कुंड अन्य चित्रण योग्य स्थान है जो धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित है.

आजकल भेड़ाघाट विकास प्राधिकरण के प्रयासों से एक रोप वे का निर्माण किया गया है. सच मानों इसकी ट्राली में धुंआधार का अतुलनीय सौंदर्य जब निगाहों के एकदम सामने आता है तब मानों सांसे थम सी जाती है. सतरंगी पानी के फुहारों से सराबोर, धुंआधार के दूसरी ओर नया भेड़ाघाट है. भेड़ाघाट के नामकरण से संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जो उसके स्थलों की पवित्रता को प्रमाणित करती है. इनमें से एक कथा कुछ इस प्रकार है : पौराणिक भृगु ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा जो नर्मदा नदी के तट पर बने आधुनिक विश्राम गृह क्रमांक–2 के निकट रहते थे. एक अन्य सुझाव था कि भेड़ाघाट की उत्पत्ति भेड़ा शब्द से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना. यह शब्द दो नदियों के मिलने की ओर संकेत करता है, अर्थात नर्मदा नदी एवं पावनगंगा का संगम स्थल जो यहां पर है. कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह प्राचीन भैरवीघाट का परिवर्तित व आधुनिक नाम है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि यह स्थान शक्ति पूजन का प्रसिद्ध केंद्र था. पुरातात्विक अवशेषों से प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल से ही यह स्थान शक्ति पूजा का केंद्र था. आज भी चौसठ जोगनी के रूप में बहुसंख्यक गौंडवाना कालीन देवी प्रतिमाएं शोध का विषय है. बंदर कूदनी, पंचवटी घाट, सरस्वती घाट तथा अन्य स्थलों से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं, जो संगमरमरी चट्टानों के सौंदर्य को दिखाते नौका विहार के समय चालक द्वारा पर्यटकों को सुनाया जाता है. यह पर्यटकों को जानकारी एवं मनोरंजन देने में मदद करता है.

विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य का प्रतीक मां नर्मदा के अद्भुत दर्शन का केंद्र होने के बावज़ूद भेड़ाघाट इतिहास के विभिन्न कालों से ही उपेक्षा का शिकार होता रहा है. यह प्राचीन काल त्रिपुरी और मध्यकाल के गढ़ा, मराठा और ब्रिटिश नियंत्रण के कार्यकाल के दौरान जबलपुर क्षेत्र में जोड़ा जाता था. यहां तक की संबंधित कालों में भेड़ाघाट का इतिहास क्षेत्रीय इतिहास में समाहित हो जाता है. ये तथ्य भेड़ाघाट से प्राप्त होने वाले अनेक पुराकृतियों से प्रमाणित होता है. इसी वज़ह से भेड़ाघाट को अपनी पहचान बनाने में इतना लंबे समय का सफ़र तय करना पड़ा.

प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ राज्य सरकार ने भेड़ाघाट को विश्व हेरिटेज का दर्ज़ा दिलाने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है. कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि ये जबलपुर वासियों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि भेड़ाघाट भी विश्व पर्यटन के नक्शे में नज़र आएगा और इस उपलब्धि से रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे. यह शहर के ज़मीनी स्तर के विकास कार्य के लिए कारगर क़दम होगा.

शहर के अनेकानेक पर्यटन स्थलों में भेड़ाघाट प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन इस ओर उदासीनता की वज़ह से इसकी बेहतर मार्केटिंग नहीं हो पाती. नतीज़ा विदेशी पर्यटक इससे आकर्षित नहीं हो पाते, इसीलिए इसे विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए यूनेस्को को भेजे गए प्रस्ताव के अलावा वर्ल्ड फोरम स्तर पर भी बेहतर मार्केटिंग करने की योजना बनाई जा रही है. अब वह दिन दूर नहीं है जब संगमरमरी वादियों के बीच से बहती नर्मदा के लिए विश्व प्रसिद्ध और प्राकृतिक मनोहारी छंटा से आच्छादित भेड़ाघाट न सिर्फ़ जबलपुर बल्कि विश्व का प्रमुख धरोहर बन जाएगा, और संगीत लहरी बिखेरता हुआ यह जलप्रपात विश्व में अपनी पहचान बनाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

बढ़ रही हैं दुष्कर्म की घटनाएं

सरकार बालिकाओं को संरक्षण देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों पर अमल कर रही है, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि इस राज्य में बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं. प्रदेश में मासूम बच्चियों के उत्पीड़न की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं. महज़ 100 दिन में तीस नाबालिग लड़कियां दुष्कर्म की शिकार हुई हैं. इससे साफ़ है कि हर तीसरे दिन एक लड़की दरिंदों की शिकार हो रही हैं. ये तो सिर्फ़ पुलिस थानों में दर्ज़ प्रकरणों का आंकड़ा है. ऐसे कई और मामले होंगे जो सामाजिक लोकलाज के कारण सामने ही नहीं आ पाते हैं.

प्रदेश में 16 अक्टूबर 09 से लेकर 31 जनवरी 10 तक बलात्कार के कुल 72 मामले पुलिस थाने में दर्ज़ किए गए. इनमें 30 मामले नाबलिगों के साथ दुराचार के हैं. इनमें सबसे ज़्यादा शिकार दलित और अन्य पिछड़े वर्ग की लड़कियां हुई हैं. ज़ाहिर है, ये वर्ग समाज की कमज़ोर कड़ी हैं और इन वर्गों की नाबालिग बच्चियों को आसानी से शिकार बनाया जा रहा है.

> मानसिक विकृति के द्योतक गांधी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आरएन साहू का कहना है कि इन दिनों मानसिक रोगों का अनुपात बढ़ा है. डॉ. साहू का मानना है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले मानसिक रूप से विकृत होते हैं और उनका दिमाग असामान्य होता है.

आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो 100 दिनों में अनुसूचित जाति की 11, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10, अनुसूचित जनजाति की 8 और सामान्य वर्ग की 1 नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले दर्ज़ किए गए हैं. ख़ास बात यह है कि दुराचार के ये मामले सबसे ज़्यादा विकसित कहे जाने वाले क्षेत्रों में हैं जबकि पिछड़े कहे जाने वाले मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, अलीराजपुर, झाबुआ और श्योपुर इस लिहाज़ से सुरक्षित व बेदाग़ है.

मानसिक विकृति के द्योतक गांधी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आरएन साहू का कहना है कि इन दिनों मानसिक रोगों का अनुपात बढ़ा है. डॉ. साहू का मानना है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं और उनका दिमाग असामान्य होता है. बताया जाता है कि यह एक तरह से सेक्सुअल डेविएशन की स्थिति है. मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कृष्णकांता तोमर का कहना है कि इन हालातों के पीछे सामाजिक मूल्यों का पतन सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है. उनका कहना है कि आज सामाजिक व्यवस्था में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनमें सुधार करना पड़ेगा. वैसे महिला आयोग हर मामले को गंभीरता से लेता है. आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि आयोग के पास नाबालिग के साथ दुष्कर्म की जो भी शिकायतें आती हैं, उनमें पीड़िता को न्याय ज़रूर दिलाया जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्रमिकों के लिए केवल तीन प्रतिशत कल्याण राशि उपलब्ध

शिवा कुमार

श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा है. जो राशि इनके कल्याण के लिए आती है वह किसी और की जेब में जा रही है और यह सब इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने उसके लिए ज़रूरी राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया है. छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा स्वयं केंद्र की सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं केवल औपचारिकता बनाकर रखना चाहती है. वस्तुत: छत्तीसगढ़ अब उद्योगपतियों की भूमि हो चुका है. यहां श्रमिकों के कल्याण की संभावनाए केवल काग़ज़ों पर है. छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास बताता है कि पिछले 9 सालों के दौरान सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उद्योगपतियों और व्यापारियों को मिला है. मज़दूरों और ग़रीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाएं सही क्रियान्वयन की प्रतीक्षा में अटकी पड़ी है. राज्य सरकार श्रमिकों के लिए एक सलाहकार समिति 9 वर्षों के दौरान नहीं बना पाई. वर्तमान में केंद्र शासन द्वारा दी जाने वाली राशि में से एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के खाते में चला जाता है. राज्य सरकार को कुछ तीन प्रतिशत राशि ही मिल पाती है. सलाहकार समिति के लिए बार–बार दबाव बनाने के कारण राज्य सरकार ने श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति ज़रूर कर दी है. मज़दूरों एवं श्रमिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीड़ी वर्कर वेलफेयर फंड 1976, लाईमस्टोन व डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1972 व आयरन और माइंस, मैगनीज़ और माइंस व क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976 जैसे क़ानूनों का लाभ मज़दूरों व श्रमिकों को मिल सके, इसके लिए स्टेट एडवायजरी कमेटी का गठन किया जाता है पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से वही कमेटी कार्य करती आ रही थी जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कार्यरत थी. इस कमेटी का कार्यकाल क्रमश: 29 नवंबर 2009 व 18 नवंबर 2009 में ही ख़त्म हो चुका है, आयरन अयस्क एक्ट के तहत तो राज्य बनने के बाद से ही प्राप्त राशि के सदुपयोग के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में केंद्रीय अधिकारियों द्वारा 15 जुलाई 2009 व 22 सितंबर 2009 को राज्य के श्रम सचिव व श्रम आयकुत को पत्र लिखकर दो बार सूचित किया गया. इस कमेटी का गठन न हो पाने के कारण उक्त क़ानूनों के तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए माइंस व फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कोई राशि आवंटित ही नहीं की जा सकी. श्रम क़ानूनों के अनुसार बीड़ी मज़दूरों के लिए प्राप्त राज्य के प्रति हज़ार रुपये में से 05 हज़ार रुपये कल्याण राशि के तौर पर कल्याण फंड में एकत्रित की जाती है. बीड़ी मज़दूरों के वेलफेयर फंड में छत्तीसगढ़ से 01 करोड़ 97 लाख व मध्य प्रदेश से लगभग 11 करोड़ एकत्रित हुए थे, जबकि लाईमस्टोन व डोलोमाईट माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1972 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में क़रीब 02 करोड़ व मध्य प्रदेश से लगभग पौने तीन करोड़ रुपये एकत्रित हुए. इसी तरह आयरन खनिज माइंस, मैगनीज़ अयस्क माइंस व क्रोम अयस्क माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976 क तहत छत्तीसगढ़ में पौने तीन करोड़ व मध्य प्रदेश से लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये एकत्रित किए गए, लाईमस्टोन व डोलोमाइट से प्राप्त राजस्व के प्रति 1000 हज़ार रुपये में से 01 रुपये , आयरन से भी प्रति 1000 रुपये में से 01 रुपये , क्रोम खनिज से प्रति 1000 रुपये में से 06 रुपये , मैंगनीज़ अयस्क से प्रति 1000 रुपये में से 04 रुपये कल्याण कोष में एकत्रित किया गया था. इस कल्याण निधि का उपयोग राज्य की श्रम कल्याण सलाहकार समिति की अनुशंसा पर श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य श्रम विभाग में श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष पद पर अरुण चौबे की नियुक्ति के बाद से श्रमिकों की स्थितियां दिन प्रतिदिन ख़राब होती गई. श्रमिक संगठनों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा. इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है.

feedback@chauthiduniya.com